खण्ड-06 सत्र -04 (भाग-03)
अंक-39

शुक्रवार

9 सितम्बर, 2016
18 भाद्रपद, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

तीसरा सत्र

अधिकृत विवरण
(खण्ड-04 (भाग-03) में अंक 39 सम्मिलित है।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव
PRASANNA KUMAR SURYADEVARA
Secretary

एम.एस. रावत
उप-सचिव (सम्पादन)
M.S. RAWAT
Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-04 भाग (3) शुक्रवार, 09 सितम्बर, 2016/18 भाद्रपद, 1938 (शक) अंक-39

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3-6
3.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	6-30
4.	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	30-31
5.	ध्यानाकर्षण (नियम-54) (मुख्यमंत्री की सुरक्षा कथित रूप से लीक होने से निर्वाचित मुख्यमंत्री की सुरक्षा हनन के प्रति श्री नितिन त्यागी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया)	31-56
6.	अनुदान की पूरक मांगों पर विचार एवं पारण	57-60
7.	(1) विनियोजन (सं. 3) विधेयक 2016 का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	60-61
8.	माननीय अध्यक्ष की टिप्पणी	62-112

क्रसं. **विषय** **पृष्ठ सं.**

9. अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) 112-192

(1) जनादेश को विफल कराने के उद्देश्य से, विधिवत रूप से निर्वाचित विधाान सभा को निष्क्रिय बनाने के कथित असंवैधाानिक प्रयासों के संबंध में।

(2) नेकनीयत वाले अधिकारियों को आतंकित तथा हतोत्साहित करने के इरादे से मनमाने तबादलों तथा अन्य विभिन्न कदमों से दिल्ली के शासन को पटरी से उतारने के कथित प्रयास के संबंधा में।

(3) दिल्ली सरकार के एक पूर्व मंत्री से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो लीक होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में

(नियम - 283 के अनुसार माननीय अधयक्ष महोदय के आदेश दिनांक 12.02.2026 के अनुपालन में माननीय मंत्री श्री कपिल मिश्रा के वकतव्य सहित विधाानसभा की कार्यवाही का अंश पृ ष्ठ संख्या 170-181 को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया।)

(4) वक्फ बोर्ड कार्यालय पर ए. सी. बी. रेड के मामले पर

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-04 भाग (3) शुक्रवार, 09 सितम्बर, 2016/18 भाद्रपद, 1938 (शक) अंक-39

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

1 श्री शरद कुमार
2 श्री संजीव झा
3 श्री पंकज पुष्कर
4 श्री पवन कुमार शर्मा
5 श्री अजेश यादव
6 श्री वेद प्रकाश
7 श्री सुखवीर सिंह दलाल
8 श्री ऋतुराज गोविंद
9 श्री रघुविन्द्र शौकीन
10 श्रीमती बंदना कुमारी
11 श्री जितेंद्र सिंह तोमर
12 श्री सोमदत्त
13 सुश्री अलका लाम्बा
14 श्री आसिम अहमद खान
15 श्री विशेष रवि
16 श्री हजारी लाल चौहान
17 श्री शिव चरण गोयल
18 श्री गिरीश सोनी
19 श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
20 श्री राजेश ऋषि

21 श्री महेंद्र यादव
22 श्री नरेश बाल्यान
23 श्री कैलाश गहलोत
24 सुश्री भावना गौड़
25 श्री सुरेंद्र सिंह
26 श्री विजेंद्र गर्ग
27 श्री प्रवीण कुमार
28 श्री मदन लाल
29 श्री सोमनाथ भारती
30 श्रीमती प्रमिला टोकस
31 श्री नरेश यादव
32 श्री प्रकाश
33 श्री अजय दत्त
34 श्री दिनेश मोहनिया
35 श्री सौरभ भारद्वाज
36 सरदार अवतार सिंह कालकाजी
37 श्री सही राम
38 श्री नारायण दत्त शर्मा
39 श्री राजू धिंगान
40 श्री मनोज कुमार
41 श्री नितिन त्यागी
42 श्री एस. के. बग्गा
43 श्री अनिल कुमार बाजपेयी
44 श्री राजेंद्र पाल गौतम
45 श्रीमती सरिता सिंह
46 मो. इशराक
47 श्री श्रीदत्त शर्मा
48 चौ. फतेह सिंह
49 श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-04 भाग (3) शुक्रवार, 09 सितम्बर, 2016/18 भाद्रपद, 1938 (शक) अंक-39

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

(राष्ट्रीय गीत - वंदेमातरम)

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : सभी माननय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन, स्वागत।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है....

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। एक सैकेंड मेरी बात सुनें। विजेन्द्र जी, आपका हर सैशन में, इस समय को बर्बाद करना...ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बैठिए, अब बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप हर बार जब भी सैशन शुरू होता है आप हर वक्त....मेरी प्रार्थना है कि आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप इधर बात करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ये कोई तरीका है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप बात कैसे कर रहे हैं? बंद कर दीजिए माईक। न क्षमा मांग रहे हो, कुछ कर रहे हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए विजेन्द्र जी। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं बैठिए। ये तरीका ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है क्या?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, इधर बात कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए आप। बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र जी, बैठिए प्लीज। मैंने सुन लिया। पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है क्या? विदेश का हिस्सा नहीं है!

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रार्थना कर रहा हूं विजेन्द्र जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप मुझ से बात कीजिए। उधर बात मत करिए। सोमनाथ जी बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : और कोई विषय नहीं है आपके पास? ये राजनीतिक भाषा के लिए...कोई दिल्ली की जनता के हित के विषय में कोई और तथ्य नहीं है? चलिए, बैठिए-बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं बैठ जाइए। नहीं, ऐसे नहीं। आप बैठ जाइए पहले। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आपने आपत्ति दर्ज कर दी। हो गया। अब बैठ जाइए। नहीं, आपने अपनी बात रख दी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए मेरी बात सुनिए। दो मिनट झा साहब। आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने उनका भी माईक अलाउ नहीं किया है। मैं आपको समय दूंगा तो माईक अलाउ...मैं जब समय दूंगा तब आपका माईक अलाउ होगा। मैं किसी का माईक अलाउ नहीं कर रहा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात बोल दी ना। दिल्ली में रोज डाके डल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : दिल्ली को किस के हवाले छोड़कर गए हैं?

अध्यक्ष महोदय : बैठिए-बैठिए।

...(व्यवधान)

विशेष उल्लेख (नियम-280)

अध्यक्ष महोदय : 280 विशेष उल्लेख में श्रीमती प्रमिला टोकस।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई विजेन्द्र जी, मैं ऐसे एलॉउ नहीं करूंगा। नहीं, मैं इस ढंग की बातों के लिए मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। नहीं...ये कोई मामला नहीं

है। कोई मामला होता तो मैं करवाता। भई विजेन्द्र जी, आप देखिए आपकी आदत कुछ ऐसी बन गई है जो विषय ठीक नहीं होता जिसको मालूम है, पॉलिटिकल विषय पर उठाना है, आप उस विषय को हमेशा उठाते हैं और हां, पॉलिटिकल विषय है। आप बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए। मेरी भी प्रार्थना है बैठ जाइए....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। नहीं-नहीं विजेन्द्र जी ये विषय नहीं है। प्लीज बैठिए आप। आप बैठिए प्लीज।...तो क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री जा सकते हैं। कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी जा सकता है बाहर।...तो क्या दिक्कत है इसमें? उन्होंने कब कहा? आप बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाइए। मैं आग्रह करूंगा कि विजेन्द्र जी, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी...विजेन्द्र जी, देखिए एक तो बिना किसी...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उत्तर नहीं दे रहा इस चीज का। मैं अगर वहां बैठा होता तो उत्तर दे देता और बहुत अच्छा उत्तर देता...विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, एक सेकेंड अमानतुल्लाह जी...त्यागी जी, एक सेकेंड, रूकिए त्यागी जी, प्लीज, सोमनाथ जी, झा साहब, बैठिए, बैठिए

प्लीज, बैठिए सरिता जी, बंदना जी। मैं बैठा रहा हूं इनको। बैठिए जरा। मैं सबको बैठा रहा हूं, बैठिए। मैं नियम भी बता रहा हूं। अभी दो मिनट रूक जाइए। बैठिए जरा त्यागी जी, सरिता जी, दो मिनट बैठ जाइए प्लीज, प्रवीण जी, बैठ जाइए... अभी बैठ जायेंगे। विजेन्द्र जी, आप बैठ जाइए, दो मिनट बैठ जाइए, दो मिनट बैठ जाइए। ये समय जो सदन का बर्बाद होता है तो मुझे पीड़ा होती है बहुत।...उप मुख्यमंत्री हैं, क्या दिक्कत है उनको? कोई बात नहीं। ना, मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा। अब आप बैठिए जरा। विजेन्द्र जी, आप बार-बार ये बोलते रहेंगे क्या?... विजेन्द्र जी, तोमर जी, बैठिए-बैठिए। त्यागी जी, दो मिनट तो बैठ जाइए... आप अच्छा बैठिए प्लीहज, अमानतुल्लाह जी एक सेकेंड तो रूक जाओ प्लीज... दो मिनट रूक जाइए, राखी जी। विजेन्द्र जी, आपने विषय को दूसरी तरफ ले लिया। आपका जो मेरे पास राइटिंग में है, इस विषय पर कुछ नहीं था, एक सेकेंड रूक जाइए जरा। वो कैसे आएगा? आप सुनते हैं नहीं। आपने जब ये विषय भी दिया है उनको। ये तो तीन घंटे पहले लगा सकते थे आप। अच्छा आप दो मिनट रूक जाइए जरा। जहां तक वेल्ले की बात है, जो मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि हम वेल्ले नहीं हैं। आप बोले होंगे। एक सेकेंड मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आपको ये बड़ी दिक्कत है। बहुत परेशानी है। प्रवीण जी, दो मिनट रूक जाइए, आप कपिल जी चलिए। त्यागी जी, विजेन्द्र जी, दो मिनट बेठ जाइए। विजेन्द्र जी, दो मिनट बैठ जाइए। भाई साहब बैठिए। मेरी प्रार्थना है विजेन्द्र जी से बैठिए। आपका नोटिस आया है, उसकी रूलिंग सुन लीजिए। नहीं, बैठना है? चलिए जाइए। प्रमिला टोकस जी।

श्रीमती प्रमिला टोकस : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, मेरे विधायक निधि से एम. सी. डी. काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही

है, मुझे हाउस में इसका जवाब चाहिए। इतने महीने हो चुके हैं हमें एम. सी. डी. को पैसे दिए हुए लेकिन अभी वो काम शुरू नहीं किया गया है और कही पर एक-आधी जगह पर किया हुआ है तो कुछ जैसे नाले काम था, वो काम शुरू कर दिया था और उन्होंने पूरा नहीं किया। कुछ ऐसे कार्य थे कि शायद उनका मकसद था कि एम.एल.ए. बदनाम हो। इस वजह से वो काम हमारे रोके हुए हैं और विधायक निधि से जल बोर्ड ने सीवर लाइन नहीं डाली। क्यों नहीं डाली है, इसका भी मंत्री साहब जवाब दे सकते हैं। विधायक निधि से कालोनियों के मेन गेट का निर्माण कार्य हम क्यों नहीं कर सकते जब और पार्षद कर सकते हैं और एमपी भी कर सकते हैं तो हम एम. एल. ए. क्यों नहीं कर सकते? विधायक निधि से एलईडी लाइट और पोल्स हम एम. एल. ए. नहीं लगा सकते, पार्षद लगा सकते हैं, ऐसा क्यों? विधायक निधि से एम. सी. डी. को एस्टीमेट के लिए कहते हैं तो एम. सी. डी. विभाग के अफसर कार्य के लिए एस्टीमेट नहीं बनाते। एम. सी. डी. के अधिकारी बिल्डिंग मेंटिनेंस, प्रोजेक्ट व अन्य विभाग के अधिकारी मीटिंग में नहीं आते हैं व एम. सी. डी. कमिश्नर मीटिंग के लिए समय ही नहीं देते।

अध्यक्ष जी, आपके माधयम से मैं सदन का धयान दिलाना चाहती हूं कि एम. सी. डी. के कमिश्नर भी हमारे कहने से मीटिंग में नहीं आते और न ही हमें समय देते हैं कि हम ही उनके पास चले जाएं तो इस पर सख्त स सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारे जोज नता के कार्य हैं, वो पूरा कर सकें और एम. एल. ए. फंड से हमारे जो एम. सी. डी. काम नहीं किये, उसको जल्दी से जल्दी से पूरा कराने का कष्ट करें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सौरभ भारद्वाज।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने आज बोलने का मौका दिया। जैसा कि प्रमिला जी बता रही थीं, ज्यादातर काम जो विधायक अपने एरिया के अंदर करा सकते हैं या तो वो जल बोर्ड से होते हैं या वो एम. सी.डी. से होते हैं। यहां तक कि जो लाईटस हैं, एल.ई.डी. लाईटस हैं, उनको लगाने के लिए भी हालांकि पेसा बी. एस.ई.एस. को दिया जा रहा है मगर उसमें भी एम.एल.ए. से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है ताकि वो लाईटस विधायकों के एरिया में लगायी जा सकें। मेरे अपने एरिया के अंदर 2015-16 में करीब तीन करोड़ रूपये का जो काम है, उसके लिए साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन को सब पैसा दिया गया है। झूले लगाने के लिए पैसा दिया गया है। ओपन जिम लगाने के लिए पैसा दिया गया है। कई कार्यो के लिए तो पैसा दिया गया है। ओपन जिम लगाने के लिए पैसा दिया गया है। कई कार्यों के लिए तो पैसा दिये हुए एक साल से ज्यादा हो गया है और उन कामों के लिए जो पैसा था, वो सारा का सारा डूडा के थ्रू एम. सी. डी. को दिया जा चुका है। जहां तक सिविल कामों की बात है, सड़कों की बात है, नालों की बात है या खड़ंजों की बात है। उन सब के लिये भी जहां पर वर्क आर्डर हो गये हैं, चार महीने पहले वर्क आर्डर हो गये हैं, वहां पर भी काम शुरू नहीं किये गये हैं। इस बार जब सदन चला तो मैंने सदन में उस अपना एक प्रश्न लगाया प्रश्न नं. 19 जिसका 23.08.16 कोज वाब आया और वो प्रश्न एम.सी.डी. से इसी के बारे में था। हमने अपने यू.डी. डिपार्टमेंट से ये प्रश्न रखा था कि एम.सी.डी. के अफसर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी सरकार इसके लिए क्या कर रही है? क्या हमने उन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है या नहीं की है या इसके लिए हमारी सरकार हाईकोर्ट में रिट पटीशन में जा सकती है? क्योंकि

कोई भी सरकारी अफसर अगर अपना काम नहीं कर रहा है, वह अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहा है तो इस पर हम दिल्ली हाईकोर्ट में रिट में भी जा सकते हैं या स्पीकर साहब की अगर अनुमति हो और हाउस की अगर राय बने तो मुझे लगता है कि इस पर हाउस की एक कमेटी भी गठित की जा सकती है। जो स्पेसिफिकली इस चीज को देखे कि एम.एल.ए. फंड के जो कार्य हैं, जो तीनों एम.सी.डी. को अलग-अलग जगह दिये गये हैं, उन कार्यो को क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि बड़ी साफ सी बात है कि उसके पैसे जा चुके हैं। कई जगह टैंडर हो चुके हैं। वर्क आर्डर हो चुके हैं। तो भी काम शुरू नहीं हुआ। कई जगह जानबूझ के... ऐसा कभी नहीं होता था जैसे कि मैंने अपने क्षेत्र में बहुत सारा पैसा झूलों के लिए या ओपन जिम के लिए दिया तो जानबूझ के छोटे-छोटे एस्टीमेटस को क्लब करके एक करोड़ से ज्यादा का बनाया गया। जो अलग-अलग एस्टीमेट थे, उनको क्लब कर दिया गया और उसके ऊपर ये कंडीशन भी लगा दी गयी कि जी, अब तो ये हाउस में पास होगा, तब ये आयेगा और बहुत ही दिनों बाद ये हाउस में लगाया और हाउस में पास किया गया। तो कुल मिलाके अलग-अलग ब्यूरोक्रेटिक तरीकों से इस काम को रोका जा रहा है। जो एस.एम.सी.डी. के कमिश्नर हैं, जैसे कि प्रमिला जी ने बताया की वो भी गोलमाल जवाब देते हैं। मिलने का समय भी अब तो उन्होंने देना बंद कर रखा है।

अध्यक्ष महोदय : करिए, कन्क्लूड करिए। हो गया है ये।

श्री सौरभ भारद्वाज : तो स्पीकर महोदय, मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी अनुमति हो तो असेम्बली की एक कमेटी जरूर बनायी जाये जिसमें एम.डी.एम.सी. द्वारा जो एम.एल.ए. लैड फंड के काम नहीं हो

रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहे हैं और अफसरों को बुलाया जाये और पता किया जाये, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सुश्री अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आपने नियम 280 के तहत मुझे मेरी क्षेत्रीय समस्या उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, ये समस्या मैं इसलिए उठा रही हूं कि क्योंकि मुझे एक परिवार मिलता है, दफ्तर में आकर मिला और उन्होंने मेरे सामने एक समस्या रखी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के एक सदस्य की मौत सिर्फ इसलिए हो गयी क्योंकि जिस एम्बुलेंस में वो था, वो एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गयी। समय से सेंट स्टीफन हॉस्पिटल अगर पहुंच जाती तो शायद वो मरीज उनके परिवार का बच जाता। तो उन्होंने मुझे बहुत करूणा के साथ अपनी इस समस्या को लिखा। मैंने तुरंत जाकर के सेंट स्टीफन हास्पिटल जो तीस हजारी के पास है, वहां के एम.एस. एवं डाइरेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने मुझे लेटर दिखाया कि ट्रैफिक पुलिस, डी.सी.पी. को हमने लगातार लेटर लिखे हैं। नगर निगम को लिखे हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मुझे ये भी जानकारी दी कि अलका जी, ये एक ही मैटर नहीं है, ऐसे बहुत से मैटर है क्योंकि आप जब रानी झांसी रोड से आते हैं जो नगर निगम का फ्लाईओवर है, पिछले दस सालों से आज भी निर्माण पूरा होने के इंतजार में है, वो निर्माण पूरा नहीं हो रहा है। उसमें है क्या अध्यक्ष जी, अगर आप आजादपुर साइड से आयेंगे तो आपको तीस हजारी कोर्ट की लाल बत्ती तक आ के यूटर्न करने के बाद फिर सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करनी पड़ती है। एंट्री इसलिए नहीं हो पाती है कि यू-टर्न करने के बाद जो एंट्री गेट है, वहां ई-रिक्शा,

रिक्शा, ऑटो और दुकानदार जितने रेहड़ी-पटरी वाले हैं, उन्होंने पूरी तरह से उस गेट पर कब्जा किया हुआ है। अध्यक्ष जी, दिल्ली नगर निगम को लगातार लिख के देने के बावजूद भी वहां से रिक्शा, ई-रिक्शा, रेहड़ी-पटरी का जो भी अवैध कब्जा है, उसे नहीं हटाया जा रहा है। डी.सी.पी. को लेकर मैंने पूरे इलाके का दौरा भी किया है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि अगर आप आजादपुर की तरफ से रानी झांसी फ्लाईओवर का जो निर्माण है, वहां से आते हैं। वहां से आते हुए एक लाल बत्ती हुआ करती थी जो बिल्कुल सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के एंट्री गेट से कोई भी एम्बुलेन्स आदि सीधा इंटर कर जाती थीं। अब तो लाल बत्ती को वहां से बंद करके उस पूरे रास्ते को ही बंद कर दिया गया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ट्रैफिक पुलिस, डी.सी.पी. के साथ मैंने खुद कम-से-कम एक दिन रहकर के वहां पर मुआयना किया है और वो लाल बत्ती वहां पर होने से ये राहत मिलेगी कि आपको सेंट स्टीफन हॉस्पिटल, जो आपका तीस हजारी कोर्ट है, वहां से यू टर्न नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि नगर निगम को... इस तरह की घटनायें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि वहां पर अवैध कब्जा है। ई-रिक्शा, रिक्शा से पूरा इन्क्रोचमैंट है जिसकी वजह से वहां पर दिक्कतें आ रही हैं और तीस हजारी के बाद तो पूरा अवैध पार्किंग चल रहा है। मैंने खुद डी.सी.पी. की गाड़ी में बैठकर, डी.सी.पी. ने अपने मोबाईल से फोटोग्राफ खींची और वो खुद बहुत शॉकिंग और हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है! जबकि उन्हीं की गाड़ी में बैठकर मैंने उनके साथ निरीक्षण किया! फोटो वे उन्होंने लीं। पर दुख की बात यह है अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई नहीं हुई! इसलिए मुझे ये मुद्दा दुबारा

से यहां उठाना पड़ रहा है। क्योंकि अभी डेंगू और मलेरिया की वजह से बहुत से लोग अस्पताल समय पर पहुंचने से वंचित रह रहे हैं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेंद्रपाल गोतम जी।

श्री राजेंद्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल सोलह स्कूल हैं और इन सोलह स्कूलों में शिक्षकों का भारी अभाव है। सुंदर नगरी में तो ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें लगभग 50 परसेंट टीचर्स का अभाव है। एक तरफ माननीय एल.जी. साहब, सरकार के सारे अधिकारों को अपने पास नियंत्रित रखने के लिए लगातार अपनी एनर्जी लगाते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है! जब स्कूल में, क्लास के अंदर टीचर न हो और टीचर के अभाव में बच्चे खाली क्लास में बैठने के लिए मजबूर हों, ऐसे हालात में मेरे जैसे व्यक्ति को पीड़ा होती है। जब मैं स्कूल में विजिट करता हूं और क्लासेज में मैं जब जाता हूं और देखता हूं कि टीचर नहीं हैं और प्रिसिंपल कह देते हैं कि भई, टीचर का अभाव है तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माधयम से बोलना चाहता हूं कि ये जो डी. एस. एस. बी. है जो सर्विसेज का काम देखती है, सलेक्शन का पूरा काम देखती है वो थोड़ा अपने सलेक्शन प्रोसीजर को एक्सपेडाईट करे। ताकि हमारे स्कूलों में और बाकी आफिसेज में भी पर्याप्त मात्रा में हमें स्टाफ मिल सके और बच्चों को इस तरह की परेशानी का सामना न उठाना पड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री संजीव झा।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, अभी आज से 15-20 दिन पहले हमारे यहां निगम के जो स्कूल हैं, मुझे उसमें जाने का मौका मिला और जब मैंने निगम के स्कूलों की हालत देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि स्कूल चल कैसे रहा है! मैंने ये देखा कि स्कूल में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है! हालात बद से बदतर हैं। एक बार एक पेपर में लिखा भी तो बार-बार लिखता रहा कि "the three Municipal Corporations have grossly failed in installing water purification systems in their schools." लगभग 1200 स्कूल हैं। एक भी स्कूल में वाटर प्यूरिफॉयर नहीं है। हालत, स्थिति बहुत बदतर है। बच्चों को पढ़ने के लिए नोटबुक तक की व्यवस्था नहीं है। इसमें माननीय अदालत ने भी कहा है : "However it is supposerd to learn, if there are no notebooks... it is not at all tolerable that 16 lacs children are going to schools without notebooks." - Justice Manmohan.

मेरा यह कहना है कि बार-बार कोर्ट की फटकार के बावजूद स्थिति वहां की ठीक नहीं हो रही है। स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कई सारे ऐसे स्कूल हैं, सुबह में लड़कियों का है, शाम में लड़कों का है। मजबूरी में बच्चों को ओपन ग्राउंड में शौचालय जाना पड़ता है। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर पूरे देश में करोड़ों रूपये खर्च किए गए लेकिन एक भी एम.सी.डी. के स्कूल में कंप्यूटर ठीक अवस्था में नहीं है। एक पेपर ने छापा भी था कि : "Not way but cog way. With no teachers, computers gathered dust in MCD Schools. इसमें लिखा था कि since 2000, Municipal corporation has hired no computer teachers, as a resul the machines have been lying in the locked rooms for the past 5 years gathering dust in the south MCD primary schools.

This is the state of computer labs. मेरा यह कहना है कि पूरी तरह से अव्यवस्था है! हद तो तब हो गई, जब मैंने पता किया बच्चों से। वर्दी के नाम पर बच्चों को कुछ पैसे दिए जाते थे। ऐसी व्यवस्था की गई थी। लेकिन कई स्कूलों में पैसे दिए नहीं गए। कई स्कूलों में उसके बदले जर्सी दी गई और जो जर्सी दी गई, इसके बारे में एक पेपर ने लिखा भी था, चूंकि कई सारे स्कूल्स के साथ, जो कपड़े बनाने वाली कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनसे साठ–गांठ है तो इसलिए सस्ती जर्सी उसको उपलब्ध करवायी जाती हैं। मेरी विधान सभा में, जहांगीरपुरी में एक स्कूल है। अभी विजेन्द्र गुप्ता जी चले गए, मैं फोटो दिखाता हूं, ये ही उद्घाटन करके आये थे! पांच साल पहले स्कूल की बिल्डिंग बननी शुरू हुई, आज भी वो कंप्लीट नहीं हुई है! एक तरफ दिल्ली सरकार ने आठ हजार कमरे छह महीने में कंप्लीट कर दिये, दूसर तरफ हालत यह है कि जिस बिल्डिंग का पांच साल पहले उद्घाटन किया गया था, आज उसी स्थिति में है । मेरा यह कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं अपने शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने दिल्ली के एजुकेशन को रि–बैक करने की कोशिश की है। पहली बार ऐसा ल गने लगा है कि अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में मिल सकती है और उसके उलट जो एम.सी.डी. के स्कूल हैं, दस साल से बी.जे.पी.एम.सी.डी. में हैं, वहां स्कूल का मतब खंडहर रह गया है, न तो टीचर की उपलब्धता है, न बच्चों की नोट बुक्स की व्यवस्था है, न साफ–सफाई है।

अध्यक्ष महोदय : संजीव जी, कन्क्लूड कीजिए।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय, तो इस सदन के माधयम से मैं तीनों एम.सी.डी. के कमिश्नर को अगाह करना चाहा हूं, आपके थ्रू निवेदन करना

चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और स्कूलों की हालत को ठीक किया जाये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सरिता सिंह जी।

श्रीमती सरिता सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठाने का मौका दिया। अभी लगभग एक हफ्ते पहले मेरी बात विधान सभा में अशोक नगर वार्ड है। अशोक नगर में बहुत छोटे-छोटे व्यापारी रहते हैं, किराये पर अपनी दुकान चलाते हैं, परचून की दुकान है, पान की दुकान है, छोटी-छोटी दुकानें हैं, जिनकी कई बार बोहनी भी नहीं हो पाती और कई बार केवल हजार दो हजार रूपये कमा पाते हैं। एम. सी. डी. ने केवल पैसा वसूलने के लिए उनको कनवर्जन टैक्स का नोटिस भेज दिया। उनके पास पार्किंग टैक्स का नोटिस भेज दिया कि आपको पार्किंग टैक्स जमा करना पड़ेगा, आपको कन्वर्जन देना पड़ेगा जबकि 2006 में जब कानून बना था, उसमें यह क्लियर था कि जो छोटे दुकानदार होंगे जिनकी 20 मीटर से बड़ी दुकान नहीं होगी, उनके ऊपर यह टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। फिर भी जबर्दस्ती उनसे यह टैक्स लेने की कोशिश की जा रही है बार-बार और टैक्स न जमा करने पर उनको धमकी दी जा रही है कि आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। मेरे क्षेत्र के अशोक नगर के लोग काउंसलर से मिलने गए, मेयर से मिलने गए, डी.सी. से मिलने गए, पर हर जगह से वो निराश होकर वापस आए और जहां पर उनको कोई भी जवाब नहीं दिया गया। उनका सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम पार्किंग चार्जेज देते हैं तो पार्किंग बनायेंगे कहां? हमारी छत के ऊपर! अशोक नगर में तो ऐसी-ऐसी गलियां हैं, जहां पर निकलना भारी है, जहां पर ऑटो रिक्शा नहीं जा सकता, वहां पर वो पार्किंग कहां

बनायेंगे? तो पार्किंग चार्जेज वो ले क्यों रहे हैं वहां पर? छोटे-छोटे दुकानदार जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जीना चाह रहे हैं, छोटी-छोटी दुकानें चला रहे हैं, अगर वो इतना टैक्स भरेंगे तो अपने घर का भरण-पोषण कैसे करेंगे! क्या वो दुकानदारों को धमकी देकर, जबरन पैसे वसूल करके उनको परेशान करना चाह रहे हैं तो इससे मेरे क्षेत्र के जितने भी छोटे व्यापारी हैं, वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है और उनकी तरफ से मैं आपसे यह अनुरोध करती हूं कि एम.सी.डी. कमिश्नर को तलब किया जाये और ईस्ट एम.सी.डी. कमिश्नर से कहा जाये, कि छोटे व्यापारी न पार्किंग टैक्स दे पायेंगे, न कन्वर्जन टैक्स दे पायेंगे और इसके लिए उनको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और न हो तो इस पर विधान सभा संज्ञान ले और एम. सी. डी. खिलाफ एक्शन ले, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति...मेरा ख्याल है कि यह सारे विधायक साथियों के लिए भी लागू होता है। पुलिस बिल्कुल एकाउंटेबल नहीं है! अभी 3 और 4 तारीख सितंबर की रात को मेरे क्षेत्र से एक फोन आया कि मेरे हजबैंड को पुलिस पकड़ कर ले गई है और उसको बहुत मारपीट रही है तो मैं वहां पहुंचा और यह सफदरजंग थाने की बात है। वहां पहुंचने के बाद देखा कि उस आदमी पुलिस ने हथकड़ी लगायी हुआ थी और इतनी पिटाई हो रही थी... Possibly he would have died अगर मैं वहां नहीं पहुंचता! जब मैंने पूछा कि किस कानून के तहत आपने अरेस्ट किया, कौन सा एफ.आई.आर. है? उनके पास कोई जवाब नहीं था।

उन्होंने कहा कि आपको हम कोर्ट से जवाब देंगे। मैंने कहा कि मुझे एक रिटन कंप्लेंट करना है। उस आदमी की दो जवान बच्चियां और उनकी पत्नी वहां पर थी, कहा कि आप थाने के बाहर जाकर के अपना कंप्लेंट लिखो। वूमन सिक्योरिटी के नाम पर कोई कसर्न नहीं था it was embarrassment! मुझे लगा कि मैं किसके पास जाऊं, किससे शिकायत करूं? मैंने ए.सी.पी. को फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। डी. सी. पी. को फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। ज्वाइंट सी. पी. को फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया तो हम इतने बेबस होकर के जियें क्या! मेरे पास कंप्लेंट्स हैं, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं। विजेन्द्र गुप्ता जी चले गये, आरती मेहरा जी भा.ज.पा. की बड़ी नेता हैं, उनके नाम से स्पेसिफिक कंप्लेंट दाखिल किया हुआ है हौज खास थाने में। उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जितेंद्र कुमार कोचर हैं, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। मेरे यहां क्षेत्र के पार्षद के हजबैंड हैं, उनके खिलाफ स्पेसिफिक कंप्लेंट है। महीनों हो गये, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह जो पुलिस का रवैया है हमारे एम.एल.ए. के प्रति, एम.एल.ए. उनको एस.एम.एस. भेज रहे हैं, मैं एस.एम.एस. भेज रहा हूं, वाट्सअप कर रहा हूं, ई-मेल कर रहा हूं, उस पर कोई जवाब नहीं है! अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बेबसी जो मैंने अभी-अभी झेली है और मेरा ख्याल है हमारे सारे साथी विधायक झेल रहे हैं, उसका कुछ न कुछ तो हिसाब-किताब आपके जरिये कराना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और एक थाना लेवल कमेटी हुआ करती थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को चेयर करते थे क्षेत्र के सांसद द कर्न्सड एम.एल.ए. वो बन गया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बन गई। चूंकि सातों के सातों सांसद भा.ज.पा. के हैं, इसलिए उसको बनने दिया गया, वो ऑपरेट भी

हो रहा है। थाना लेवल कमेटी को चेयर करते हैं वहां के विधयक। उसको बनने नहीं दिया जा रहा। मुझे लगता है चूंकि जैसा हमने पहले भी सदन में चर्चा की है कि जनता को मालूम नहीं होता कि किसके पास किसके लिए जाना है। पुलिस के साथ कोई समस्या होती है, पुलिस के खिलाफ कोई समस्या होती है तो जनता हमारे पास ही आती है तो हमारे पास जरिया क्या है? मैं आपके जरिये सदन से भी गुजारिश करूंगा कि सदन का एक under rule-54, there is a provision using which the House can communicate its disappointment os this ssue and request Hon'ble LG to do something about hon'ble committee and its powers.

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। मेरे क्षेत्र में मैं बहुत बेबस हूं। ढेर सारे केसेज हो रहे हैं जिसमें कि पुलिस की एकाउंटबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। मैं इस विषय को बड़ी गंभीरता से आपके जरिये उठवाना चाहता हूं। आप इस पर कृपा करके एल. जी. महोहदय के पास इस बात को पहुंचाने का कष्ट करें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। जैन साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री सत्येंद्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है, आज से पहले कई सालों से थाना लेवल कमेटियां हुआ करती थीं और जब एक साल का दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन था, एल. जी. रूल था - 14 फरवरी, 2014 से लेकर 14 फरवरी, 2015 तक, उस दौरान एल. जी. साहब ने खुद फाइल के ऊपर लिखा था कि why thana level committees are not formed, they should be formed immediately और उन्होंने थाना लेवल कमेटीज को बनवाया था। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के अंदर कहने के लिए लोकतंत्र है, हम लोग बड़े खुश होते हैं

कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं! मुझे शर्म आती है, कहते हुए कि अभी लोकतंत्र काफी दूर है! अभी लोकतंत्र में हम नहीं हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के 70 में से 67 सदस्य बनें और 7 एम.पी. में से 7 एम.पी. बने बी.जे.पी. के तो एल.जी. साहब ने जो अपने विचार थे, बदल दिये। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तो होनी चाहिए क्योंकि उन सब के जो अध्यक्ष हैं, वो एम.पी. होते हैं वो सारे क सारे के बी.जे.पी. के हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाये और थाना लेवल कमेटी को खत्म कर दिया जाये। मैंने उसका बहुत विरोध भी किया। उनको लैटर भी लिखे कि दिल्ली के अंदर अगर बी.जे.पी. की 3 सीटें आई तो उन्होंने अपने राजनीति के विवश होते हुए...सदन को यह बताते हुए दुख होता है कि उन्होंने कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटठी, उसकी तीन महीने में एक घंटे की मीटिंग होती तो है। आप सोचकर देखियेगा कि एक घंटे की मीटिंग में जिसमें 15 थाने, 20 थाने, 15-20 थानों को एक-एक मिटन या दो-दो मिनट मिलेगा, कहते हैं, काफी है, जैसे कि माइंडसेट वही है जिस जिस जमाने में वाइसरॉय साहब हुआ करता था कि हिंदुस्तान के लोगों को क्या चाहिए कि उनको दो मिनट मिल गये, काफी हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है कि थाना लेवल कमेटीज को खत्म किया गया है और उसके साथ-साथ दिल्ली पुलिस को किसी भी तरीके की जवाबदेही कहीं पर नहीं है। वो किसी भी पब्लिक रिप्रजन्टेटिव के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि बस एक ही टाइम पर वो एक्शन पर आते हैं। जब कोई कहे कि हां, किसी आम आदमी पार्टी के सदस्य के खिलाफ शिकायत...लिख देता है, एस.एम.एस. कर दे, किसी आम आदमी पार्टी की शिकायत करनी है, तुरंत वो अपने आप खुद ही उठकर आ जाते हैं, ए.सी.पी. साहब आ जाते हैं कि अभी आते हैं, अभी काम करते

हैं। जनता के लिए उनके पास समय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए और उसके लिए मैं माननीय सदस्य के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बंदना जी।

श्रीमती बंदना कुमारी : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत अच्छी स्थिति थी पहले लेकिन ये तीन चार महीने से पानी काफी गंदा और बहुत जगह तो पानी की सप्लाई बंद हो गई है जिसमें कुछ एरिया हैं हैदरपुर और शालीमार गांव और खादर, खादर की आर्युवैदिक कलस्टर जो है, वहां पर पानी की सप्लाई एकदम बंद हो गई है। कभी-कभी तो दो बजे रात में, थोड़ी देर के लिए आता है। कभी अधिकारियों से बात करें तो वो बोलते हैं कि दो डीडीए फ्लैट बहुत दिनों से बने हुए थे डीए ब्लॉक और सीएडीडी ब्लॉक जसमें बहुत दिनों से जब से बना, तब से पानी नहीं आ रहा था तो हमने काफी जद्दोजहद की और वहां पानी की सप्लाई डी. डी. ए. के और जलबोर्ड के दोनों के सहयोग से वहां पानी की सप्लाई तो हो गई। पहले तक टैंकर से ही उनको पानी मिलता था। आज पानी की सप्लाई उनको तो मिल गई लेकिन वो डीडीए फ्लैट में सप्लाई शुरू हो गई। लेकिन इधर पानी एकदम कम हो गया तो अधिकारी कहते हैं कि वहां पानी तो उतना ही है लेकिन ज्यादा जगह वितरण करने से यहां की पानी की कटौती हो गई। अब हमारे कुछ विपक्षी साथी हैं जो अभी फुर्सत में हैं, उनको कोई मौका मिलना चाहिए, मुद्दा मिलना चाहिए आये। दिन वो 50 लोगों को भेजते रहते

हैं ऑफिस में और बस वो पानी को लेकर तो मैं आपसे और सदन के माध्यम से मंत्री जी से भी कहूंगी कि उस एरिया में सीरियसली जरा सा देख लें। कहीं-कहीं पानी की बहुत दिक्कत है और लगभग चार महीने से लगातार अधिकारी भी प्रयास में हैं लेकिन पानी की समस्या हो रही है। चार-पांच एरिया हैं जिसमें मैं चाहूंगी कि जहां थोड़ी सी पानी की कैपिसिटी बढ़ा दी जाएगी तो समस्या का समाधान क्षेत्र में हो सकता है, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : नरेश बाल्यान जी।

श्री नरेश बाल्यान : धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा प्रश्न जल बोर्ड को लेकर है कि जलबोर्ड ने एक नियम बनाया है कि दस से ज्यादा कनेक्शन वाली अगर कोई बिल्डिंग है तो दस से ज्यादा कनेक्शन उसके अंदर नहीं मिलेंगे और पहले छह कनेक्शन का था और इसको बढ़ाकर दस कर दिया था लेकिन जो फ्लोर या प्लॉट जो पुराने बने हुए हैं, उनके अंदर दो सौ गज का मकान है तो बारह, पंद्रह, अठारह के आसपास फ्लोर बने हुए हैं। पचास-पचास गज के। अब उसमें दस लोगों को तो कनेक्शन मिल जाता है लेकिन दस के बाद जो फ्लैट बच गये, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो मेरा आपके माध्यम से जलमंत्री जी से यह निवेदन है कि जो ये सीमा इन्होंने तय की है, इस सीमा को खत्म किया जाए ताकि दिल्ली वासियों को बहुत लाभ मिले।

अध्यक्ष महोदय : सोमदत्त जी।

श्री सोमदत्त : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा में निगम पार्षदों द्वारा एम.सी.डी. के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार बदाव डाला जा रहा है, उनको डराया और धमकाया जा रहा है कि एम.एल.ए. के यहां से आई हुई पब्लिक की शिकायतों पर किसी भी प्रकार

की कोई भी कार्रवाई न की जाए। एम.सी.डी. के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका अंजाम भुगतने के लिए भी काउंसिलर द्वारा धमकी दी जा रही है जिससे एम.सी.डी. के कर्मचारी भारी दबाव में हैं और पब्लिक की शिकायतों पर जो एम.एल.ए. ऑफिस से प्राप्त होती है, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मसला है। पैसा तो एम. सी.डी. दिल्ली सरकार से मांगती है और हमारे आफिस पब्लिक के आफिस हैं। पब्लिक अपनी कॉमन कम्प्लेंट्स लेकर आती है जैसे सफाई नहीं हो या डेंगू की मशीनों से दवाई वहां पर डलनी है। जब भी ऐसा कोई काम होता है काउंसलर ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि एम. एल. ए. के यहां से आई हुई कम्प्लेंट पर कोई कार्रवाई न की जाए।

मेरा आपसे अनुरोध है, एक एग्जाम्पल भी कोट कर रहा हूं। आजकल मलेरिया-डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा है। आपकी सबकी जानकारी में है। अभी मैंने वहां के एम.सी.डी. के कर्मचारियों को हरिजन बस्ती में मलेरिया की दवाई डलवाने के लिए भेजा तो काउंसलर ने उनको बुलाकर स्पेशियली बोला, एम.सी.डी. के कर्मचारी हैं वो कि अगर एम.एल.ए. के कहने पर आप कहीं पर भी कोई भी काम करने किसी कम्प्लेंट पर कार्रवाई करने गये तो आपका ट्रांसफर करा दिया जाएगा और आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर एम.सी.डी. को पैसा दिल्ली सरकार देती है तो पब्लिक की कम्प्लेंट्स की कमप्लायेंस भी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम पब्लिक केरिप्रजेन्टेटिव हैं। अपना पर्सनल काम नहीं करवा रहे, पब्लिक की कम्प्लेंट्स का समाधान करा रहे हैं और हमने कभी भी नहीं कहा कि काउंसलर दिल्ली जलबोर्ड के सीवर साफ करवा रहे हैं तो उसमें कोई रूकावट आये, पब्लिक का काम है, चाहे वो काउंसिलर के आफिस में आये, चाहे

एम.एल.ए. के आफिस में आये। वो काम होना चाहिए, चाहे किसी के भी माधयम से हो। जब हम ऐसी सोच नहीं रखते तो काउंसलर ऐसी सोच क्यों रखते हैं? कभी हाउस के अंदर अपने प्रपोजल लेकर आते हैं कि एम.एल. ए. के यहांपर एम.सी.डी. के अधिकारी नहीं जाएंगे। कभी तरह-तरह की दुर्भावना के तरहत ऐसे प्रपोजल लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक के काम सफर कर रहे हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है इस मामले पर उचित एम. सी. डी. का की जाए ताकि पब्लिक को राहत मिल सके, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, धन्यवाद।

श्रीमती बंदना कुमारी : अध्यक्ष जी, ये सभी एरिया में है, हमारे एरिया में भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि एम.एल.ए. जब विजिट पर बुलाये तो उनके जिविट पर मत जाओ और एकदम से ही ये बहुत ही अलग है और हम सबको इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सदन के माध्यम से इसमें सभी कमिश्नर को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय बाजपेयी जी, 280 पूरा हो गया, प्लीज।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : सर थोड़ा सा है।

अधधक्ष महोदय : नहीं, अब फिर और कइयों का आयेगा। आदरणीय सत्येंद्र जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सत्येंद्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, यूडी के अभी लगभग छह प्रश्न सदस्यों ने अलग-अलग पूछे हैं, मैं इंतजार कर रहा था क्योंकि सभी के लगभग एक ही जैसे प्रश्न थे। तो मैंने कहा कि अलग-अलग जवाब न देकर इकट्ठा जवाब दे देंगे। सबसे पहले तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि एम.एल.ए. फंड से जो भी कार्य कराये जाते हैं या एमपी फंड से कराये

जाते हैं या काउंसलर फंड से कराये जाते हैं, वो फंड जो होता है, वो होता है इमरजेंसी काम कराने के लिए, जल्द से जल्द काम कराने के लिए। जिस भी एक्जीक्युटिव एजेंसी को दिया जाता है, उसको बहुत ही जल्दी उस काम को करना होता है। फंड ही एक साल के लिए होता है। अब फंड से ये कई सालों का काम नहीं चलना होता। आपने कोई काम कहा है कि नाली बनवानी है, कोई सड़क टूट गई है, सड़क ठीक करानी है, कहीं पर झूले लगवाने हैं, छोटे-मोटे काम होते हैं, बैंच लगानी है वो एक-दो महीने में, तीन महीने में, चार महीने में हो जाना चाहिए। यहां पर कई सदस्य हैं, आदरणीय विपक्ष के नेता भी हैं, उनको पता ही होगा कि सिस्टम क्या होता है कि फंड जल्द से जल्द खर्च करके...बनाना होता है। अगर हमारे सदस्य बता रहे हैं कि जानबूझकर उसको डिले किया जा रहा है तो यह बहुत सीरियस मैटर है और मैं सभी सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी एम. एल. ए. फंड से किया गया काम, किसी भी डिपार्टमेंट को दिया गया है, उसको जल्द से जल्द कराया जायेगा और आप हमें सारी डिटेल दीजियेगा। सबको तुरंत कराकर देंगे।...(व्यवधान) आप सब को कर लेना न, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं जो अफसर है, उसको बुला लीजियेगा। आपकी पॉवर है। मैं आश्वासन दे रहा हूं आपको। जो भी अफसर है, उसको यहीं बुलाओ। क्या दिक्कत है?

श्रीमती सरिता सिंह : और इसकी समय सीमा में है कि छह महीने ...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाज : इसको खत्म किया जाए हाउस के अंदर।

...(व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री : आप सबको कर लेना न जी। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं न। जा अफसर है, उसको बुला लीजियेगा। आपकी पावर है। मैं आश्वासन दे रहा हूं आपको। जो भी अफसर है, उसको यहीं बुलवाओ। क्या दिक्कत है?

श्री सौरभ भारद्वाज : वो आते नहीं हैं न कई बार।

लोक निर्माण सदस्य : सर पैसे लेते हैं और कुछ नहीं करते।

लोक निर्माण मंत्री : सर, देखियेगा, विधान सभा की जो शक्तियां हैं, वो अब हमारे विजेन्द्र जी से पूछ लेना। वो बता देंगे आपको कि क्या-क्या शक्तियां होती हैं, कैसे-कैसे किसी को बुलाना होता है। अगर मैंने आश्वासन दिया है, आप उन सब अफसरों को बुलवाइयेगा। काम नहीं करते हैं तो उनसे पूछियेगा कि क्यों नहीं काम कर रहे हैं और उनको सजा देने का आप ही का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। मैं सदन में बोल रहा हूं। सोच-समझकर बोल रहा हूं। दूसरा अगर कोई अधिकारी जनता के कार्यों के लिये आने से मना करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है और उसका भी संज्ञान लिया जायेगा और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें राइटिंग में या लिखित में किसी तरह के किसी ने आदेश दिये होंगे। अगर कोई इस तरह के आदेश हैं तो उनके बारे में बिल्कुल पूछताछ की जाएगी और इसका भी मैं आश्वासन देता हूं कि जनता के काम करने के लिए जितने भी अधिकारी हैं, जनता के लिए बने हैं।

...(व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री : मैं न्यूज पेपर की बात नहीं कर सकता मैं तो अपनी करता हूं। अगर इस तरह के अगर आदेश हैं तो वो गलत हैं। ऐसे कोई आदेश नहीं दिये जा सकते हैं। जितने भी अधिकारी है, वो सिर्फ जनता

के काम करने के लिए...जनता के काम करने के लिए उन्हें आना होगा और काम करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, अब ये प्लीज, देखिए, ये सारे विषय रह जाएंगे। सोमनाथ जी, मैं ले रहा हूं विषय। आ रहा हूं ना आप बैठिये दो मिनट बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी ये प्रश्न काल नहीं है प्लीज। कई लोगों के हाथ उठे हुए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो इसका मतलब ये हुआ विजेंद्र जी कि आपका पहला नंबर होता तो आप शोर नहीं मचाते! आपका पहला नंबर 280 में होता तो आप सदन को ठीक से चलने देते! चलिये, जगदीश जी ग्यारहवां नंबर है मैं समय दे रहा हूं आपको, बोलिए।

श्री जगदीश प्रधान : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान उच्च न्यायालय के उस निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने 21 संसदीय सचिवों का पद समाप्त कर दिया है। सरकार ने अपने अधिक से अधिक विधायकों को पद और लाभकारी आकर्षणों द्वारा नियम कायदे और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए 21 संसदीय सचिव नियुक्त किये सरकार ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये विजेन्द्र जी ये 280 का मामला थोड़ी है!...एक सैकेंड जगदीश जी को बोलने दीजिये...नहीं मैंने कहा है।

अध्यक्ष महोदय : ये नहीं लगेगा 280 में।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 280 का हिस्सा है ये...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, फिर वही...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिये आप बोल लीजिये क्या बोलना है बोलिये छोड़िये। आप बैठिये आप पढ़ दीजिये जो लिखा है आप पढ़ दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, ऋतुराज जी प्लीज, गोयल साहब

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने पढ़ दिया ना बस बात खत्म हो गई। बैठिये बैठिये, जगदीश जी, इस पर चर्चा नहीं। मैं सबको रोक रहा हूं कोई चर्चा नहीं।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, इनको बात तो पूरी करने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वो कह रहे हैं पढ़ दिया...पढ़ दिया उन्होंने सारा।. ..आप क्यों फीड कर रहे हैं? उन्होंने पढ़ दिया सारा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समय तो पता नहीं किस किस चीज में बर्बाद हो रहा है। बैठिये जगदीश जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब हो गया प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधान : सर, मैं बिल्कुल बैठ जाना चाहता हूं। अगर इजाजत आपकी हो तो...

अध्यक्ष महोदय : नहीं अब हो गया प्लीज।

श्री जगदीश प्रधान : विशेषकर दिल्ली वासियों को ही नहीं अपितु संवैधानिक संस्थानों को गुमराह करने का प्रयास किया है। अतः सरकार संविधान का उल्लंघन के कारण राजकोष की हानि की भरपाई की जाये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें मैं व्यवस्था दे रहा हूं नेता प्रतिपक्ष से एक पत्र प्राप्त हुआ है इसमें किसी नियम का कोई उल्लेख नहीं है। वे इस तरह नोटिस देते हैं, मेरी सुन लीजियेगा विजेन्द्र जी, ...मैं व्यक्तिगत बात कर लूं एक बार अभी बैठकर यहां पर। आपने मुझे ऐड्रेस किया है। उस पर किसी नोटिस का जिक्र नहीं है कोई कानून की संख्या रूल, नियम...एक सैकेंड रूक जाइये। मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। कोई उल्लेख नहीं है। वे इस तरह नोटिस देते हैं कि वे अपने आप खारिज हो जायें और ऐसा लगता है कि वे सच्चे दिल से चर्चा नहीं

चाहते... दो मिनट रूक जाइये। विजेन्द्र जी, मैं दूंगा समय।... भई, राठी जी प्लीज, अमानतुल्लाह जी प्लीज,... इसको मैंने विचारार्थ ले लिया था लेकिन नेता प्रतिपक्ष से आज ही नियम 54 के अंतर्गत धयानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई हैं। मैंने उसको ले लिया था लेकिन आपने 54 में भी दे दिया अब ये ही मैटर! ...एक ध्यानाकर्षण अल्पकालिक चर्चा पहले ही सूचीबद्ध है तथा और कार्य भी होना है। अतः ये सारा काम आज निपटाने के बाद भी श्री गुप्ता जी के नोटिस पर लगभग सांय पांच बजे अध्यक्ष के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए चर्चा की जायेगी। मुझे आशा है कि वे शांति पूर्वक सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे और चर्चा में भाग लेंगे। पांच बजे मैं इस विषय को ले लूंगा।

अब श्री नितिन त्यागी, माननीय सदस्य इस संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा संबंधी विवरण के कथित रूप से लीक होने से निर्वाचित मुख्यमंत्री की सुरक्षा का हनन हुआ है।

ध्यानाकर्षण (नियम-54)

श्री नितिन त्यागी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 54 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक बहुत रीसेंट घटना है। ये कल की घटना है। इस घटना पर आने से पहले... मैं एक बहुत पुरानी कहानी, आप सब ने भी सुनी होगी, वो बताना चाहूंगा। छोटी सी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बस में बहुत सारे लुटेरे घुसे, उन्होंने पूरी की पूरी बस लूटी एक-एक आदमी को औरत को जो है, उनको लूट लिया, उनका सामान ले लिया। सामान जो लूटा उसको देखा, हिला के कितने का है। उन्होंने कहा कि लो भैया, इसको वापिस ले लो, बोले क्यों वापिस क्यों कर रहे हो? बोले कि इससे ज्यादा तो पुलिस को देने पड़े जायेंगे तो ये एक पुलिस का

और क्रिमिनल्स का हमेशा नैक्सेस रहा है और साथ में मिल के बड़े-बड़े कारनामे इन लोगों ने किये हैं और आम आदमी को लूटा है! ये सब थोड़ी सी न्यूज पेपर की कटिंग्स हैं। ये दैनिक जागरण की चार तारीख की कटिंग है, ये तो बिल्कुल रिसेंट है जिनको मैं आपको दिखा रहा हूं, ''सरकारी तंत्र की शह पर चल रहे कोठे दिल्ली पुलिस, एस. डी. एम. और निगम की उदासीनता के कारण नहीं होती कारवाई! ये दिल्ली पुलिस इन्वाल्व है इसमें।'' ये आज की है, ''पुलिस दबा गई कोठा सील करने के आदेश, कोर्ट के आदेश भी नहीं माने गये।'' मैं इसलिये दिखा रहा हूं कि ऐसे पुलिस और क्राइम हैंड इन हैंड रहा है दिल्ली के अंदर। अभी पंजाब गुजरात की बात नहीं कर रहा है मैं विजेन्द्र जी। ये एक और है बड़ी शर्मनाक! टाईम्स आफ इंडिया की liquor bottle missing or empty, court slams police 2005 में liquor bottle. एक हरियाणा से एक, सज्जन कहूं या दुर्जन कहूं तो वो स्मगल करते थे। दिल्ली के अंदर वो पकड़ी गई और दिल्ली पुलिस पास थी तो सील तोड़ के शराब पी गये दिल्ली पुलिस वाले! शर्मनाक बात है! सोचना चाहिए। हम सब विधायक यहां पर बैठे हैं। हमारे यहां पर डेली कम्पलैंटस आती होगी कि क्षेत्र में कहीं न कहीं चोरी हो गई है और उस चोरी के बारे में पता करो तो यूजअली ये था। पीछे से चोरी हो गई। ये सारा का सारा एक नैक्सेस है आम आदमी को लूटने का। सरकारी तंत्र का मिसूज करने का। ऐसे ही कल सुबह एक घटना दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई, पर यहां पर मैं जिन लोगों की बात कर रह हूं, वो शायद क्रीमिनल्स नहीं थे और उन्होंने भी पुलिस के साथ मिलकर कुछ ऐसी घटना करने की कोशिश करी। सीएम साहब पंजाब जा रहे थे, उनको एक तथाकथित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कुछ लोगों ने घेरा, धक्का मुक्की की, हमला करने की कोशिश की लेकिन

उससे बड़ी बात और कि उससे पहले पुलिस ने सीएम साहब की सिक्योरिटी के बारे में जो भी इन्फारमेशन हो सकती थी या लैक ऑफ सिक्योरिटी की जो भी इन्फोरमेशन हो सकती थी, वो अखबार में दे दी! सर, ये न्यूज पेपर है कल का। आठ तारीख ये फ्रंट पेज पर है इसमें "Cops do not have full itinerary or Delhi Police gets back at Kejri Won't provide cover during his Punjab tour." कहने को तो सर, ये खबरें जरा डिफरेंट सी हैं। अब न्यूज पेपर वालों की या मीडिया वालों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो खतरे का अनुमान लगायें या कितना खतरा है, खतरा ज्यादा है या खतरा कम है, है भी या नहीं है ये उनकी रिस्पोंसिबलिटी नहीं है, पुलिस की रिस्पोंसिबलिटी है। वो तो हमेशा तत्पर रहते हैं कि कोई भी नई चीज मिले उसे छाप दो। आजकल तो वैसे भी तत्पर रहते हैं कुछ भी तो वैसे खिलाफ मिल जाए तो छाप दो। तो बड़ी तत्परता से उन्होंने छाप दिया। जिम्मेदाराना हरकत थी या गैर जिम्मेदाराना, ये तो मैं नहीं कहूंगा। सब लोग समझदार है अपने आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ये बता रही है कि किस तरीके के हथियार, वहां की सिक्योरिटी, जो सीएम साहब के लिए है वो यूज करते हैं कि "Is secured by commandos armed with sub MP-5 machineguns, Klsahnikov SLRs and block pistols." मतलब क्या-क्या हथियार होंगे, वो उनको बता दिया। इधर कहां-कहां वो जाएंगे, मोगा जाएंगे, वो बता दिया। उनके पास सिक्योरिटी नहीं होगी, ये बता दिया कि सिर्फ दो पीएस होंगे, ये भी बता दिया और ये कब बता रहे हैं? ये बता रहे हैं सर, ये 19.08.2016 का एक कमिश्नर आफ पुलिस को लैटर लिखा स्पेशल सैकेट्री होम ने, इसमें रैफरेंस आता है सर, एक सज्जन शिव नंदन शर्मा उन्होंने एक चिट्ठी लिखी ओ. एस. डी., सीएम को कि सीएम और डिप्टी

सीएम साहब की जान को खतरा है। सैक्रेटेरेयैट और सीएम साहब के घर पर बम के धमाके करने की योजना बना रहे है। एक अकरम साहब हैं और एक मुरलीधरन साहब हैं। अकरम साहब से भी बात हो गई पुलिस की, मुरलीधर जी आज एक एब्सकॉण्डिग हैं। ये शिव नंदन शर्मा जी दिल्ली पुलिस में ही कार्यरत है। अकरम और मुरलीधर पहले होम गार्ड में थे। अब इतना बड़ा खतरा होते हुए, इस तरीके की सिक्योरिटी की डिटेल्स दी जा रही है। एक छोटा सा सवाल है। अगर विजेन्द्र गुप्ता जी सीएम होते तो क्या दिल्ली पुलिस की हिम्मत होती इस तरीके की सिक्योरिटी की डिटेल्स को डायवल्ज करने की, बता देने की या जगदीश प्रधान जी होते या ओम प्रकाश शर्मा जी होते या कोई और बी.जे.पी. का होता तो ऐसी सिक्योरिटी की डिटेल्स दे देती क्या पुलिस? देखिए, सबसे पहले तो सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिसने डिसाइड किया ये सिक्योरिटी थ्रैट सिमी तक का सिक्योटिरी थ्रैट, इसमें लिखा हुआ है पूरा, सिमी का सिक्योरिटी थ्रैट, इंडियन मुजाहिदिन का सिक्योरिटी थ्रैट है सीएम साहब की जान को। उसके बावजूद सिक्योरिटी हटाने का जो कार्य किया दिल्ली पुलिस ने, क्या इसको ये माना जाए कि आज हमारे दिल्ली के सीएम साहब की जान को खतरा है और उस खतरे का फायदा विपक्ष उठाना चाहता है। सिर्फ इसलिए कि वो पंजाब हार रहा है, गुजरात हार रहा है, गोवा हार रहा है। इतनी नीचता की राजनीति हो गई है हमारे देश में! जो महिलाएं वहां पर पहुंची जिन्होंने सीएम साहब का घेराव किया! क्या रेलवे स्टेशन के अंदर आज की तारीख में कोई भी ऐसा आंदोलन या धरना या प्रदर्शन करना एलाउड है? ये कब से एलाउड हो गया? हमें तो नहीं पता चला, क्या ये एलाउड है, क्या पुलिस को वहां पर नहीं होना चाहिए था? हम तो परमीशन लेकर जाते हैं तो हमें रास्ते में से रोक लेते हैं, उठा-उठा कर चार-चार, पांच-पांच

घंटों को थाने में डाल देते हें। इनमें से किसी को उठाया पुलिस ने? किसी को डिटेन किया या ये लोग प्लेटफार्म टिकट लेकर गए थे? अगर प्लेटफार्म टिकट नहीं लेकर गए थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? अगर वो धरना देने गए थे तो क्या उन्होंने परमीशन ली थी? प्रदर्शन करने गए थे तो क्या उन्होंने परमीशन ली थी? अगर परमीशन नहीं ली थी तो उन्हें परमिट किसने दिया? क्योंकि प्लान तो ये था... क्योंकि मीडिया भी वहां पर थी। क्या हुआ इंटलीजेंश? ये दो चीजें हो सकती हैं या तो दिल्ली पुलिस इन्कम्पीटैंट है, उसे पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ होने वाला है या दिल्ली पुलिस मिली हुई थी इन प्रदर्शनकारियों के साथ में। आप वीडियो को देखिए। आप वीडियो को देखिए। एक वीडियो मंगाकर जरूर देखिएगा सर! वहां पर रेलवे की पुलिस भी थी। वो भी मोदी पुलिस है और दिल्ली पुलिस भी थी। वो भी मोदी पुलिस है। केंद्र के अंदर है दोनों। हंस रहे थे वहां पर! खड़े होकर हंस रहे थे वहां पर! सीएम के साथ धक्का-मुक्की होरही थी! आज दिल्ली का रेलवे स्टेशन सेक्योर नहीं है, रेड अलर्ट रहता है दिल्ली के अंदर। सीएम से तो चलिए आप बदला भी ले रहे होंगे, कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है ये रिर्हसल हो कि उनकी सिक्योरिटी की जांच करने का और अगली बार घटना को अंजाम दे दिया जाए। सीएम साहब ने भी अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे लोग होते हैं रेलवे स्टेशन पर। जरूरी नहीं है दिल्ली के हों। ऐसे राज्यों के भी हो सकते हैं जहां आपकी सरकार है। उन्हें भी मरवाना चाहते हों, ये कमाटली ब्रीच आफ सिक्योरिटी है! अगर देश की सच्चाई के लिए उठने वाली सबसे मुखर आवाज को इस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है तो क्या इसके लिए कोई जांच नहीं होनी चाहिए? इन पुलिस वालों के ऊपर जिन्होंने अपने आप डिसाइड कर लिया कि सिक्योरिटी

नहीं देंगे या सिक्योरिटी की डिटेल्स को पूरे के पूरे न्यूज पेपर में बता देंगे! इनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई नहीं चाहिए? क्या इनकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए?

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, कंकल्यूड करे प्लीज।

श्री नितिन त्यागी : सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन पर ट्रीचरी प्लान के तहत सीएम साहब के ऊपर अटैक करवाने का जो प्लान बनाया गया, क्या इसमें दिल्ली पुलिस एन्वाल्व थी, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस एन्वाल्स थी तो उनके पीछे किसका हाथ था, किसने उन्हें प्रेरित किया, किसने उन पर प्रैशर डाला, किसने उनको सुपारी दी, इसकी जांच होनी चाहिए? मोदी ओर अमित शाह... मैं नाम नहीं लेता, वो तो जगजाहिर है। क्या जिन लोगों ने सर, ये कार्य किया, उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, इसका एश्योरेंस कौन देगा? जिस तरह से रेलवे स्टेशन को धेरकर प्रदर्शन का अड्डा बनाया गया, प्रदर्शन के बहाने से धक्का-मुक्का की गई केजरीवाल साहब के साथ में, सीएम साहब के साथ में, देश के हमारे राष्ट्र की राजधानी के सीएम के साथ में, अगर वो एनसेक्योर हैं तो हमारी दिल्ली में कौन सेक्योर है? इस बात को मैं खत्म करना चाहूंगा सर, और आशा करता हूं कि आपकी तरफ से ये एश्योरेंस आएगा कि इन सब चीजों की जांच होगी। मैं बता देता हूं स्पेल आउट कर देता हूं कि इन सब चीजों की जांच चाहिए। जिन लोगों ने ये प्रदर्शन किया, क्या उनके पास परमिशन थी और अगर नहीं थी तो क्या पुलिस को पता था या नहीं? अगर पता था तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर प्रदर्शन हो ही गया तो उसके बाद उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई, रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा क्या कार्रवाई

की गई? एक भी आदमी का प्लेटफार्म टिकट चैक हुआ या नहीं हुआ, किस तरीके का फाइन लगेगा, कौन डिटेन हुआ, किससे पूछताछ की गई और दिल्ली पुलिस को ये काम करने के लिए किसने प्रेरित किया, इन सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए?

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। आप मुझे परमीशन दें। एक ट्वीट था जिसमें अरविंद जी ने लिखा, "I am in Shatabadi right nows spoke to several people, everyone is against Modi Govt. surge-pricing. तो किसी ने कमेंट किया 'I am in same Shatabadi did not speak to anyone. People hooted seeing you entering in coach and this tweet was re-tweeted by Ministry of Railways. अगर इस तरह के ट्वीटस मिनिस्ट्री आफ रेलवेज के आफिशियल ट्वीटर एकाउंटस से रिट्वीट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो जो घटना नितिन भाई बता रहे हैं, जो प्लेअफार्म पर घटी, सरकार का हाथ है उसके अंदर। जांच होनी चाहिए इसकी। इस तरह की एमिनिटी, इस तरह की कह सकते हैं वीभत्स! जो इन्होंने किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। काश! हमारे पास सीबीआई होती।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए सोमनाथ जी, बैठिए प्लीज। सरिता जी।

श्रीमती सरिता सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं नितिन भाई की बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातिों पर और ज्यादा एम्फेसिस करना चाहूंगी। मैं दो पहलुओं पर बात करूंगी—एक दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों कर रही है और दूसरा, मैं बिल्कुल क्लीयर बोलूंगी। शायद इन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन मैं नाम लूंगी। मोदी जी की जो भा.ज.पा. की सरकार है, भा.ज.पा. की मोदी सरकार

की मानसिकता कितनी गंदी और घिनौनी है कि एक प्रदेश के सी. एम. के साथ वो किस तरह व्यवहार करते हैं, इसमें डेट वाईज कोट करते हैं, 07 सितंबर को पूरे मीडिया में चलता है कि दिल्ली पुलिस अब केजरीवाल जी को सुरक्षा नहीं देगी। मैंने आज तक कभी-भी किसी न्यूजपेपर में, किसी भी न्यूज में एक्सैप्ट ये जो केजरीवाल जी का न्यूज आया, कभी-भी न्यूज नहीं सुना कि अब कोई भी पुलिस या कोई भी ऑर्गनाइजेशन पर्टिकुलर मंत्री या पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या एक्स. वाई. जैड. वी. आई. पी. को सिक्योरिटी नहीं देगी! क्योंकि वो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलटी ऑफ दिल्ली पुलिस कि वो ये ब्रीच ना करे, वो ऐसा काम ना करे। पर बकायदा दिल्ली पुलिस मीडिया को बताती है, मीडिया में न्यूज चलता है और अगले ही दिन सुबह पूरा इनका शैड्यूल जैसा नितिन भाई ने बताया, पूरा इनका शैड्यूल छपता है और अगले ही दिन सुबह जब वो शताब्दी से पंजाब जाने को होते हैं, सबसे बड़ी बात प्वाइंट टु बी नोटिड वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, फिर भी वो एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। वो चाहते तो हैलीकॉप्टर, प्लेन किसी से भी जा सकते थे, पर वो ट्रेन से गए क्योंकि वो आम आदमी की जिंदगी जीना चाहते हैं। वो आम आदमी की तरह रहना चाहते हैं। तो जब वो शताब्दी से रवाना होने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो जब उनकी एंट्री होती है, उसी एंट्री गेट से बिना चैकिंग के, कुछ महिलाएं एंटर करती हैं और वहां पर अरविंद केजरीवाल जी का विरोध होता है। मैं पूरे घटनाक्रम को इसलिए बता रही हूं कि जब ये विरोध होता है, हमने भी बहुत धरना-प्रदर्शन किए हैं, मुझे याद है एक बार हरियाणा में शीला दीक्षित गई थी। वहां पर किसी कार्यक्रम के लिए और ये सबको पता है कि पी. डी.एस. में कितना बड़ा घोटाला था, संतोष कोहली जी के साथ हम लोग

वहां पर गए थे। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने यहां पर ये हवाला दिया कि क्योंकि वे दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। हम उनका पंजाब में सिक्योटिरी नहीं दे सकते तो क्या शीला दीक्षित हरियाणा की मुख्यमंत्री थी जो दिल्ली पुलिस वहां पर सिक्योरिटी देने गई थी! सबसे पहला सवाल? और जहां पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अंडर कोर्ट वो दिल्ली की सीमा के अंदर आता है। ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की बात नहीं हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली के अंदर है। यानि वहांपर दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी उनको सिक्योरिटी देने की। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे वीडियो में जैसा नितिन भाई ने बताया, वो क्लीयर था कि किस तरह वहां पर महिलाएं आई, वहां प्रदर्शन किया, धक्का-मुक्की हुई और सब कुछ हुआ। दिल्ली पुलिस वहां पर केवल हाथ पर हाथ बांध के, चाहे वो रेलवे पुलिसरही हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस रही हो, हाथ पर हाथ बांध के खड़े थे। वो केवल एक नजारा देख रहे थे, ये कैसे हो सकता है? ये क्लीयर है। मीडिया में न्यूज आई। अगले दिन प्रदर्शन हुआ, वहां महिलाएं पहुंची।

अध्यक्ष जी, ये पूरा का पूरा प्लान है। पिछली बार भी ये बात हुई थी कि जांच की मांग हम किनसे कर रहे हैं? उन्हीं से कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। हम जांच की मांग उसी सी.बी.आई. से कर रहे हैं जिस सी.बी.आई. को सुप्रीम कोर्ट ने पैरट बोला हुआ है, ‘‘It is a mere parrot." ये क्लीयर साजिश है जो देखने को मिलती है, हमेशा मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इसमें तीसरे प्वाइंट पर आना चाहूंगी। क्योंकि इस पार्टी की वालिंटियर हूं और बहुत मेहनत की है, बहुत आंदोलन किए हैं। जब

भा.ज.पा. ने इस प्रदर्शन का तैयारी की तो पूरे एस. एम. एस. किए, पूरे कॉल किए, कि वहां केजरीवाल जी का घेराव होगा। सारी महिलाएं पहुंच जाएं, सब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। कितनी? बीस! पूरी दिल्ली की भा. ज. पा. महिला मोर्चा की 20 महिलाएं पहुंच पाईं। मैं ये बोलना चाहती हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका हुआ ना, इसको चाहे चेतावनी समझ लीजिए, चुनौती समझ लीजिए, जो समझना है, वो समझ लीजिए। रिकॉर्ड डालना है, डालिए। नहीं डालना है, मत डालिए। लेकिन ये क्लीयर है अरविंद केजरीवाल का बाल भी बांका हुआ तो पूरी की पूरी दिल्ली की महिलाएं 6 तो यहीं बैठी हैं, पूरी की पूरी दिल्ली की महिलाएं 7 आर. सी. आर. और दिल्ली पुलिस हैडक्वार्टर पे नजर आएंगी और तब आप नहीं बच पाओगे।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए सरिता जी, अब प्लीज।

श्रीमती सरिता सिंह : बिल्कुल अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले आपको याद होगा। अरविंद जी ने ये कहा था उनकी जान को खतरा है। अभी नितिन जी ने पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें खुद सरकार ये मान रही है कि सी. एम. की जान को खतरा है। तो ये सब कुछ पता था। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने लापरवाही बरती! मोदी पुलिस ने लापरवाही बरती! रेलवे पुलिस ने भी लापरवाही बरती! तो इनकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए और जिम्मेदारी तो ये तय करने से रहे और कल जब गुजरात में इन्हीं के पार्टी के प्रेजिडैंट, जो इनका गढ़ है, मैं नाम नहीं लूंगी, इन्हीं के पार्टी के प्रेजिडैंट वहां पर सम्मेलन करने के लिए गए थे। तो गुजरात में उनके खिलाफ धरने दिये गए! यानि इनको ये पता है कि ये पंजाब तो हार ही चुके हैं। गोवा

भी हार रहे हैं, गुजरात भी हार रहे हैं। तो यही एक तरीका है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को रोका जाए। मैं बार-बार ये कहती हूं कि अरविंद केजरीवाल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है और वो सोच हम सबके मन में है और लाखों-लाखों लोगों की दुआएं हैं इनके साथ में और ऐसे कई लोग जिनमें से कुछ इस विधान सभा में भी बैठे हैं, जो उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : करिए, कन्क्लूड करिए।

श्रीमती सरिता सिंह : तो इसलिए ये चुनौती/चेतावनी जो समझना है, समझिए और दिल्ली पुलिस को आप सम्मन करिए। मैं बार-बार ये कहती हूं कि दिल्ली पुलिस को सम्मन करने का भी क्या फायदा होने वाला है क्योंकि वह तो वही काम कर रही है जो मोदी जी का ऑर्डर मिला हुआ है। मोदी जी की कार्य करने की शैली यही है जो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो ठीक-ठीक चलेगा और क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनकी गंदी नीतियों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो उनको मारने की, उन पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे वो डरने वाले नहीं हैं और हम सब उनके साथ हैं और दिल्ली पुलिस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये हादसा दिल्ली का है। पंजाब की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये हादसा दिल्ली के अंदर हुआ है, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर हुआ है। तो ये कैसे हुआ, ये इन्फार्मेशन लीक कैसे हुई, इसकी पूरी की पूरी तह में जाने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है और इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, धन्यवाद, दिनेश मोहिनिया जी।

श्री दिनेश मोहनिया : धन्यवाद, अध्यक्ष जी, समय देने के लिए। वैसे तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि डिटेल मेरे साथियों ने बता दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार की नीति मोदी जी और अमित शाह जी की है, वो अपना विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये गुजरात मॉडल है। इसमें विपक्ष को बर्दाश्त न करने की, इसमें जो एक है कि या तो उनको किसी तरीके के केस में फंसाओ, केसों में नहीं फंसते तो फिर एनकाउंटर करो और विपक्ष को मतलब किल करने की, विपक्ष को खत्म करने की जो एक प्रवृत्ति है, इनमें खासकर मोदी जी में और शाह जी में, उसी का ये परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में कोताही बरती गई है और जो सेंध लगाने की कोशिश की गई हैं, ये एक तरह से प्रैक्टिस की जा रही है, एक तरह से ट्रायल किया जा रहा है कि किस तरह से इनकी सुरक्षा में सेंध लगे या किस तरह से उन पर हमला किया जा सके और ये ऐसा नहीं है कि ये केवल पहली बार हो रहा है, कई बार हो चुका है और कई बार पुलिस को लिखा भी गया है लेकिन जो दिल्ली पुलिस के जो आका बैठे हैं, वो बिल्कुल मैंटली इस तरह से प्रेपेयर है कि धीरे-धीरे एक ट्रायल किया जाए कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कैसे घुसा जा सकता है और कैसे उन पर हमले किए जा सकते हैं। ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, इन्होंने 15 साल में गुजरात में बिल्कुल यही किया है, जो खुद इनकी अपनी पार्टी के गृह मंत्री थे हरेन पांडया जी, उनका एनकाउंटर किया, जिसकी जांच अभी तक चल रही है लेकिन उस जांच में भी देखेंगे कि पुलिस को कुछ नहीं मिला जबकि खुद प्रदेश के गृह मंत्री होते हुए उनकी हत्या हुई थी। ये सारे जो ये गुजरात मॉडल हैं... एक वर्ड आपने सुना होगा इन्टॉलरैंस, इनमें विपक्ष की किसी भी बात, किसी भी तर्क को समझने

की कोशिश नहीं है। केवल यही बात है कि जो भी विपक्ष है, किसी तरह से उसकी बात ना सुनी जाए, उसके तर्क न सुने जाएं। केवल उसको किल किया जाए, उसको दबाया जाए। जैसे आज सुबह की ही घटना है। एक हमारे कॉमेडियन हैं, कपिल शर्मा जी उन्होंने जरा सा केवल एक ये लिखा कि मुझसे रिश्वत मांगी गई तो आज देख रहे हैं उनके ऊपर केस हो गया है, उनके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करा दी गई है कि और अब ये पता लग रहा है कि उनके ऑफिस को ही इल्लीगल बना दिया है। अब आप देखें उनके ऊपर केसेज होंगे कुछ दिन में, कुछ दिन में गिरफ्तार करेंगे उनको। मतलब इस देश में यह हो गया है कि जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो इस समाज का हिस्सा हो, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसकी आवाज को कुचल दिया जाएगा। वो तो सब देख रहे हैं कि कौन किस को कुचल रहा है और किसके पास ताकत है कुचलने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : अबकन्क्लूड करिए। कन्क्लू करिए प्लीज।

श्री दिनेश मोहनिया : मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो ये प्रवृत्ति है ये काफी दिन लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। क्योंकि जिस तरह का इन्होंने पाटीदारों के साथ किया, जिसमें इन्होंने दलितों के साथ जो किया, वो जिस तेजी के साथ इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिस तेजी के साथ सब इकट्ठे हो रहे हैं, उसका एक उदाहरण कल सूरत में देखने को मिला है और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से सूरत के अंदर अमित शाह जी का विरोध हुआ है, ये आवाजें और तेज होंगी और जितना ये कोशिश कर रहे हैं, इन आवाजों को दबाने के लिए, इनको कुचलने के लिए उतनी तेजी के

साथ सब ये एकजुट होंगे और जो गुजरात मॉडल हैं, उसे धवस्त कर देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्षा जी, अभी मेरे पूर्व साथियों, पूर्व वक्ताओं ने वक्तव्य दिया, वह ऐसे लग रहा था कि कोई हादसे और विरोध की बातें यहां चल रही हैं। क्योंकि मुझे इस बात का याद है कि जब चुनाव चल रहा था तो एजेंडे में रखा था कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए... हमें सुरक्षा नहीं चाहिए और जब मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल जी को मिली तो पत्रकारों ने पूछा कि आपने तो कहा था कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। अब तो आपके चारों तरफ सुरक्षा ही सुरक्षा चल रही है! तो उन्होंने कहा कि ये मैंने इनको नहीं कहा, जहां मैं जाता हूं ये मेरे पीछे-पीछे आ जाते हैं और ये तो मेरी जासूसी कर रहे हैं। यानि कि सुरक्षाबलों का बार-बार मनोबल गिराया गया। अभी मोहनिया जी कह रहे थे... यानि की अगर दूसरी पार्टी के बारे में बात करनी है तो वो विरोध है और अपने मुख्य मंत्री के बारे में बात करनी है तो वो हमला है! सुरक्षा को खतरा है! वास्तविकता यह है जिस तरह का रोष जनता में है, उसको शायद आम आदमी पार्टी समझने को तैयार नहीं है। जिस तरह से संदीप कुमार ने...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : संदीप कुमार के मामले में पूरे सदन में खामोशी पसरी हुई है। यहां कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई नोटिस नहीं दिया गया सत्तारूढ़ दल की तरफ से।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप विषय को डॉयल्यूट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल डॉयल्यूट कर रहे हैं। जब मैंने आपका नियम-54 का नोटिस एक्सेप्ट किया हुआ है। पांच बजे समय दूंगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं उस पर नहीं जा रहा अभी। मैं सुरक्षा की एक सीडी बता रहा हूं। मेरे पास एक सुरक्षा से संबंधित सीडी है, आप इजाजत देंगे तो...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरे पास एक सुरक्षा से संबंधित सीडी है। इसी सदन में मंत्री के रूप में बैठे हुए थे। आज जेल में हैं। वो बात कर रहे हैं कि मुझे सुरक्षा लेनी है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी। देखिए जिस विषय पर चर्चा चल रही है आप उससे डायवर्ट हो रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं डायवर्ट...अगर मैं एक भी शब्द डायवर्ट...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब तक आप डायवर्ट हो रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं सुरक्षा पर बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं सुरक्षा पर बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री की सुरक्षा और मंत्री की सुरक्षा पर बात कर रहा हूं। उसमें वो कहते हैं... अपने साथी से कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। सुरक्षा लेनी है और फिर कहते हैं कि उसके लिए एक काम करते हैं... मैं मीडिया को जरूर वो सीडी दूंगा और आप सबके पास भी भेज दूंगा और उसको सुनवाऊंगा संदीप कुमार जी की आवाज में! वो कह रहे हैं कि ऐसा करो, मेरे ऊपर गोली चला दो। पूर्व मंत्री जो बलात्कार के मामले के आरोप में अभी जेल में है और उसके बाद मेरी गाड़ी पर गोली चला दो, उसके बाद मुझे सियोरिटी मिल जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, विषय कुछ और है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। विषय ये मुख्य मंत्री जी को जाना था... रेलवे प्लेटफार्म के ऊपर जो सरकारी जगह है, जहां एंट्री बैन है, चर्चा इस पर हो रही है।

विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री को 150-200 आदमी मिले हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : भई, इनको बोलने दो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, देश के लोगों को बताना चाहता हूं...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी जवाब देंगे न मंत्री जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर विरोध होता है, अगर जनता प्रदर्शन करती

है...महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ होता है और वो अपनी आवाज उठाती हैं तो उनकी आवाज कुचलने के लिए सरकार ये षड्यंत्र करती है। ये इमोशनल ब्लैकमेल कब तक चलेगा? ये टोटल-टोटल इमोशनल ब्लैमेल है। ये एक नाटक है जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि जो आशुतोष जी...अभी चर्चा आएगी, जब सारी बात करूंगा। मैं भी अभी करना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : चलिए बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : लेकिन महिलाओं के अंदर रोष है। उस रोष के आगे आप उनको, क्या जो महिलाएं अपनी अस्मिता की बात करती हैं, मुख्य मंत्री से गुहार लगाती है, आप उनको क्या गोली मरवाना चाहते हैं? आप क्या कार्रवाही करना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिए बैठिए-बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप करिए। सबको वीडियो फुटेज हैं। सब जानता है। वो महिलाएं हैं। आप महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं!

अध्यक्ष महोदय : चलिए बैठिए-बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नाटक कर रहे हैं यहां पर सुरक्षा के नाम पर!

अध्यक्ष महोदय : चलिए कपिल मिश्रा जी। विजेन्द्र जी, अब आप...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, विशेष रवि जी। अब विजेन्द्र जी बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :माननीय मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी।

पर्यटन मंत्री (श्री कपिल मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, अपनी बात रखने पहले दो चीजें कहना चाहता हूं। एक चीज तो यह कहना चाहता हूं कि गुप्ता जी संदीप कुमार वाले मुद्दे पर...हम तो इंतजार कर रहे हैं कि सदन में चर्चा कब होगी। हम तो वेट कर रहे हैं। जब चर्चा होगी तब भाग मत जाना। जब चर्चा होगी तो भसागना मत।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, विजेन्द्र बैठ जाओ।

...(व्यवधान)

पर्यटन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज अगर वो बीस महिलाएं जनता होती तो तुम्हारी तीन सीट नहीं होती दिल्ली में! लेकिन मैं एक और बात यहां रखना चाहता हूं इस पूरी परिप्रेक्ष्य में दिल्ली का पर्यटन मंत्री होने के नाते मैं यह बात रखना चाहता हूं कि कल नई दिल्ली स्टेशन पर जो हुआ है, जो जांच होनी चाहिए, वो मामला अपनी जगह पर है और उसकी मांग भी जायज है। लेकिन इस पूरे शहर की, इंडियन रेलवे की, शताब्दी और राजधानी ट्रेन की और पूरी दुनिया में दिल्ली की जो पहचान है, ज्यादातर जो पर्यटक आते हैं, वो नई दिल्ली स्टेशन पर आते हैं। शताब्दी और राजधानी ट्रेनों का उपयोग करते हैं और ये माना जाता रहा है कल तक कि ये सुरक्षा के तौर पर थोड़ी ज्यादा सुरक्षित ट्रेन होती हैं। इस स्टेशन को भी सुरक्षित माना जाता था लेकिन कल जो हुड़दंग की तस्वीरें पूरी दुनिया में गई है जिसमें भा.जा.पा. के लोग

नई दिल्ली स्टेशन पर हुड़दंग की तस्वीरें पूरी दनिया में गई है जिसमें भा. जा. पा. के लोग नई दिल्ली स्टेशन पर हुड़दंग कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, शताब्दी ट्रेन के आगे बवाल कर रहे थे, पूरे देश की छवि और इंडियन रेलवे की छवि पूरी दुनिया के आगे कल गिरी है। इस देश का, भारत देश का, दिल्ली शहर का, नई दिल्ली स्टेशन का और इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा एक अपमान... और मुझे लगता है कि रेटिंग में असर दिखता है जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो इंटरनेशनल रेटिंग में असर दिखता है। देश की छवि में असर दिखता है। भारत के टूरिज्म पर, आने वाले यात्रियो पर असर दिखता है और वो भी जब नई दिल्ली स्टेशन पर हो जो कि मेन इंटरलिंकिंग स्टेशन है। बाकी राज्यों से अगर कोई ताजमहल भी जा रहा है तो उस वक्त वह स्टेशन पर होता है, सुबह के समय। जयपुर जाने वाले पर्यटक भी वहीं पर होते हैं। तो ये वहां पर स्टेशन में थे उस वक्त। विदेशी नागरिक भी उपस्थित थे। पर्यटक भी उपस्थित थे। दिल्ली में आने वाले, दिल्ली से जाने वाले, मुझे लगता है कि जिन्होंने भी किया है, किस राजनैतिक दल के हैं, वो भी सामने है। मुझे लगता है कि जांच वगैरह तो बाद में हो लेकिन उस राजनैतिक दल की एक जिम्मेदारी यह बनती है कि देश से और दुनिया से माफी मांगे। मैं पर्यटन मंत्री होने के नाते ये चिंता व्यक्त करता हूं कि इंडियन रेलवे मंत्री को भी यह चिंता होनी चाहिए कि रेलवे की जो छवि गिरी है, वो बनाने में दोबारा 5-10 साल लग जाएंगे, यहीं मैं सदन में रखना चाहता था, थैंक्यू सर।

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृहमंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी।

श्री सत्येन्द्र जैन (गृह मंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मुद्दा जो है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

हमने कभी नहीं कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए। फिर भी कल के अखबारों में जब पढ़ा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए इतने लोग लगे हुए हैं, वो ये-ये हथियार रखते हैं, उनका ये शेड्यूल ये होगा। मुझे ये अखबार से पता लगा। मैं दिल्ली के अंदर मंत्रीमंडल का सदस्य भी हूं। मुझे नहीं पता... इसका मतलब जान-बूझकर ऐसा माहौल पैदा किया गया। क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी, मेरी सुरक्षा, मैं सुरक्षा बिल्कुल नहीं लेता। हमारे मंत्रिमंडल में किसी को सुरक्षा दी भी नहीं गई। परंतु मेरे ऊपर अगर थ्रैट है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, सुरक्षा अपने-आप करेंगे। मुझे तो पता भी नहीं लगेगा। अभी क्या है, मेरे घर पर प्रदर्शन करने के लिए एक महीना पहले काफी सारे लोग आए थे। 200-300 लोग थे। तो मैं घर पे गया तो मुझे घर के बाहर ही रोक लिया। मैंने कहा जी, मेरा ही घर है तो कहते हैं कि अच्छा-अच्छा तो निकल जाओ। तो मुझसे तो पूछ करके तो नहीं आए थे वो अब ये काम है। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे और दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी थे कि मैंने नही बुलाया, मैंने सुरक्षा नहीं मांगी। इसलिए मेरे घर पर नहीं आयेंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आज से कुछ महीने हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जो थे ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जी, उनको श्रद्धाजंलि देने के लिए गए थे। वहां का माहौल देखा! हमारे प्रधानमंत्री महोदय जाने वाले थे दो केबिनेट मिनिस्टर मेरे साथ में खड़े थे उनके केबिनेट के जो सैंटर के केबिनेट मिनिस्टर थे। मैं भी साथ में था। ये नहीं आम आदमी है, कहा कि गर्दन दूसरी तरफ कर लो। पुलिस वालों ने उनकी गर्दनें दीवार की तरफ कराई थी और ये लोग कहते हैं कि हम सुरक्षा की की बातें करते हैं। क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है इस तरह की चीजें देखने की। जहां तक यह कहना है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी नहीं, ये सबको पता है। हमारी आपत्ति ये है कि पुलिस को सुरक्षा

नहीं देनी, मत दें परंतु सुरक्षा के अंदर ऐसे काम तो न करें कि उनके ऊपर हमला करने वालों को आसानी हो सके। आज से कुछ महीने पहले छत्रसाल स्टेडियम में, सभी को पता होगा पूरी दिल्ली की केबिनेट थी, मुख्यमंत्री जी वहां पर थे। उनके ऊपर हमला किया गया था, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में किया गया था। कोई पूछ सकता है कि छत्रसाल स्टेडियम की तरह कुछ हो रहा है। वो स्याही लेकर आई। बम लेकर भी आ सकती थी लेडी! तो वहां पर किसी ने उसे चैक नहीं किया। कह रहे हैं कि स्याही ही तो थी। मैं जानना चाहता चाहता हूं अगर ये सारी चीजें दिल्ली पुलिस, दिल्ली के दिल्ली के मुख्यमंत्री के समाने होने देती है, दिल्ली के अंदर 77 मिनिस्टर्स है केंद्र सरकार के। आज तक ढाई साल हो गए सरकार बने हुए, बी. जे. पी. के कितने मंत्रियों के साथ सुरक्षा में खामी हुई है, मैं ये जानना चाहता हूं? प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए। उनको तो खैर! सभी चीजें हैं। उनके ढाई हजार सुरक्षाकर्मी एक साथ चलते हैं, उनके साथ में। बाकी किसी भी मंत्री के साथ ऐसी चूक आज क्यों नहीं हुई है? तो कहते हैं कि चूक वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे नितिन जीने कहा था कि ये प्लान लग रहा है कुछ। ये जान-बूझके इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, ऐसा मौका दिया जा रहा है। जो तथ्य हैं, उनको बताया जा रहा है कि आप जाइए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप हमला कर सकते हैं। अगर आप हमला करेंगे तो सदन में आपको डिफेंड करने वाले लोग बैठे हैं और बाहर तो पुलिस है ही। पुलिस भी कहेगी कि हां जी, सुरक्षा लेने से इन्होंने मना किया था। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती नहीं थी। अब इन्होंने कुछ कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कुछ महीने पहले अभी कहा था, एक दो महीने पहले कहा था कि मेरे जीवन को खतरा है ओर सबको पता है कि किससे खतरा

है। अब ये मत कहना कि मुझसे खतरा है! खतरा तो उसी से होगा जिनकी सत्ता जा रही है। अभी बी.जे.पी. पंजाब में, गोवा में, और गुजरात में, सबको पता है हारने वाली है। वो उसको सहन नहीं कर पा रही है और मैं समझता हूं कि जो कल हुआ, वो इससे जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफार्म स्टेशन के बाहर होता तो भी समझ में आता है कि कुछ लोग आ गए, जब टीवी पे देखा पुलिस वहां पर होती है। उसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री को धक्का देने का मौका दिया गया! क्योंकि धक्का-मुक्की की गई तो धक्का-मुक्की करके वो प्लेटफार्म पर डाल सकते हैं, गिरा सकते थे, ट्रेन के आगे भी धक्का दे सकते थे। फिर कह देता हम क्या करें? ये तो आम लोगों को शह देना, सर फोटोज जो हैं, मैं विशेष रवि जी से कहूंगा कि उसके नाम बताएं इनको कि इनके बी.जे.पी के कौन-कौन थे या नहीं थे और मैं मांग करता हूं कि अगर वो बी.जे.पी. वाले नहीं थे, अगर वो महिलाएं 15-20 महिलाएं जो भी थी, वो बी.जे.पी. से संबंधित नहीं थी तो हमारे विपक्ष के सदस्य कहेंगे कि बयान दें कि उनका बी.जे.पी. से कोई संबंध नहीं है। किसी तरह के कोई संबंध नहीं है। और मैं गारंटी लेकर कहता हूं कि उन सबका संबंध बी.जे.पी. से होगा, तभी उन्होंने ऐसे काम किए हैं, और कोई कर नहीं सकता।

मेरे सामने एक घटना हुई जो पहले मैंने आपको बताई थी वो महिला भी यही शोर मचाने आई थी कि मैं तो पब्लिक के लिए आई हूं। बाद में पता लगा कि केशवपुरम मंडल की महिला विभाग की अध्यक्ष थी वो बी. जे. पी. की, आपकी खास है। उन्होंने आते ही मेरे खिलाफ पुलिस में कम्पलैंट भी कर दी थी। वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वर्ना कह देते कि हम तो जानते ही नहीं। हमारे को क्या पता! ये सारा प्रायोजित कार्यक्रम था। सब कुछ

इन्होंने जान-बूझकर किया और सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार की है। और सुरक्षा केवल मुख्यमंत्री की क्यों? एक आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। मैं पूछना चाहूंगा आज भी दिल्ली पुलिस कितने एक्स एम. एल. एज., जो इस विधानसभा के एक्स एम. एल. एज., मैं अभी गया था एक फंक्शन में वो एम. एल. ए. साहब आए थे। मैं गया। मैं तो जैसे था, वैसे ही चला गया। एम. एल. ए. साहब के साथ में पुलिस की दो गाड़ियां थीं और मैंने मंच पे कहा कि सहाब, आपको सुरक्षा की क्या जरूरत है? आपसे तो जनता को सुरक्षा की जरूरत है। आप सुरक्षा के लिए घूम रहे हो तो मैंने कहा कि आपसे जनता डरती है, आप पुलिस को क्यों लेके चल रहे हो? और कान में कहते हैं कि भाई साहब, दिखाने के लिए कुछ करना पड़ता है। वो कहते हैं दिखाने के लिए, अपना रौब पड़ता है। चाहे हमारे जो विपक्ष के सदस्यगण है, ये भी सुरक्षा लेकर के चलते होंगे। जरूर लेके चलते होंगे। वैसे मुझे पता नहीं है पर मैं मान नहीं सकता कि आप न लेके चलते हों। क्योंकि उससे रौब पड़ता है। तो रौब दिखाने के लिए दो-चार पुलिस वाले अपने साथ लेकर चलते ही चलते हैं। तो यह पुलिस जो ये कहती है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था, इसलिए सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और विपक्ष के लोगों को सुरक्षा देती है। जो लोग एक्स एम.एल.ए. हैं, उन सबको सुरक्षा देती है कि क्यों देती है कि उनका रौब पड़े। मेरा जनता के ऊपर रौब रहे। काउंसलर बी.जे.पी. के है ना, सर, उनको पीटेगा कोई, रहने दें। मेरा ये कहना है कि सुरक्षा कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है और अगर सुरक्षा नहीं भी दे सकते, कम से कम सुरक्षा को खतरे में न डालें। सरक्षा को खतरे में डालना बहुत ही गलत काम है। मुझे लगता

है कि किसी साजिश का नतीजा है ये। हम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से इसकी जांच करायेंगे, पूछेंगे कि इसमें किसने गलती की है? क्या जान-बूझके ऐसा किया गया है? जो लोग वहां पर आए, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया और लोगों को गिरफ्तार किया या नहीं किया? मुझे याद है आज से कुछ दिन पहले दिल्ली के 54 विधायक और मंत्री प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गए थे तो उनके उतरने से पहले, जैसे ही बस से उतरे गाड़ी से उतरे, उनको उठाके पुलिस स्टेशन ले गए। अभी हम तो सड़क पर चल रहे हैं। आप इतने सड़क पर चलते हैं तो पुलिस को वो... एम.एल.ए. है आप। चलो अंदर चलो। तो उसमें से जो 20 लोग थे या 15 लोग थे, उनमें से कितनों को थाने में ले गए। कितने घंटे बैठाया गया, हम ये पूछना चाहते हैं? फिर उन्होंने पूछताछ की कि क्या वो हमला करने आए थे या प्रदर्शन करने आए था या अपना ज्ञापन देने आए थे और उन्होंने वही जगह क्यों चुनी? वो मुख्यमंत्री के घर पर क्यों नहीं चले गए? घर पर चले जाते। तो इन्होंने उनको दिखा दिया कि मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना कितना आसान है! उनको धक्का देना कितना आसान है! तो उन्होंने लोगों को बताया है कि आप आ सकते हो, हमारी तरफ से पूरी छूट है और जिस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है, मैं चेताना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री के जीवन के साथ इस तरह का कोई खिलवाड़ हुआ तो देश सहन नहीं करेगा और बी.जे.पी. को भुगतना पड़ेगा बहुत बुरे तरीके से। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा का आम नागरिक की तरह से दिल्ली के जितने भी आम नागरिक हैं, सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए और कम से कम सुरक्षा नियंत्रण में छेद नहीं करना चाहिए और जब भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली में आएं... जब गलती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में वापिस आ जाएं, अभी भी विदेश में हैं तो उनकी सुरक्षा का

ध्यान भी दिल्ली पुलिस ही रखे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उनको याद दिलाएं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी कभी-कभी आते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इनको बड़ा कष्ट रहता है। हम इस तरह की राजनीतिक बातें करना नहीं चाहते हैं। जान-बूझके ये बीच-बीच में लेके आते हैं और फिर कहते हैं कि कहां क्यों? कहते हैं खूंटा गाड़ के अरे! हिंदुस्तान के अंदर गाड़ रहे हैं ना, पाकिस्तान में तो नहीं गाड़ रहे। ये लोग तो पाकिस्तान में जाकर के खूंटा गाड़ रहे हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान में से हिलूंगा नहीं। बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। अरे! जा के ओबामा के पीछे-पीछे घूमते रहते हैं। कोई आज हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री... दो साल के अंदर तीन बार चीन की यात्रा करने जा रहे हैं! अरे! इनके पास देश के अंदर टाइम नहीं है। मेरे ख्याल से पूरे देश में घूमो ना। उनके पास चुनाव यात्राओं के अलावा विदेश यात्राओं से फुर्सत नहीं है। फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की बातम मत कीजिएगा। अरे! आप हमें छेड़ते हैं बार-बार। प्रधानमंत्री भी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री... कहना चाहिए परिधान में लगे रहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं...आप छेड़ रहे हैं ना। इस देश के अंदर पहले प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं जिन्होंने आज तक ढाई साल के अंदर जितने वस्त्र पहने, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाए। इन्होंने जो कपड़े पहने, वो सौ करोड़ पहनते हैं। आप छेड़ते हो, फिर कहते हो कि प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हो, हम जिक्र नहीं करना चाहते। हर चीज में प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं और बार-बार प्रधानमंत्री जी को बीच में मत लाइयेगा। अगर लायेंगे तो आपको एक की जगह चार सुननी पड़ेंगी और शाम के टाईम आप सोच-समझ के बोलियेगा। जो भी बोलेंगे न। कही न सहन कर पायें और छोड़ के भाग जायें मैदान! सर जी, सच-सच बता देंगे। उनके नाम भी बता देंगे

सदन के अंदर नाम बता देंगे। सदन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हमें पता है।... अध्यक्ष महोदय, इसको नोट किया जाये। अभी इन्होंने मुझे धमकी दी है। गंभीर धमकी दी है और मैं इसको लिखवाना चाहता हूं कि मेरे जीवन को अगर कुछ भी होता है तो विजेन्द्र गुप्ता जी इसके जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा है अपनी जिंदगी मत बर्बाद कीजिएगा। सर, इन्होंने धमकी दी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं विजेन्द्र जी, अब वो अपना उत्तर दे रहे हैं। ठीक उत्तर दे रहे हैं। सत्येंद्र जी, पूरा हो गया। जैन साहब, पूरा हो गया। बैठिए, बैठिए।

गृह मंत्री : और दूसरा मैं कह देना चाहता हूं। ये लोग तो वो लोग हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगा करते थे और माफीनामा लिखकर दिया करते थे। अध्यक्ष महोदय, जो धमकी इन्होंने दी है न... सर, धमकी दी है, जवाब देना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : चलिए रिकार्ड हो गया।

स्वास्थ्य मंत्री : 2014 में इन्होंने हमला भी कराया था मेरे ऊपर और उस हमले के बाद मैं घर नहीं बैठा था। उस दिन कसम खाई थी, इन नेताओं को और इस सिस्टम को बदलने के लिए। इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। नेताओं की नेतागिरी खत्म करना है। खत्म करके छोड़ना है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

स्वास्थ्य मंत्री : एक मिनट और मैं दुबारा से कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस से इसकी जांच कराई जायेगी और पूरी सुरक्षा के अंदर जो भी कमियां रही हैं, उसकी जांच रिपोर्ट इस सदन के सामने रखी जायेगी।

अनुदान की पूरक मांगों पर विचार एवं पारण।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी...वो आ रहा है। मैं लूंगा विषय। 2016-17 के लिए फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमैंट्री डिमांड पेश करेंगे। मनीष सिसौदिया जी।

Deputy Chief Minister : Hon'ble Speaker Sir, I present first batch of supplementary demands for the yesr 2016-17 before the House.

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सप्लीमेंट्री डिमांग पर डिमांग वाईज विचार करेगा :

डिमांड नं. 3, आग ये होंगे आपके पास। क्या अभी आई नहीं रिपोर्ट आपके पास? दीजिए, दीजिए। आप टेबल पर नहीं थी जब वितिरत हुई।

डिमांड नं. 3 एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। जिसमें रेवेन्यू में एक लाख रूपये हैं, सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 3 पास हुई।

डिमांड नं.–4 (फाईनेंस) जिसमें रेवेन्यू में एक लाख रूपये हैं, सदन के सामने हें :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 4 पास हुई।

डिमांड नं.–6 (एजूकेशन) जिसमें रेवेन्यू में एक करोड़ दस लाख रूपये और कैपिटल में पांच करोड़ उन्तीस लाख रूपये हैं, कुल राशि 6 करोड़ 39 लाख रूपये सदन के सामने हैं–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 6 पास हुई।

डिमांड नं.–7 (मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ) जिसमें रेवेन्यू में दस करोड़ तीन लाख रूपये और कैपिटल मेंप ांच करोड़ यपये हैं, कुल राशि 15 करोड़ 3 लाख रूपये सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 7 पास हुई।

डिमांड नं.–8 (सोशल वेलफेयर) जिसमें रेवेन्यू में तीन लाख रूपये और कैपिटल में 1 करोड़ 51 लाख रूपये हैं, कुल राशि 1 करोड़ 54 लाख रूपये सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 8 पास हुई।

डिमांड नं.–10 (डेवलपमेंट) जिसमें रेवेन्यू में चार लाख रूपये हैं, सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 10 पास हुई।

डिमांड नं.–11 (अरबन डवलपमेंट एंड पब्लिक वर्कस) जिसमें रेवेन्यू में 117 करोड़ 50 लाख रूपये और कैपिटल में 2 लाख रूपये हैं, कुल राशि 117 करोड़ 52 लाख रूपये सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 11 पास हुई।

हाउस ने कुल मिलाकर रेवेन्यू में 128 करोड़ 72 लाख रूपये तथा कैपिटल में 11 करोड़ 82 लाख रूपये कुल राशि 140 करोड़ 54 लाख रूपये की सप्लीमेंट्री डिमांड को मंजूरी दी है।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री अप्रोप्रिएशन (नं. 3) बिल 2016 को हाउस में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगे।

विनियोजन (सं. 3) विधेयक 2016 का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

Dy. C .M. : Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce appropriation No. 3 bill 2016 to the House.

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री बिल को सदन में इन्ट्रोड्यूस करेंगे :

Dy. C. M. : Hon'ble Speaker Sir, I introduce appropriation No. 3 bill 2016 to the House.

अध्यक्ष महोदय : अब बिल पर क्लॉज वाईज विचार होगा।

प्रश्न है कि खंड-2, खंड-3 व शेड्यूल बिल का अंग बने :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

खंड-2, खंड-3 एवं शेड्यूल बिल का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड-1, प्रिएम्बल और टाईटल बिल का अंग बने :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
खंड-1, प्रिएम्बल और टाईटल बिल का अंग बन गये।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि अप्रोप्रिएशन (नं. 3) बिल 2016 को पास किया जाये।

Deputy Chief Minister : Hon'ble Speaker Sir, the House may please pass the appropriation No. 3 bill 2016

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
अप्रोप्रिएशन नं. 3 बिल 2016 पास हुआ।

माननीय अध्यक्ष की टिप्पणी

माननीय सदस्यगण, अब जनादेश को विफल करने के उद्देश्य से, विधिवत रूप से निर्वाचित विधान सभा को निष्क्रिय बनाने के कथित असंवैध ानिक प्रयासों के विषय मपर सुश्री अलका लाम्बा द्वारा चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं सदन के सामने कुछ तथ्य रखना आवश्यक समझता हूं।

मेरे विशेष अनुरोध पर श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा को दिल्ली विधान सभा के सचिव के रूप में आकाशवाणी से प्रतिनियुक्ति पर लाया गया था।

इनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष की थी जो बाद में दो वर्ष तक बढ़ा दी गई। आदेश प्रतिनियुक्ति 16 जुलाई, 2018 तक वैध है।

मैंने इनकी सेवाओं को उत्कृष्ट पाया तथा विचार किया कि यदि इन्हें यहां स्थायी आधार पर समावेशित (absorb) कर दिया जाये तो दिल्ली विधान सभा को अत्यधिक दीर्घकालीन लाभ होगा। तदनुसार, इस बारे में इनकी इच्छा जानकर, मैंने आकाशवाणी से श्री सूर्यदेवरा के दिल्ली विधान सभा में स्थायी आधार पर समावेशन के लिए सहमति देने का अनुरोध किया है। आकाशवाणी ने स्टाफ की कमी का कारण बताते हुए अपने पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2016 को मेरा अनुरोध स्वीकार करने में असमर्थता जाहिर की। उक्त संस्थान ले श्री सूर्यदेवरा को आकाशवाणी में वापस भेजने के लिए यह बताते हुए अनुरोध किया कि इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि 16 जुलाई, 2016 को समाप्त हो चुकी है जो कि गलत है, जबकि वास्तविकता यह है कि इनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि 31 मई, 2016 को, पहले ही 16 जुलाई, 2018 तक बढ़ा दी गई थी।

श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा पिछले 12 वर्षों से भी अधिक समय तक लगातार आकाश्वाणी से बाहर रहे हैं। इस अवधि के दौरान उन्होंने विधायी कार्य-प्रणाली के विषयों में गहन अनुभव तथा विशेषज्ञता हासिल की। दिल्ली विधायी कार्य-प्रणाली के विषयों में गहन अनुभव तथा विशेषज्ञता हासिल की।

दिल्ली विधान सभा में आने से पहले श्री सूर्यदेवरा ने माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के कार्यकाल में 5 वर्ष तक तथा माननीय सभापति, राज्य सभा के कार्यकाल में 6 वर्ष तक कार्य किया। कुल मिलाकर इन्होंने लगभग 11 वर्षों तक भारत की संसद की सेवा की। यह समय अब तक इनके द्वारा आकाशवाणी में बिताई गई अवधि से कहीं ज्यादा है।

इस मामले में संबंध में मैंने माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री को दो बार, 18 तथा 28 अगस्त, 2016 को पत्र लिखा। माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने पत्र प्राप्त होने की सूचना दी तथा यह आश्वस्त किया कि मामला विचाराधीन है।

इस बीच, 30 अगस्त, 2016 को सुबह जब मैं उदयपुर, राजस्थान गया हुआ था, मुझे सचिव ने फोन किया और बताया कि उन्हें सेवा विभाग से एक आदेश की फैक्स से प्रति प्राप्त हुई है, जिसमें उन्हें उपराज्यपाल महोदय की अनुमति से 29 अगस्त, 2016 को दोपहर बाद से कार्यभार मुक्त कर दिया गया है। मुझे अपने कार्यालय से भी इसकी सूचना मिली। मुझे यह जानकर हैरानी हुई है कि उपराज्यपाल महोदय ने ऐसे असंवैधानिक आदेश को जारी करने की अनुमति कैसे दी दी!

पहले कदम के तौर पर मैंने श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा जी को फोन पर बताया कि मैं उन्हें रिलीव नहीं कर रहा हूं तथा उन्हें सचिव के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखनी चाहिए। मैंने इस संबंध में अपने कार्यालय से सचिव तथा सचिवालय को लिखित आदेश भी जारी कर दिया।

तत्पश्चात् इस पूर्वानुमान के साथ कि उपराज्यपाल महोदय को ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश जारी करने की अनुमति देने में गुमराह कर दिया गया होगा, मैंने उदयपुर से उनसे बात करने के लिए उनके कार्यालय में फोन किया। उन्होंने बात करने से मना कर दिया। भगवान् उनकी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करे!

मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था कि मैं उन्हें यह स्पष्ट

करते हुए पत्र भेजूं कि विधायिका में किसकी सर्वोच्चता है। मुझे उनको यह साफ शब्दों में बताना था कि इस मामले में उनकी कोई अधिकारिता है। मुझे उनको यह साफ शब्दों में बताना था कि इस मामले में उनकी कोई अधिकारिता नहीं है तथा उन्हें विधान सभा सचिव के पद से और सचिवालय से दूर रहना चाहिए तथा विधायिका से उनका कोई मतलब नहीं है। मैं इस पत्र को सदन की कार्यवाही का भाग बनाना चाहता हूं। मैं निर्देश देता हूं कि मेरा वक्तव्य समाप्त होने के बाद तथा चर्चा शुरू होने से पहले इसे तत्काल कार्यवाही में शामिल किया जाए।

मैं एक बार फिर यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि श्री सूर्यदेवरा जी इस विधान सभा में बतौर सचिव अपनी सेवायें पूर्णतः मेरे निर्देशों के आधार पर जारी रख रहे हैं तथा मेरे निर्देशों को विफल करने का कोई भी प्रयास सहन नही किया जायेगा। मैं यह ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात की चिंता थी कि एक निर्दोष तथा ईमानदार अधिकारी को इस प्रक्रिया में गलत ढंग से शिकार बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे यह निर्देश जारी करने पड़े, क्योंकि मेरे सामने यह बहुत बड़ा मुद्दा है। इस सदन ने मुझे सदन की संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करने का विधिवत उत्तरदायित्व प्रदान किया है जो जनता की प्रभुसत्ता का प्रतीक है। मैं इस सदन को तथा उन लोगों को जिन्होंने इस सदन को चुना है, विफल नहीं कर सकता।

अब इस विषय पर अल्पकालिक चर्चा होगी। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे चर्चा के दौरान अपने भाषण में सचिव पद तथा सचिवालय की गरिमा बनाये रखें ताकि सचिव के रूप में श्री प्रसन्ना कुमार कोई क्षति न पहुचें।

मैं पुनः एक बार सबसे यह प्रार्थना कर रहा हूं कि चर्चा बहुत शांतिपूर्वक हो और इसकी चर्चा हम ठीक 4.30 बजे करें। 4.30 बजे हम पुनः मिलेंगे। टी–ब्रेक, धन्यवाद।

RAM NIWAS GOEL

SPEAKER
Legislative Assembly
National Capital Territory of Delhi

Old Secretariat, Delhi-54
Tel: 23890140, 23890150
Fax : 23890375
Camp : Udaipur

Hon'ble Lt. Governor,

My office informed me a while ago that the approval of Lt. Governor, Delhi an order (no 478, dated 29 August, 2016) was issued by the Services Department of the Government of Natioal Capital Territory of Delhi, releving and repatriating Shri Prassana Kumar Suryadevara, Secretary (Legislative Assembly) with effect from 29.08.2018 (A/N).

2. On my specific request, Shri Prasanna Kumar Suryadevara was appointed as Secretary, Legislative Assembly, NCT of Delhi on deputation basis on 17 August, 2015. After a few months, based on my assessment of his performance as outstanding, term of his deputation was extended by two years i.e. up to 16 July 2018. A communication was also sent to Director General, All India Ratio at my behest, to concur with my request for his absorption as Secretary, Legislative Assembly on permanent basis.

3. I have followed up this request with a D.O. letter (no. 4566 dated 18 August, 2016) to Hon'ble Minister of information and Broadcasting, Government of India. Subsequent to that I have received a communication dated 20 July, 2016 (D.O. No. DYCM/2016/5212) from Shri Manish Sisodia, Hon'ble Dy Chief Minister, GNCTD informing me of the reply received from the Directorate General of All India Radio, conveying its inability to concur with my request for Shri Suryadevara's absorption and also asking for his repatriation.

4. In response, I have taken up the matter with Hon'ble Minister of information and Broadcasting, Government of India once again through D.O. letter (No. 4619 dated 29 August, 2016) requesting him to facilitate Shri Suradevara's absorption in Legislative Assembly, NCT of Delhi on permanent basis. I have also brought to the notice of Hon'ble Union Minister the fact the term of deputation of Shri Suryadevara stood extended till 16

July, 2018.

5. In the meanwhile, I have also learnt that Shri Prasanna Kumar Suryadevara, in his 23 years of service so far has spent more than last 12 years (over 50%) cosecutively in the legislative arena out of which over 11 years were spent in the sevice of parliament of India, there by gaining experience and expertise in matters of Legislative functioning. Notably, All India Radio has been managing without his service for last 12+ years without any complaint and has willingly and unconditionally relieved him to join the Legislative Assembly of NCT of Delhi, for which I am thankful to AIR. I am also given to understand that out of a total 230+ posts in his cadre, which is a dying cadre, only 40+ are in service because of a conscious decision taken by AIR nearly 15 years ago to desist from filling vacancies and to run the show with casual assignees. When I reason out the same with Hon'ble Union Minister concerned, I am optimistic that he would accede to my request for Shri Suryadevara's absorption as Secretary, Legislative Assembly on permanent basis.

6. In the meanwhile, unilaterally, the order referred to above in para 1 was issued with out any regard to the Constitutional Office that I am holding. As you are fully aware, the position of Secretary is very crucial for any Legislature. He not only assists the Speaker and the Assembly but also is the Secretary to the Committees of the Legislative which keep functioning throughout the year, even when the House is not in Seassion. The Legislative Assembly of NCT of Delhi has recently resolved to form Special Inquiry Committees to look into alleged irregularities/illegalities levelled against Shri Najeeb Jung. The Special Inquiry Committees and the Petitions Committee, as reported in media, have been examining the feasibility of seeking deposition of Shri Najeeb Jung Committees. For the functioning of these Committees as mandated by the House, it is essential that the Committees receive quality assistance from the Secretariat which is possible only when there is a competent Secretary present and functioning to the full potential and freedom without any interference from any quarter. Moving him out at this juncture, I am afraid, will certainly invite he attention of one and all towards the conflict of interest involved in this exercies.

7. With the respect to the office of Hon'ble Lt. Governor, I take the issurance of the impugned order referred to in para 1 as an affront to the independence and the Consti-

tutionally guaranteed powers of the Legislature. As such, I have directed Shri Prasanna Kumar Suryadevara to continue to discharge his duties as Secretary, Legislative Assembly, who is holding an ex-cadre position which is purely under the control of Speaker, Legislative Assembly. This decision of mine is solely aimed at upholding the Constitution in letter and spirit.

8. I also take this opportunity to suggest that, you as a holder of Constitutional Office, direct those concerned to rescind the impugned order that was issued unilaterally keeping the Speaker in dark, which amounts to contempt of the Speaker and the House, as you have a duty to uphold the Constitution. I am constrained to point out that not doing so amounts to aggravation of unconstitutional act of encroaching into the freedom guaranteed to the Legislature under the Constitutional of India.

9. Since my efforts to speak to you on telephone to resolve this matter did not succeed as you were not available for such a communication and since I am stationed in Udaipur, Rajasthan now, I have no other option but to put on record my serious concern about his grievous injury sought to be inflicted on the Constitutional Scheme, which I afraid, is aimed at making the duly elected Legislature totally defunct.

with regardes,

Yours sincerely

Sd/-
(Ram Niwas Goel)

Shri Najeeb Jung
Hon'ble Lt. Governor
NCT of Delhi
Raj Niwas, Delhi

(सदन की कार्यवाही 4.30 बजे तक टी-ब्रेक हेतु स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 4.40 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय : सुश्री अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–55 के तहत अल्पकालीन चर्चा जिसका विषय है 'जनादेश को विफल करने के उद्देश्य से विधिवत रूप से निर्वाचित विधानसभा को निष्क्रिय बनाने के कथित असंवैधानिक प्रयासों के बारे में।'

अध्यक्ष जी, आज इस सदन में जिसमें हम खड़े हैं, इसे भी कमजोर करने का एक राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि पहला वार जो आया, आपके ऊपर आया। आपके ऊपर पहला वार क्यों आया... और मैं बिल्कुल आपकी हिम्मत की तारीफ करती हूं कि आप इस पूरे सदन को हमेशा ताकत देने का काम करते हैं और आपसे ज्यादा मुझे लगता है विधायक रहने का, विधानसभा कैसे चलती है और जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, मुझे लगता है कि शायद ही उसकी गरिमा आपसे अधिक कोई जानता हो कि किस तरह से संविधान के भीतर रहते हुए इस हाउस को लाने के लिए क्योंकि हम सब विधायक अधिकतर ऐसे हैं जो पहली बार आये हैं। संविधान के मुताबिक ये हाउस कैसे चले, कैसे हम लोग इसमें लोगों की भलाई के लिये विषयों पर चर्चा करके, प्रस्ताव पारित करके जिन्होंने हमें चुना है, हम उनको ताकत दे पायें। ये सब आपसे सीखा है लेकिन पहला वार आपके ऊपर आया, कैसे? क्योंकि आपने दिल्ली विधानसभा में जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा जी को, उनके काम से खुश होकर जिस विभाग से वो आये हैं–प्रसार भारती से, आपने प्रसन्ना जी के बारे में सबसे पहले उन्हें लिखा कि उनका सचिव के तौर पर एक साल का जो

कार्यकाल है, उसमें हम सबने देखा, हमें प्रसन्ना जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि प्रसन्ना जी को जो अनुभव है, प्रसन्ना जी, ठीक है प्रसार भारती आल इंडिया से आए हैं। इनका कैडर जो था, वो न्यूज रीडर का था लेकिन इन्होंने 50 प्रतिशत 23 साल इनकी नौकरी को हो रहे हैं, प्रसन्ना जी की 23 साल की नौकरी... अध्यक्ष जी आप ही ने बताया कि 50 प्रतिशत समय यानि की 12 साल इन्होंने विधायिका को दिये हैं। आपने ही बताया कि पांच साल लोकसभा, छह साल राज्यसभा और एक साल से आप यहां पर दिल्ली विधानसभा में सचिव के पद पर हैं। बारह सालों तक प्रसार भारती को अपने उन अधिकारियों की जो उसने डेपुटेशन पर भेजे, उनकी कभी याद नहीं आई। ये वही प्रसार भारती है जो अभी तक खामोश था लेकिन आपके लैटर के बाद वो खुलासा करने पर मजबूर हो गया। जब आपने कहा कि प्रसन्ना जी का एक साल का डेपुटेशन पूरा हुआ लेकिन उनके अनुभव को देखते हुए इस हाउस को प्रसन्ना जी की जरूरत है, अतः उन्हें दो साल का और एक्सटेंशन दिया जाये। उसके जवाब में प्रसार भारती के हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन सबका एक खुलासा आता है कि प्रसार भारती तो बिल्कुल डूबने के कगार पर है। क्यों डूबने के कगार में है? क्योंकि प्रसार भारती में जिस कैडर से प्रसन्ना जी आते हैं, उसमें 240 उसी कैडर के अधिकारियों की जरूरत है लेकिन आज हैं कितने प्रसार भारती में सिर्फ 40 पूरे देश भर में सिर्फ 40 हैं जब कि होने कितने चाहिये थे 240 बारह साल तक उन्हें अपने अधिकारी की सुध नहीं, उसकी जरूरत महसूस नहीं होती! अगर कैडर 240 का था, 40 पर पहुंच गया तो आपको नियुक्तियां करनी चाहिये थी और वो नियुक्तियां... मुझे अभी तक तो नहीं मालूम था लेकिन मैं अभी चाय पर जब बैठी थी तो सुखबीर दलाल जी के बारे में जानने को पता लगा

कि सर्विस रहती थी तो इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की लड़ाई में शामिल होकर आज विधायक हैं यहां पर। चाय पर जब बैठे थे तो और बारीकियां मुझे जानने को मिली कि इस प्रसार भारती को आज तक सुध नहीं थी कि ये डूब रहा है, ये खत्म हो रहा है। इनके पास इस कैडर के अधिकारियों की कमी है और जब तक प्रसन्ना जी हमारे राज्यसभा में 12 सालों तक थे इनको चिंता नहीं हुई लेकिन एक साल में चिंता क्यों होती है? अब मैं इस पर आती हूं।

अध्यक्ष जी, मेरे पास एक अखबार की कटिंग है असेम्बली 'सैक्रेट्री ज्वाइन हिज पेरेंट ओर्गनाइजेशन' ये अखबार की कटिंग है। ये अखबारों से ही हमें पता लगता है कि इन्हें आदेश हुआ है और उसके बाद ये आदेश कब और कैसे हुआ बड़ा इन्ट्रेस्टिंग है क्योंकि एक नेता विपक्ष हमारे यहां पर बैठे हुए हैं। हमारी तरह वो भी जनता से चुनकर आये हैं। बिल्कुल जनता की आवाज, जनता की समस्याओं को उठाकर उनके हल करने का काम है और ये जनता के लिए नहीं... मैं दावे से कह रही हूं एल. जी. साहब के आंख, नाक और कान बनकर यहां बैठे हुए हैं। ये वहां से ब्रीफिंग लेकर आते हैं, यहां धमकाते हैं और उसका नतीजा होता है, उसका नतीजा होता है...(व्यवधान) गुप्ता जी, सबूत है, गुप्ता जी मेरे पास सबूत है। अध्यक्ष जी, मैं झूठ नहीं, सबूत दे रही हूं। सबूत सदन के पटल पर है। सदन के पटल पर सबूत है कि एल.जी. साहब का यह आदेश जो प्रसन्ना जी को यहां से मुक्त करने को आया है, अध्यक्ष जी, आपके सचिव हैं कि आपके लिये, विधानसभा के लिये काम कर रहे हैं। ये इनकी नियुक्ति आपकी इच्छा से आपके निवेदन पर हुई है...(व्यवधान) लेकिन एल. जी. साहब आज इन्हें हटाने का आदेश देते हैं। किसके कहने पर? नेता विपक्ष के कहने पर। कब और क्यों कहा नेता विपक्ष ने, इसका भी सबूत है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी उनको अपनी बात करने दीजिए, विजेन्द्र जी, उनको अपनी बात करने दीजिये प्लीज। विजेन्द्र जी, उनको अपनी बात करने दीजिये प्लीज। आपने लिखकर दिया हुआ है, बोलने का मौका मांगा है ना। फिर आप डिस्टर्ब करेंगे, फिर जब आप बालेंगे तो वो बोलेंगे बीच में...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, उनको अपनी बात करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कौन सी बकवास? नहीं उन्होंने क्या कहा है?

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो भी कहा है वह...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने आंख, कान, नाक बोला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस चलिये, अलका जी बोलिये।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं ये आरोप यूं ही नहीं लगा रही, क्योंकि प्रसन्ना जी की जो नियुक्ति है, वो स्पीकर का अधिकार है। स्वतंत्रता है कि आप किसी पद पर...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, आप बैठिए। आप बीच में ऐसे बोलेंगे तो आप जब बोलेंगे, दिक्कत हो जायेगी।

...(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बा : सबूत है मेरे पास अध्यक्ष जी, ये सबूत आपको दिखाये जायें।

अध्यक्ष महोदय : बैठिये, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष महोदय, एल. जी. को प्रभावित करके प्रसन्ना जी के खिलाफ आदेश पारित करवा के कि उनको यहां से हटाया जाये। अध्यक्ष जी इंडियन एक्सप्रेस के न्यूजपेपर में 21 जून को प्रसन्ना जी एक आर्टिकल लिख देते हैं जिस आर्टिकल के ऊपर नेता विपक्ष का टवीट है। किस तरह से मीडिया में, टवीट में, अखबारों में जाकर इन्होंने प्रसन्ना जी द्वारा इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल लिखा है, उसके खिलाफ आवाज उठाई और सदन में धमकाया कि आपको इस कुर्सी पर न हीं रहने दूंगा। ये सबूत है कि आज...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, अब ये ऐसे नहीं चलेगा जब आपको समय मिलेगा, आप बोलियेगा ना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिये ठीक है, बैठिये बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, जगदीश जी, ये तरीका ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या बोला? आंख कान नाक बोला ना और क्या बोला उन्होंने? मुझे लगता, मैं खुद रोक देता। कोई असभ्य भाषा नहीं बोली है।

...(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बा : ...(व्यवधान) विजेन्द्र जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ नाम ले रही हूं आपको माफी मांगनी चाहिये जो इस हाउस को आप लानत की बात कर रहे हैं, लानत आप पर है। हाउस को नहीं। इस चुने हुए हाउस को लानत नहीं, लानत आप जैसे लोगों को है जिन्होंने एल. जी. के सामने घुटने टेक दिये हैं!

...(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, जब ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रसन्ना जी का आता है आफिस ऑफ प्राफिट पर, नेता विपक्ष ट्वीट करते हैं, धमकी देते हैं कि इस कुर्सी पर बने रहकर दिखाइये! और उसका नतीजा ये होता है कि आपके लिखने के बावजूद दिल्ली सरकार की सहमति के बाद. ..तब तक प्रसार भारती को कोई आपत्ति नहीं थी। जब प्रसन्ना जी का एक साल का टैन्योर पूरा हो गया, उसके बाद जब दो साल का एक्सटैंशन मांगा गया प्रसार भारती को कतई भी इस बात में कोई आपति नहीं थी। जब प्रसन्ना जी का एक साल का टेन्योर पूरा हो गया, उसक बाद जब दो साल का एक्सटेंशन मांगा या, प्रसार भारती को कतई भी इस बात में कोई आपत्ति नहीं थी और दिल्ली सरकार ने उनसे बात करने के बाद एक्सटेंशन दो साल का दे दिया जो 2018 में पूरा होता है लेकिन इस आर्टिकल के लिखने के बाद 21 जून को...

...(व्यवधान)

श्री बिजेंद्र गुप्ता : [1]××× बोल रहे हैं!

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है विजेन्द्र जी, आप बार-बार बीच में टोंकेंगे नहीं...आप मेरे कमरे में आ जाना, मैं बता दूंगा कि सच क्या है। आप बैठ जाइये, आप आराम से बैठ जाइये अब।...

...(व्यवधान)

श्री बिजेंद्र गुप्ता : [1]××× बोला जा रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :नहीं, आप आराम से बैठ जाइये।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं वो ही कह रही हूं कि ये कारण क्यों है? क्यों प्रसन्ना जी के 12 साल जिस प्रसार भारती को, केंद्र सरकार को याद नहीं आई कि वो एक न्यूज रीडर थे, उनका कॉडर ये है और वहां 240 अधिकारी होने चाहिए थे, 40 रह गए है। उसकी भरपाई आप 200 लोगों की, अधिकारियों की भरपाई प्रसन्ना जी से आज करने लगे है। आपको 12 सालों से प्रसन्ना जी, सचिव की याद नहीं आई। जब एक आर्टिकल लिखा जाता है ऑफिस आफ प्रॉफिट पर, तब उस पर छटपटाहट होती है और एक महीने के बाद 20 जुलाई को प्रसार भारती इन्हें नोटिस भेजता है कि आप इस पर जवाब दीजिए। लेकिन आप देखिए 31.05.2016 का ये लैटर है प्रसन्ना जी को सचिव के पद पर 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिलता है और ऐसा क्या होता है कि सिर्फ जून के बाद 29.08.2016 को?...(व्यवधान)

---

[1] ××× चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन कीकार्यवाही से निकाला गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हमें भी दे दो कॉपी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे से ले लेना। मेरे ऑफिस में आ जाना, दे दूंगा। अब डिस्टर्ब मत करो विजेन्द्र जी। प्लीज। अब उनको बोलने दो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं, मेरे ऑफिस से ले लेना। हां, तो ठीक है, आप ले लेना ऑफिस से।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : दीजिए...

अध्यक्ष महोदय :मैं कह रहा हूं, ऑफिस से ले लेना।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता :आप फेयर डिसक्शन करा रहे हैं दीजिए कॉपी...

अध्यक्ष महोदय :एक सैकेंड विजेन्द्र जी।

...(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, साफ पता लग रहा है, तीर अपने निशाने पर लग रहा है। बिल्कुल दर्द हो रहा है क्योंकि तीर अपने निशाने पर लग रहा है, दर्द होना वाजिब है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, एक सैकेंड। विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र जी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। अलका जी, एक मिनट। मैंने सदन में बयान दिया है कि साल का एक्सटेंशन मिला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो मैं कह रहा हूं ना। मैंने बयान दिया है। मैंने बयान दिया है, उस बयान पर वो बोल रही है, मैंने स्टेटमेंट दिया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बोला है तो दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : किसको? मैं दे दूंगा। आप आ जाइयेगा मेरे पास।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी दिलवा देता हूं। बैठ जाइये।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं वही कह रही हूं। 31.05.2016 को दिल्ली सरकार का एक पत्र है जिसमें प्रसन्ना जी को दो साल का एक्सटेंशन दिया गया और प्रसार भारती से बातचीत हुई लेकिन 29.08.2016 को सिर्फ तीन महीने में ऐसा क्या हो गया कि एल. जी. को हस्तक्षेप करके इस नियुक्ति को, उन्हें यहां से तुरंत हटने के लिए कहा जाता है! उसका और भी कारण है क्योंकि हमारी जो कमेटियां बनी हुई हैं, जांच कमेटियां हैं, बहुत सी इंक्वायरी कमेटियां हैं, जिसमें बहुत सी चीजों में एल. जी. साहब को भी दोषी पाते हुए वो कमेटियां बुलाने का विचार कर रही हैं जो किसी न किसी तरह मीडिया के माधयम से एल. जी. साहब तक, इन सब तक पहुंचा और इन्हें ये लगा कि ये तो नए विधायक चुनकर आए हैं। इन्हें संविधान, कांस्टीट्यूशन, कमेटियों को क्या पावर है, कौन समझा रहा है? फिर वही समझ आई कि ये 12 साल

का एक अनुभव जो लेकर यहां पर आए हैं सचिव, प्रसन्ना जी, ये सब गाईड वो कर रहे हैं। इस हाउस को, इन कमेटियों को कमजोर अगर करना है तो प्रसन्ना जी का यहां से जाना बहुत जरूरी है जिससे इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस जो चल रहे हैं, इन कमेटियों में कमजोर किया जा सके। अध्यक्ष जी, आपने, खुद मैं आप ही के लैटर देख रही हूं, आपने वैंकेया नायडू जी को लैटर लिखा है। आपने एल. जी. साहब को लैटर लिखा है। मैंने वो लैटर बहुत बारीकी और डिटेल से पढ़े हैं। आप ये लैटर नहीं लिखते अध्यक्ष जी, तो शायद मुझे लगता है 7 फरवरी को हमारा वोटिंग था, 6 तारीख को आपकी विधान सभा में भी कुछ आपने बी. जे. पी. के जो आपके खिलाफ उम्मीदवार थे, वहां पर दारू... बांटी जा रही थी, आपने छापा पड़वाया और आपके ऊपर एक साल से वो केस था लेकिन चार्ज शीट कब किया जाता है, जब ये लैटर आप लिखते हैं, ये मैं बताना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, यहां मैं करेक्ट कर रहा हूं ऑफिस जो बना हुआ था अनअथोरइाज-वे में, जो मेरे खिलाफ कैंडीडेट थे, उनका नहीं था। जो मेरी बगल की विधान सभा के थे अतुल गुप्ता जी, उनका मेरी विधान सभा में अनअथोराइज-वे में ऑफिस बना हुआ था।

सुश्री अलका लाम्बा : आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई।

अध्यक्ष महोदय : हां।

सुश्री अलका लाम्बा : और इसलिए आपको आज चार्जशीट किया जाता है एक साल के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा और वो भी कब? जब आप इसके ऊपर सख्ती से प्रसन्ना जी के यहां पर एक ऐसी अधिकारी की सदन में जरूरत को देखते हुए... आपके खिलाफ भी काम शुरू हुआ। मैं यही बता रही हूं

अध्यक्ष जी। आपके लैटर भी मैं पढ़ रही हूं। हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वैंकेयानायडू जी को आपने लैटर लिखा है। उनके लैटर का सिर्फ अभी तक यही आया है कि 18 अगस्त का आपका लैटर प्राप्त हुआ, हम इस पर अभी देख रहे हैं और ये जवाब आपको 24 को मिलता है। आप देख क्या रहे हैं, आपके देखने से पहले ही एल. जी. साहब अपना आदेश सुना चुके हैं। तो मुझे तो कई बार ये लगता है कि एल. जी. साहब अब केंद्र के वैंकेयानायडू, केंद्रीय मंत्री से भी ऊपर हो गए हैं कि उनके आदेश का इंतजार नहीं किया जाता है कि इसमें क्या चल रहा है। उससे पहले ही एल. जी. साहब अपना आदेश दे चुके है। अध्यक्ष जी, ऐसी बहुत सी बातें हैं कि इस हाउस को कमजोर करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मैं कहूंगी बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से मैं आपके सामने कहना चाहूंगी कि हमें मालूम है प्रसन्ना जी यहां पर जब बैठे हैं तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूं कि इतने दबाव के बावजूद भी आप अपनी ड्यूटी को कैसे ईमानदारी से यहां पर निभा पा रहे हैं। कितना दबाव है, आपको शो काज नोटिस भेजे जा रहे हैं, ये हमें अखबारों से ही पता लगता है और अखबारों में जब आया अध्यक्ष जी, कि प्रसन्ना जी को शो काज नोटिस भेजा गया है कि इनकी नौकरी तक को खतरा है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इनका कैरियर बर्बाद कर दिया जाएगा तो ऐसा जब अखबारों में आता है तो हमने प्रसन्ना जी को वैसे ही व्यक्तिगत फोन करके पूछा कि ऐसा अखबार में आया है तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा कोई भी शो काज नोटिस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये अखबारों में कैसे आ गया जब कि कर्सन्ड पर्सन को अभी तक प्रसार भारती ने नहीं दिया तो ये अखबारों में कैसे आया! फिर मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो पता लगा नेता, विपक्ष का ही ये काम है। ये जो नोटिस है जो प्रसन्ना जी तक प्रसार

भारती से नहीं पहुंचता, पर प्रसार भारती से नेता, विपक्ष क्योंकि अपनी सरकार है, अपना मंत्रालय है, निकाल कर लाकर मीडिया को पहले थमा देते हैं। मैं जब भी इन सब चीजों की... क्योंकि ये आरोप पहली बार नहीं लग रहा नेता, विपक्ष पर कि जो बात सदन के सामने आए या कमेटियों के सामने आए या आदेश जो पारित होते हैं एल. जी. हाउस से, वो नेता, विपक्ष के पास पहले पहुंचते हैं और हम लोगों के पास बाद में पहुंचते हैं। तो मैं यहीं कहूंगी कि पूरा सदन अध्यक्ष जी, आपको पूरे तरीके से ताकत देने का काम करेगा। जहां आप कहेंगे हम, सदन आपके साथ आवाज से आवाज मिलाएंगे, आपको ताकत देंगे ताकि आप ये एक ईमानदार, मेहनती, अनुभवी अधिकारी हमारे सामने जो प्रसन्ना जी बैठे हुए हैं, जिससे इस हाउस को पिछले एक साल में बहुत लाभ पहुंचा है, उन्हें आप किसी तरह भी, यहां पर इस हाउस की जरूरत के मुताबिक उन्हें आप बनाए रखें और मैं बिल्कुल कहुंगी कि इस तरह की राजनीति, मै फिर कह रही हूं, ये सब सबूत हैं कि किस तरीके से एल. जी. हाउस का, मैं कहूंगी नेता, विपक्ष इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी कागज आता है, हमें मालूम है इस हाउस में आने से पहले वो एल. जी. हाउस में जाते हैं। वहां से ब्रीफिंग लेते हें, रिपोर्ट लेते हैं और यहां पर आकर वो कागज लहराने लग जाते हैं जिन कागजों की खबर हमारे पास नहीं होती...

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करें अलका जी, प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बा : स्पीकर साहब, हम आपके साथ, प्रसन्ना जी के साथ खड़े हैं और श्री वैंकेया नायडू जी, सूचना प्रसारण मंत्री से हम लोग निवेदन करते हैं इस हाउस की तरफ से कि इस हाउस की जरूरत है, दिल्ली विधान सभा के सचिव इसी पद पर बनाए रखना जाना चाहिए, न कि किसी

राजनीति हथकंडे का इस्तेमाल करते हुए इस हाउस को कमजोर करने का कोई भी प्रयास करें, जय हिंद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : थैंक्यू अध्यक्ष महोदय, आपने इस बहुत ही इंपोर्टेंट विषय पर बोलने का मौका दिया। अलका जी ने अधिकांश बातें तो कही, बहुत सारे फैक्टस उन्होंने सामने रखे, पर कुछ चीजें जो महसूस होती हैं, जो फीलिंग्स हैं और सदन की जो फीलिंग है और बाकी सारे सदस्यों की जो फीलिंग है, साथ में उनको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब असेम्बली का सदन चल रहा था, उस वक्त आपने प्रसन्ना जी से कुछ बात पूछी उन्होंने ऊपर उठकर जाकर आपको उस बात का जवाब दिया जिस पर कि भारी विरोध किया नेता, विपक्ष ने। मैं आपको सुबह से कह रहा हूं कि ये सज्जन, नेता, विपक्ष होने के लायक नहीं हैं। ये मैं आप ही से कह रहा हूं इसलिए कोई और बीच में न बोले। ये इस लायक नहीं है कि नेता, विपक्ष रहें लेकिन फिर भी हैं तो झेलना पड़ेगा! अध्यक्ष महोदय, ये बीच में बोलते हैं, हंसते हैं, सदन का समय खराब करते हैं। ये एक मसखरे बनकर रह चुके हैं। ये कोमेडियन बन गए हैं यहां पर आज की तारीख में। ठीक है, ऐसा लगता है सिर्फ एंटरटेंमेंट के लिए हैं और वो भी हमारे एंटरटेंमेंट के लिए आ रहे हैं। एनी वे! तो इन्होंने उस वक्त भारी विरोध दर्ज किया और चिल्लाए और असंवैधानिक कहा इस बात को कि आप अपने सचिव से कुछ पूछते हैं और वो ऊपर आकर आपको कुछ बताते हैं कि नहीं, ये अनकॉंस्टिट्यूशनल है। ये हुआ और 2 दिन बाद पता चला कि एल. जी. साहब ने कहा, 'वापस चले जाओ प्रसन्ना जी। आपकी यहां पर कोई

जरूरत नहीं है।' तो मैं तो बहुत सीरियसली लेने लगा। उसके बाद से तो धमकियों को सीरियसली लेने लगा। एक दिन इन्होंने कहा था कि पूरे के पूरे सदन को बर्खास्त कर देना चाहिए... भंग करवा देंगे ये। आज इन्होंने सत्येंद्र जी को कहा, आप अपना ख्याल रखो। सर, ये बड़ा सीरियस इश्यू है। इंसटैंटली चीज जब उठकर के आती है रेपर्कसन दिखाई देने लगता है। तो सर, हम ये कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप पूरे सदन को चला रहे हैं, हमें गर्व है इस बात का कि आपके जैसे सदन के अध्यक्ष हैं और हम ऐसे समय पर विधायक हैं जब आपके जैसे अध्यक्ष हैं। और एक ये है, जिन्हें गर्व ही नहीं है, घमंड है इस बात का कि केंद्र में वे लोग बैठे हुए हैं। हम तीन ही रह गये तो क्या हुआ! सभा तो अपने हिसाब से ही चलवायेंगे। जिसे चाहेंगे, उसे रखेंगे। जिसे चाहेंगे, उसे भगाएंगे। ये पूरा का पूरा जो लेजिस्लेचर है, इसे डॉयल्यूट करेंगे। दिल्ली सरकार इसको डॉयल्यूट करेंगे। ये जीत गए तो क्या हुआ, उसके बावजूद काम नहीं करने देंगे। हम एम.सी.डी. से कहेंगे कि किसी भी तरीके से विधायकों को कोआपरेट ना करें, किसी तरीके से उनका फंड ना लग जाए, किसी भी तरीके से कोई सा भी मंत्री काम न कर पाए। मंत्री आज की तारीख में अपने सारे शैडॅयूल चेंज करते हैं, सारी मीटिंग्स कैंसिल हो जाती हें क्योंकि उनके जो सचिव है, वो फाइलें बनाने में लगे हुए हैं जो एल. जी. साहब ने मंगाई हैं, जो काम पूरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए हो रहे हैं, दिल्ली की प्रौग्रेस के लिए हो रहे हैं, दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए हो रहे हैं, हर चीज की फाइल मंगवा के रख ली गई है, 6 महीने तक रखी रहेगी, बना लो पीडब्ल्यूडी की सड़कें, बना लो तुम स्कूल। बना के दिखाओ। तुम्हारे बस की है, तुम हैल्थ अच्छी करके दिखा दो। कुछ नहीं करने देंगे। इसी तरीके से अगर हम सदन में हम लोग अपने

क्षेत्र के काम लेकर आते हैं, क्षेत्र की समस्या लेकर आते हैं, उनका डिस्कशन करना चाहते हैं, उन बातों को उठाना चाहते हैं, हर बार सदन एक घंटा लेट शरू होता है सिर्फ क्योंकि एक आदमी सदन को नहीं चलने देता। अपने हिसाब से सदन को चलाना चाहता है और उसके बाद पावर किसकी है? पावर केंद्र से मिली हुई है जो इस विधान सभा में आकर खत्म हो जाती है। उनको भी इस बात को रियलाइज करना चाहिए, जनता ने उनको भी चुना है। वो यहां पर आके ऐसे नहीं बैठ गये कि किसी ने उठा के भेज दिया, हो सकता है कि टिकट के टाइम पर पैसे खर्च हुए हों, पर उसके बाद तो जनता ने वोट दी है। जनता का अगर आप नेतृत्व करते हैं, आप कभी-कभी रोहिणी की बात भी उठा लिया कीजिए। जगदीश प्रधान जी उठाते हैं, अपने क्षेत्र की बात उठाते हैं। मैं तो आपसे कहूंगा कि जगदीश प्रधान जी को नेता, विपक्ष बना दीजिए। लेकिन अगेन कहूंगा ऐसा भी हो सकता है। देखिए! जैसी इनकी हरकतें आजकल हैं, मैं तो कहूंगा ओम प्रकाश शर्मा जी को भी एक बार को बना दीजिए। बस, इन्हें रहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : चलिए कन्क्लूडए करिए अब प्लीज। वक्ता बहुत ज्यादा हैं।

श्री नितिन त्यागी : अच्छे से सदन आप चला रहे हैं, प्रसन्ना जी की गाइडैंस में, प्रसन्ना जी की एडवाइस से, प्रसन्ना जी के असिस्टैंस के साथ ये सदन बहुत अच्छा चल रहा है। किसी भी तरीके से इस सदन की गरिमा में, इस सदन के कार्य में जैसा की एम.सी.डी. में बी.जे.पी. है और एन्क्रोचमैंट इनका कल्चर है, इसकी पावर में एंक्रोच करने की कोशिश न करें किसी भी तरीके से धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने विस्तृत जानकारी दी कि वाकया क्या हुआ, प्रसन्ना जी के साथ...आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि 1947 में हम आजाद हुए, 26 जनवरी, 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान सौंपा और हम सबने इस देश का प्रजातंत्र कैसा हो, जनतंत्र कैसा होगा, बाबा साहेब के संविधान के जरिये हमने एक सपना बुना एक जनप्रतिनिधि जनता चुनेगी, सदन होगा, सदन के जरिए जनता की आवाज उठाई जाएगी और सदन सर्वोच्च होगा क्योंकि संविधान में सबसे ऊपर जनता है, सदन को ये अधिकार है चाहे कोई सरकार हो, मंत्री हो या कार्यपालिका का कोई भी अंग है, सदन के प्रति जिम्मेदार होगा, सदन में आकर उसको हिसाब-किताब देना पड़ेगा। लेकिन जो वाकया हुआ, ये वाकया आपने आप में, पूरी डैमोक्रेसी सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है! मुझे ऐसा लगता है कि ये बात केवल विधान सभा सचिव की नहीं है, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि इस सदन में, सदन के सदस्य सवाल उठाते हैं, ज्योंही सदन में सवाल उठाया जाता है, बाहर में उनको एकनोटिस दे दिया जाता है कभी एल. जी. साहब से नोटस आता है, कभी पुलिस का नोटिस आ जाता है। तो ये सदन में जनता की बात मजबूती से उठाएं और उसकी कार्रवाई बाहर में किया जाता है, डराया-धमकाया जाता है। तो लगता है कि सदन को ओवर पॉवर करने की कोशिश की जा रही है। मुझे गर्व है आप जिस तरीक से इस सदन को चला रहे हैं, जिस तरीके से अभी आपने आवाज उठायी, जिस तरीके से एक तरह से एल. जी. साहब को समझाया कि सबका अपना अधिकार क्षेत्र है और हर एक आदमी अपने अधिकार क्षेत्र में रहे, एल. जी. साहब सरकार के मुखिया हो सकते हैं, सदन के मुखिया नहीं हो सकते। ये सदन, जब जनता हमें यहां

भेजती है तो जनता के सपनों के मंदिर में हम लोग बैठते हैं। जनता के विश्वास की अट्टालिका है ये। इस सदन में आकर के हम जनता के एक-एक दर्द को यहां रख करके सरकार को समझाते हैं कि वास्तव में कार्यपालिका हो या सरकार, जनता के लिए कैसे काम करना चाहिए तो ऐसे में अगर सदन को इस तरह से कमजोर किया जाएगा, अगर इस तरह से सदन को मजबूर किया जाएगा तो फिर जनता के सपनों को हम पूरा नहीं कर सकते। जनता के विश्वास में हम खरे नहीं उतर सकते। आपने बताया कि विधान सभा सचिव के साथ जिस तरह का वाकया हुआ, मैं देख रहा था इनका टैन्योर, 1993 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया था, 2004 में लोकसभा में और राज्यसभा में 10 साल इनका टैन्योर रहा, उसके बाद एक साल हम लोगों के साथ रहे। एक व्यक्ति अपने जीवन का अपने प्रोफैशनल लाईफ के 12 साल लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, लेजिस्लेचर में अपना समय बिताता है, उसमें अनुभव प्राप्त होता है और उसके बाद अचानक केंद्र सरकार को या यहां बैठे विपक्ष के साथियों को डर लगने लगता है। अगर हम गलत करेंगे तो चूंकि जिस तरीके से प्रसन्ना जी ने पिछले एक साल में काम किया है, तमाम तरह की कमेटियों को बनाकर के सरकार के काम काज में मदद करने की कोशिश की है और विधान सभा में जनता के सवालों को, जनता की बातों को सदन के जरिये समाधान हो पाए, इन्होंने बहुत सारे प्रयास किये हैं। तो जब क ये ऐसे काम करने लगे तो डर लगने लगने लगा! अभी अलका जी बता रही थी, नितिन भाई बता रहे थे कि ये हुआ क्यों और कैसे हुआ और जब अलका जी बता रही थी, नितिन भाई बता रहे थे कि ये हुआ क्यों और कैसे हुआ और जब अलका जी ने बात उठाई तो विजेन्द्र जी को दर्द होने लगा। हम सबको पता है कि ये वाकया हुआ कैसे, उसकी डिटेल में अगर जायें कि आप कहां-कहां

गए, किस-किस से बात की, कौन से आका से मिले और फिर कैसे नोटिस आया? ये सबको जानकारी है लेकिन मेरा ये कहना है कि इस सदन में आपको भी कहीं की जनता ने चुनकर भेजा है। अगर सदन को कमजोर करने की कोशिश आप करते हैं तो आप जनतंत्र के मंदिर में आकर के जनतंत्र को धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपसे एक हम्बल सब्मिशन है कि सरकार एक ऐसा बिल लेकर आये जिसमें कम से कम विधान सभा में काम करने वाले लोग किसी सरकार से ना आयें। ये इंडिपेंडेंट विधान सभा में ही रहें ताकि विधान सभा के काम काज ठीक से हो पायें और कल को, कोई किसी को डरा नहीं पाये। चूंकि मान लीजिये कोई आईएएस आ गया, आज हम यहां पर सैक्रेटरी को बुलाते हैं, कोई दानिक्स अफसर है तो पहले ही धमका देता है उसको, मुझे तुम मत बुलाना, मुझे बुलाओगे तो बाद में देख लूंगा मैं, या जो आज इनके साथ हुआ है कि आज ऑल इंडिया रेडियो में जितने भी न्यूज रिडर है वो कांट्रेक्ट पर रखे जाते हैं। 2010 से कोई बहाली नहीं हुई है वहां, सारे इम्पलाई कांट्रेक्ट पर रखे जाते हैं। प्रसन्ना जी का 13 साल से लेजिस्लेशन में कार्य का अनुभव रहा है लेकिन कहा जाता है कि न्यूज रीडर की जरूरत है, आप वहां आइये। अरे! बदले में... अगर जरूरत है भी तो आप... अभी मैं देख रहा हूं 40 रीडर सरकारी हैं, बाकी सारे कान्ट्रेक्ट पर आए हुए लोग हैं, तो एक और रख लो। लेकिन मसला केवल ये नहीं है कि इनकी जरूरत है, मसला ये है कि एक आदमी कोई अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसको डराओ, उसको धमकाओ और उसको मजबूर कर दो कि वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाए।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री संजीव झा : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि आपके जरिए सरकार के वे मंत्री हैं यहां, उप-मुख्यमंत्री हैं यहां कि ये सदन एक बिल लेकर आए जिसमें ये पुख्ता व्यवस्था की जाए कि विधान सभा में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो लोग विधान सभा के लिए जिम्मेदार हों, वो सरकार से या डेपुटेशन से बाहर से कहीं न लाए जाएं और अंतिम बात जिस तरह से आपने हालांकि चिट्ठी एल. जी. साहब को लिख दिया है पर ये सदन एक डिटेल उनको जानकारी दे दे कि उनकी सीमा क्या है। ये डेढ़ करोड़ जनता के सपनों के मंदिर में बैठे हुए लोगों को इस तरह से चुनौती और नोटिस नहीं भेज सकते। इसलिए उनके अपने अधिकार क्षेत्र की उनकी अपनी हैसियत को लिखकर के बता दिया जाए कि ये जो विधान सभा है, ये जो विधायिका है, उनमें उनकी हैसियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि यहां इस तरह से चिट्ठी लिखकर के यहां के अधिकारी को, विधायका को या अध्यक्ष को सवाल करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सौरभ भारद्वाज जी। जरा संक्षेप में रखे सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाज : बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी जो आपने मौका दिया। मेरा ये मानना है कि ये जो मसला जो आज हमारे बीच में है, ये प्रसन्ना जी का मसला नहीं है। न ही हमारे अध्यक्ष रामनिवास गोयल का मसला है न ही विजेन्द्र गुप्ताजी का मसला है। ये मसला सदन की Sovereignity का है। सदन की कितनी पावर्स हैं, कितने अधिकार हैं, यहां पर और लैजिस्लेटिव की सुपरमेसी का मसला है। जब इस देश के अंदर प्रजातंत्र स्थापित हुआ ओर हमारा संविधान बना तो इस चीज का ध्यान रखा कि लैजिस्लेटिव की और लैजिस्लेचर की एक सुपरमेसी है और मैं मानता हूं कि एल. जी. साहब एक

मुगालते में हैं। 4 अगस्त को जो दिल्ली हाईकोर्अ का जजमेंट आया है, उससे उनको ऐसे लगता है कि वो दिल्ली सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उस फैसले को देखा जाए तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो दिल्ली सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर है और जो कन्फ्यूजन यहां पर हो रही है कि जो ये सदन है, ये जो विधान सभा है; ये दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। ये दिल्ली सरकार के ऊपर है। सबसे ऊपर जनता है। जनता ने इस विधान सभा को चुना है और इस विधान सभा के अंदर सरकार बनाई जाती है। तो जो विधान सभा है, इस सरकार के ऊपर है, हैरारकी में देखा जाए तो। तो अगर एल. जी. साहब इस सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर हैं भी हालांकि ये भी एक सब-ज्यूडिस्ड मैटर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मगर अगर एल.जी. सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो भी एल. जी. साहब किसी भी कीमत पर इस विधान सभा के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस सदन के, विधान सभा के एडमिनिस्ट्रेटर एल. जी. साहब हैं और इस लिए मुझे लगता है कि जो स्पीकर साहब ने एल. जी. साहब को वापिस जो चिट्ठी लिखी पूरे सदन की तरफ से, मुझे लगता है कि स्पीकर साहब को बधाई देनी चाहिए कि इन्होंने इस पूरे सदन की पॉवर, को, इसकी सुपरमेसी को बचाने के लिए एल. जी. साहब को वो चिट्ठी लिखी। मेरे दोस्त नितिन भाई कह रहे थे कि विजेन्द्र गुप्ता जी बहुत नाराज रहते हैं हमारे से और वो कह रहे थे कि जगदीश जी को मौका दिया जाए। वैसे आज जगदीश जी का कुर्ता आपसे ज्यादा चमक भी रहा है। देखो, तैयारी तो जगदीश जी ने कर दी है और हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं तो मेरी तरफ से यही बात है... तो हम सब जगदीश जी के साथ है इस चीज के लिए।

तो स्पीकर साहब इस चीज के अंदर सीरियसनेस के लिए दोबारा लौटते हुए मेरी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि ये जो मसला है, ये पूरे हाउस की sovereignty सोवरनिटी का मसला है और इसको हम सब लोग बहुत सीरियसली लें और आप इसमें जो भी फैसला लेते हैं, ये पूरे का पूरा सदन आपके साथ है और जहां चलना होगा, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : कैलश गहलात जी।

श्री कैलाश गहलोत : स्पीकर सर, सबसे पहले धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सर जो फैक्चुअल पोजिशन है, वो आलरेडी आपके सामने आ चुकी है। पूरे सदन के सामने आ चुकी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो मीडिया के थ्रू, अभी तक जो सैक्रेट हैं, इस सदन के उनको अभी तक ऑल इंडिया रेडियो से कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है और ये चीज मैंने कन्फर्म की सैक्रेटी से कि उनको आज तक कोई भी नोटिस ऑल इंडिया रेडियो से रिसीव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि ये मीडिया को रिपोर्ट मिल रही है! ये कहां से मिल रही है? मुझे कतई भी संकोच नहीं है कहने में कि पहले भी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि कहीं उंगली खड़ी होती है विजेन्द्र गुप्ता जी पर कि ये इस सदन के ऑनरेबल मेम्बर होने के बावजूद एक एजेंट का काम भी कर रहे हैं और जो मीडिया से सर, रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसमें सैक्रेट्री के बारे में लिखा कि सैक्रेट्री जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हें इस सदन में कि अनऑथ्राइज्ड एब्सेंस इतने स्ट्रॉग वर्डस एक आफिसर के बारे में जो स्पीकर के अंडर काम कर रहे हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल

ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। जिनकी हम सबके सामने एक यहां ऑथराइज्ड प्रेजेंस है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अनऑथराइज्ड एब्सेन्स है। सर मेरे ख्याल से I do not think that this is a simple case of unauthorized absence. I think, this is a very serious attack on the fundamental principle of separation of power. और जब हम separation of powers की बात करते हैं हमारे जितने, अलका लाम्बा जी से लेकर नितिन भाई, सौरभ जी, सजीव झा ने बार-बार कहा कि ये सदन सरकार हिस्सा नहीं है। We are talking about a very important principle of state governance which is embodied in separation of powers और जब सर हम हम सैपरेशन ऑफ पॉवर्स की बात करते हैं तो We are not talking about 21st century, this goes back to 18th century. Separation of powers के बारे में कहा है कि स्टेट को कैसे गवर्न किया जाए ताकि कोई भी इंस्टीट्यूशन इतना सैंट्रलाइज्ड न हो कि सारी पॉवर उसमें केंद्रित हो जाएं और ये स्टेट सैपरेशन ऑफ पॉवर्स का आइडिया Philosopher Montesce उसके पास 1787 में यूथ यूनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका अपने संविधान में इसको लागू किया और जब हम अपने देश की बात करते हैं तो सैपरेशन ऑफ पॉवर्स के बारे में judicial pronouncements right from गोकुलनाथ केस से लेकर राजनारायण केस में केशवानन्द भारती ने तो यह कहा कि सैपरेशन ऑफ पॉवर्स, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्सिट्यूशन का। इसको आप छीन नहीं सकते। इसको कोर्ट भी अगर छीनना चाहे तो छीन नहीं सकती। तो सर, I am really surprised to see such remakrs from a Govt. institution regarding and officer who is working in the Assembly and performing contitutional duties.

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री कैलाश गहलौत : Thank you so much sir.

अधधक्ष महोदय : सोमनाथ भारती जी। लंबा नहीं करिएगा, शार्ट रखिएगा। सीरियस, सदन को थोड़ा हंसी आ गई।

श्री सोमनाथ भारती : Hon'ble Speaker, Sir, I am very grateful to you for giving me this opportunity. आज जब गुप्ता जी बार-बार हंस रहे थे या कुछ कर रहे थे सदन में तो मुझे ख्याल आ रहा था कि एक मंदिर है सिविल लाइंस पे। वहां एक मौलवी जी रहते हैं। उस मौलवी से जा के रोजाना ये ब्रीफिंग लेते हैं कि करना क्या है? आज सदन में कब खड़े होना है, कब बैठना है? आप बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 21 लाइन के बाद ये क्या बोलने वाले हैं। बिल्कुल एक एग्जेक्ट ब्रीफिंग लेके आते हैं और उस ब्रीफिंग के अनुसार इनका सारा चाल चलन यहां पर होता है। तो ये किसी के हाथ में कठपुतली हैं और उस कठपुतली बनने का कारण न तो अपनी जनता को सर्व कर पा रहे हैं और न दिल्ली की जनता को जवाब दे पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज जो इस इश्यू पर जो चर्चा चल रही है सदन के अंदर It's a very serious matter. The Contitution of India talks about division of powers among Judiciary, Exectuive and the Legislature and over reach of any one of the three units to the other has to be seriously looked after.

अध्यक्ष महोदय, आपको सदन को भी याद होगा कुछ समय पहले भारत

के माननीय मुख्य न्यायधीश ने ये बात बार-बार कही कि किस तरह से एक्जीक्यूटिव पावर्स को यूज करके सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स के भी पावर्स को कटिंग करने का प्रयास ये सरकार करती रही है। हर जगह जो सैपरेशन ऑफ पॉवर्स की बात कैलाश भाई ने भी कही कि This is a sanctified affaire by the Constitution and the Constitution has not been given by abybody lesser than Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar who was, you can say, intellectually disigned, the way he drafted the Constitution, the way he talked about separation of powers, the way he talked about saving one wing by the other wing, it is something which all of us have to be seriously looking into it.

अध्यक्ष महोदय, Execytive overreach into the legislature affair. का जो ये उदाहरण प्रस्तुत हुआ है सौरभ ने बड़े अच्छे से बात कही कि ये मामला सेक्रेटरी महोदय का नहीं है, ये मामला स्पीकर महोदय का नहीं है। ये मामला एक बहुत सीरियस अफेयर्स की तरफ इशारा करता है कि किस तरह से ये सरकार विक्टोरियल तरीके से सब कुछ में जूडिशियरी में हो, लेजिसलेचर में हो, हर तरफ इसके बारे में चर्चा है कि किस तरह से पूरी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को, लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग को, जूडिशियरी की फंक्शनिंग को 24 घंटे डर लगा रहता है कि कब माननीय मोदी जी की तरफ से कोई चाल चल दी जाए जिससे हमारी फंक्शनिंग को खतरा पहुंच जाए! जब ये बात मुझे मालूम पड़ा, चूंकि उस वक्त मैं प्रिविलेज कमेटी के टूर पर था और वहां के लोग अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन के साथ शेयर करना चाहता हूं कि शायद हम उन राज्यों में न पहुंचे हों प्रिविलेज कमेटी की टूर थी 3 राज्यों के अंदर हमारे 7 सदस्य यहां मौजूद हैं, हम वेस्ट बंगाल गए थे, मणिपुर गए थे, मिजोरम गए थे। मिजोरम

जैसे इलाके के अंदर जहां तक हम अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं वहां पर एंड आई एम प्राउड ऑफ इट टु से करीब–करीब 100 परसेंट लोगों ने आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल साहब की जो लाइकिंग दिखाई, उससे हम सबको गौरवान्वित महसूस हुआ और मालूम पड़ा कि माननीय एल. जी. महोदय ने चूंकि हम सब, जैसा कि अलका जी ने कहा प्रसन्ना जी के अनुभव से हम सबको बहुत ही फायदा पहुंचा है। चाहे वो सदन की प्रोसिडिंग को समझने की बात हो और इत्मीनान से समझने की बात हो। मुझे लगता है कि जो अटेम्प्ट है, माननीय एल. जी. महोदय का और माननीय एल. जी. महोदय तो कठपुतली हैं। एल. जी. महोदय एक भी क्षण मोदी जी के बगैर कुछ कर दें तो अपनी सीट बचा नहीं पायेंगे। तो एल. जी. महोदय की जो ये करनी है, ये करनी एल. जी. महोदय की नहीं है, ये करनी मोदी महोदय की है। अध्यक्ष महोदय, आज पूरा सदन आपके साथ खड़ा है क्योंकि आज हम विधायक हैं। आज इस तरह से एल. जी. महोदय के जरिए दिल्ली के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है! यही भाजपा, यही कांग्रेस कहती थी कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आज क्या हो गया भई! आज आम आदमी पार्टी शासन में है। आज हम विधायक हैं। कल कोई भी हो सकता है। तो आपको दुश्मनी दिल्ली से है या दुश्मनी आम आदमी पार्टी से है? जिस तरह से आज सदन में सवेरे चर्चा की माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेके। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह सदन चर्चा करता है; किस पे? उन कारणों पे जिन कारणों से मोदी महोदय हमें काम नही करने दे रहे। हम किन कारणों से चुन के आए थे, जो हम करने आए थे, उसपे हम सिर्फ 10 परसेंट टाइम व्यतीत कर पा रहे हैं! फिर कहते हैं कि दिल्ली में काम नहीं हो रहा है। इनके लाख कोशिशों के बावजूद बहुत सारा काम हो रहा है जो कि ये 5 साल के अंदर भी पूरा न कर पाए।

अध्यक्ष महोदय : कनक्लूड करिए सोमनाथ जी अब प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : इन द सेंस ऑफ दि हाउस, चूंकि हम सबने गहरे मन से इस बात को बताया है, इस बात को सदन के आगे रखा है कि जो एक्जीक्यूटिव ओवररिच है, एल. जी. महोदय के जरिए इसे संवैधानिक थंब-लॉ की तरह देखा जाना चाहिए Today, the Constitution of the nation is in danger. ये संविधान जो लेजिस्लेचर को बिल्कुल अलग रखता है। माननीय स्पीकर महोदय, आपकी जूरिस्डिक्शन है कि सेक्रेटरी महोदय का इतना कार्यकाल होना चाहिए, उनका कार्यकाल बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। बगैर किसी कारणों से for no rhyme or reason order has been passed by Hon'ble LG without consulting you. This is a direct threat to the Constitutional framework of this nation and this must not be tolerable. अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दे तो सेन्स ऑफ द हाउस को समझते हुए एक रेजल्यूशन मूव करना चाहता हूं if I have your permission, then I can move. अध्यक्ष महोदय, The Legislative Assembly of NCT of Delhi having its sitting in Delhi on 9th of September, 2016, this is the resolution which I have to move :

Noting the fact that the services of Shri Prasanna Kumar suryadevara as Secretary of Legislative abbembly are secured by Hon'ble speaker and that the term of deption of Shri Suryadevara as secretary, Legislative Assembly is valid till 16th of July, 2018.

Further, noting the fact that Shri Suryadevara has gained exsperiences and exsperites in the matters of legislative functioning through his service of more than twelve years in the legislative arean including over eleven years that he spent in the services of Parliament of India out of a total of 23 years of services he has put in so far;

Also noting the fact that the request of the Hon'ble Speaker for concurrence for absorption of Shri prasana Kumar Suryadevara as

Secretary of Legislative Assembly of NCT of Delhi on permanent basis was duly conveyed to the Directorate General of All India Radio;

Placing on record sincere appreciation of the outstanding services being rendered by Shri Prasana Kumar Suryadevara which resulted in streamlining of the fuctioning of the Legislative Assembly and its Secretraiat in various spheres;

Condemning in strongest possible terms that the efforts of the administrator of NCT of Delhi which is LG to scuttle the functioning of duly elected Legislative Assembly by way of unilaterally issuingan illegal, unconsititutioal and untenable order suggesting that Shri Prasanna Kumar Suryadevara is relieved as Secretary, Legislative Assembly;

Vewing seriously the transgression on the part of the Administaror of NCT of Delhi in venturing into the legislative arena which is constitutioally under the sole custody of the Speaker arena which is constitutionally under the sole custody of the Speaker of the Assembly;

Expressing grave concern at the fact that the Administrator who is also the Lt. Governor who is holding a Constitutional Office, perpetuated the breach of 'Laxman Rekha' by way of assualting the very independence of the Legislature guratanteed under the constitution;

Treating the intrusion of the Administrator into the matters of legislative functioing as a serious affront to the authority of the Speaker and the sovereign rights of the people of Delhi who have elected the Legislative Assembly;

Warning the Administrator of desist from such autocratic, undemocratic and unconstitutional moves in future: And lauding the Mfirmness displayed by the Hon'ble Speaker in scuttling the designs of the Administrator to make the Assembly defunct by standing up to the untenable orders of the Administrator;

Resolves to stand by the directions issued by Hon'ble Speaker to all concerned that Shri Prasanna Kumar Suryadevaa shall continue to discharge his duties as Secretary, Legislative Assembly, NCT of Delhi notwithstanding and order issued or to be issued from any quarter that runs contrary to the Speaker's dirctions;

Further resolves that any move in any quarter that results in any violation either directly or indirectly of Hon'ble Speaker's directions in relation to the position of secretary, Legtislative Assembly and the functioning of the Secretariat be treated as serious breach of Privilege of the Legislative Assembly and as such necessary proceedings be initiated forthwith against those who cause such a breach and requests Hon'ble Speaker to take all necessary steps to secure the services of Shir Prasanna Kumar suryadevara for absorption as secretary, Legislative Assembly on permanent basis in the long term interests of the institution."

This is the detailed reslution I wish to move Hon'ble Speaker, Sir which, in a manner, encompasses every sense which the house has

expressed so far and this is for you to consider and for the House to vote on it. Thank you.

Sh. Saurabh Bhardwaj : Hon'ble Speaker, Sir, I Second the resoulution moved by Mr. Som Nath Bharti.

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं अपने साथियों का दर्द समझ सकता हूं क्योंकि इस सदन में सामान्यत: झूठ फैलाया जाता है और जब विपक्ष...(व्यवधान)। एक मिनट, आप बैठिए। मुझे मालूम था। मुझे बोलने नहीं दिया जायेगा।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जो भी मैं कह रहा हूं। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं तथ्य रखकर यहां कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप भाषा को, आप अपनी, अगर वो आंख, कान और नाक बोलते हैं। आपको परेशानी होती है। आप जो मर्जी आप बोल रहे हो। वो आंख, नाक और कान बोलते हैं तो परेशानी होती है आपको। नहीं, देखिए, आप जो मर्जी बोल रहे हैं सदन में। नहीं उसको छूट मिलनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं ये चाहूंगा कि आप सबको बिठायें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप अपनी भाषा को सुधारिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो यहां हो रहा है और पूरे सदन को गुमराह किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पर विपक्ष को अपनी बात कहने का शांति से समय दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, विजेन्द्र जी मेरी बात, सोमनाथ जी, दो मिनट बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए। देखिए विजेन्द्र जी, मेरा ये कहना है। बैठिए, बैठिए। मेरा ये कहना है। अगर आंख, नाक, कान बोला तो आपको परेशानी हुई और आप जो मर्जी आये बोल जायें और वो न उठें। फिर आपको परेशानी होती है!

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप मुझे मौका दीजिए अपनी बात कहने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : तो आप अपनी बात को कायदे से रखिए न। शब्दों में कहिए न।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सदन में स्पीकर, सेक्रेटरी, सदस्य सबकी एक भाषा होगी। विपक्ष को कहीं तो मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये सदन अगर इतना बायस्ड हो जायेगा!

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सदन की गरिमा तार तार हो जायेगी!

अध्यक्ष महोदय : मेरा ये कहना है। एक सैकेंड बैठिए। सोमनाथ जी प्लीज। ये जो चाहे बोल लेने दीजिए आज इनको। मुझे समझ नहीं आता आप अपनी गरिमा क्यों गिरा रहे हैं! नेता विपक्ष के पद को गिरा रहे हैं!

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुझे तकलीफ समझ में आ रही है।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, आप बोलिए। क्या बोल रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं दर्द समझ सकता हूं। क्योंकि इनको लगता है कि हम गुमराह करें दिल्ली की जनता को, देश की जनता को। ये कहां से आ जाते हैं! तथ्य के अनुसार हमारी बात झूठी सिद्ध हो जाती है और यही हाईकोर्ट में हुआ है। अगर बात मान लेते जून, 2015 में तो आज ये हश्र न होता। आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो हश्र हुआ है आपकी एप्लीकेशन का। आपको कुछ तो विचार करना चाहिए अन्तरात्मा के साथ! मैं आगे अब कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ये तो दिल्ली के अधिकार का संघर्ष है। जो संघर्ष ...पहले मेरी बात सुन लीजिए विजेन्द्र जी। एक सेकेंड। क्योंकि चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी इस सदन के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने प्रयास किया दिल्ली की जनता को अधिकार मिलें और परिणाम स्वरूप चार साल बाद मुख्यमंत्री पद उनसे ले लिया, ये रिकार्डेड है। एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए और ये सदन जब ये संसद के रूप में चलता था। जब सेंट्रल यूनाईटेड एसेम्बली थी। हमारे माननीय विट्ठल भाई जी का ऊपर चित्र लगा है, इस सदन के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन अंग्रेजों के गवर्नर को इसी कुर्सी पर बैठकर लोकतांत्रिक तरीका अपनाने के लिए मजबूर किया था। मैटर ऑफ रिकार्ड और दिल्ली की जनता को जिसकी दिल्ली की जनता मांग करती रही है, इस सदन के अंदर बैठकर शीला दीक्षित ने मांग की। इस सदन के अंदर बैठकर खुराना ने मांग की। इस सदन के अंदर बैठकर साहब सिंह वर्मा ने मांग की। इस सदन के अंदर बैठकर ये सदन मांग कर रहा है। ये कोई, एक सेकेंड भाई एक सेकेंड। रूक जाइए जरा।

या तो मदन लाल खुराना जी अलोकतांत्रिक थे। आप कह दीजिए। ये सदन तय कर ले या साहब सिंह वर्मा अलोकतांत्रिक थे या शीला दीक्षित अलोकतांत्रिक थी या जनता के बीच में जाकर चुनाव के मैनिफेस्टो में हमने कहा दिल्ली को पूर्ण का अधिकार मिलना चाहिए। हमने कहा। मैं, हम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। हम में सभी राजनीतिक दल आ गये और इसी सदन में बैठकर विट्ठल भाई पटेल जी ने उसवक्त अंग्रेजों का शासन होते हुए उन अलोकतांत्रिक मर्यादाओं का खंडन किया। गवर्नर की बात को स्वीकार नहीं किया। वो एक डेमोक्रेटिक वे में लिखा है। बाकी आप जो राह चलना चाहें, आप चलें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को जानकारी का अभाव है। अगर उनको आप सही जानकारी देते तो शायद वो सही राह पर जाते। जो बातें आपने कहीं हैं। यहां जितना स्टाफ बैठा है। ये कोई भी स्टाफ दिल्ली विधान सभा का स्टाफ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। अगर आप मर्ज में नहीं जायेंगे तो उसकी दवा ठीक प्रकार से कैसे करेंगे! हमारे माननीय स्पीकर महोदय, अध्यक्ष दिल्ली विधान सभा का किसी चपरासी को भी नौकरी पर रखने का अधिकार नहीं है। हां, ये अधिकार होना चाहिए। आप अगर ये वाली चर्चा करते हैं और उस पर बात करते हैं कि विधान सभा जो आज दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के अंतर्गत आती है। उसकी बजाय, एक मिनट, एक मिनट।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप कैलाश जी, बैठ जाइये प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता :पहले दर्द समझिए, फिर दवा खाइये।

अध्यक्ष महोदय : देखिए विजेन्द्र जी, मैं आपको दुरूस्त करता हूं।

विधान सभा, देखिए आप जो बोल रहे हैं न। एक सेकेंड विधान सभा दिल्ली सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आता। आपने बोला है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इम्प्लायीज सर्विसेज।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय, हां ये कोट करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो यहां पर बैठे हैं, सब लोग आप बाद में गलत कहना। इतना गलत यहां बोला गया है। मैं तो नहीं बोला बीच में।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बार-बार बोलते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं अपनी बात कह लूं। आप उसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हो सकता है आपका ज्ञान ज्यादा हो।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, बैठिए। आप ये स्वीकार कर रहे हैं न। एक सेकेंड। नहीं, आपने मुझे ही कहा है अध्यक्ष जी, अगर गलत रिपोर्टिंग नहीं करते तो ये विषय नहीं होता। मैं बहुत सम्मानित तरीके से कह रहा हूं। आपने अभी कहा कि जितने भी इम्प्लाईज हैं। दिल्ली के सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली सरकार के सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब ये बात आप इसी पर रहना। मैं इसी पर आपको देता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं अपनी बात कह लूं। यहां कोई जीत और हार का प्रश्न नहीं। मैं अपनी बात कह लूं। अब प्रश्न ये है, जैसे मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रसन्ना जी जो हैं, वो न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर हैं और राज्य सभा में वो डिप्टी डाइरैक्टर मीडिया थे और राज्य सभा में वो डिप्टी डाइरेक्टर मीडिया थे और राज्य सभा में वो डिप्टी डायरेक्टर (मीडिया) थे। उनका यहां पर एक साल के लिए वो यहां पर नहीं आये थे, वो दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग

में डेपुटेशन पर आये थे एकसाल के लिए और उसके बाद उनको दिल्ली विधान सभा में पोस्ट कर दिया गया। उकसे बाद यहां पर वो सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। 21 जून, 2016 को जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो चिट्ठी लिखती है ए. आई. आर. (डी. जी.) को कि हम प्रसन्ना जी को दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार विधान सभा नहीं लिखती कि हम उनको एबजोर्ब करना चाहते हैं। उसका जवाब आता है 20 जुलाई को और कहा जाता है कि हमारे पास, यहां सब ने ही बताया है; स्टाफ कम है ए. आई. आर. प्रसार भारती में। स्टाफ की कमी है। 17 जुलाई को प्रसन्ना जी का टर्म पूरा हो गया एक साल का, जो उनको हमने डेपुटेशन पर यहां भेजा था और 16 जुलाई को टर्म पूरा हो गया, 21 जुलाई हो गई है तो हम चाहते हैं कि आप इनको वापस भेज दें और रिपेट्रिएट कर दें। यह 20 जुलाई, 2016 को प्रसार भारती ने दिल्ली सरकार को लिखा...(व्यवधान) वही तो मैं कह रहा हूं, नहीं है न? अगर है तो पेपर दो। आप पेपर दे दो।

अध्यक्ष महोदय : पेपर दे दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : लेकिन 20 जुलाई को...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक्सटेंशन का पेपर दे दीजिए। मुझे दे दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : रिपेट्रिएट के 20 जुलाई को...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब दो मिनट उनको बोलने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 20 जुलाई को उनके रिपेट्रिएट के ऑर्डर हो जाते हैं। फाइनली क्योंकि 21 जून को रिक्वेस्ट जाती है, 20 जुलाई को रिजेक्ट हो

जाती है। उसके बाद प्रसन्ना जी को, वो तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, जब उनका टर्म खत्म हो गया, उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए था अपना पेरेंट डिपार्टमेंट। फिर दोबारा से अगर उनको लगता है कि फिर बुलाया जा सकता था या फिर एक्सटेंड हो जाता लेकिन फाइनली 20 जुलाई को रिजेक्ट हो गया प्रपोजल और रिपेट्रिएशन के ऑर्डर हो गए। उसके बाद 29 अगस्त को दिल्ली सरकार एक ऑर्डर निकालती है और कहती है कि 29 अगस्त को हमने इनको स्टेंड रिलीव कर दिया। अब आप सोचिये। एक तरफ तो मंत्री जी बैठे हैं...प्रसन्ना जी की आपने सैलरी रोक दी। 29 अगस्त के बाद आप उनको सैलरी नहीं दे रहे, लैटर्स पर आप उनको एक्स सेकेट्री लिख रहे हैं...पूर्व सचिव लिखते हैं और यहां पर उनको आपने सचिव बनाकर बिठाया हुआ है, ये विरोधाभास कि आप सैलरी नहीं दे रहे, आप उनको पूर्व सचिव कह रहे हैं और वो यहां पर विधान सभा के कागजों पर सचिव के रूप में साइन कर रहे हैं। आप उनकी नौकरी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं! मेरी सिम्पैथी पूरी सिम्पैथी प्रसन्ना जी के साथ है क्योंकि 2 सितंबर... यह आप अपनी अपनी राजनीति के लिए, 2 सितंबर को जिस पर अभी गहलोत जी बहुत गर्म हो रहे थे एक शब्द इन्होंने जो पढ़ा, सुनिये अब मैं पढ़ देता हूं, 2 सितंबर को एज पर एवॉव ऑर्डर दिल्ली गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है Reference is invited to Govt. of NCT of Delhi vide order No. dated 29th Aug. ---order No. 478 as per the above, you have been relieved from Govt. of NCT Delhi and repatriated with direction to report to DG (AIR), however you have not reported देखिये, यह प्रसार भारती का...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अभी विधान सभा को नहीं मिला है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : एक मिनट, मैं पढ़ दूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, यह चीज मुझे नहीं मिली है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : You have not reported for duty to DG(AIR) till date, you are hereby directed to report for duty immediately failing which you will be treated on unauthorized absence अब 29 अगस्त और आज 9 तारीख हो गई 10 दिन का जो इनकी सर्विस में गैप हो रहा है, आप तो अपनी राजनीति कर रहे हो, उनको धार पर चढ़ा रहे हो, ये जो चिट्ठियां आप निकाल रहे हो, इनका कोई लॉजिक नहीं है, यह जो प्रस्ताव आप पास कर रहे हो, इनका क्या लॉजिक है? आप उनकी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? उनको आपको सजेस्ट करना चाहिए था कि आप जाइये अपना पेरेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करिये, उसके बाद हम नए सिरे से कोई कोशिश करते हैं।

हां, अब बात आती है ऑटोनोमी की। विधान सभा की ऑटोनोमी की. ..देश में बहुत सारी ऐसी विधान सभाएं हैं, जहां पर उसका अपना सेक्रेटरिएट है, अपना स्टाफ है, ऑनरेबल स्पीकर की अपनी पावर्स हैं। अगर आप एक ऐकेडैमिक डिबेट करें, कॉन्स्टिट्यूशन के एकॉर्डिंग और उस तरह के विषय को आगे बढ़ायें तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई पक्ष और विपक्ष का विषय है। इसको कहते हैं ताकत लेना और ताकत प्राप्त करना। लेकिन यहां पर राजनीतिक भाषा बोलना, फिर प्रस्ताव पारित करना झूठा-सच्चा, उसका कोई अर्थ न होना और एक अधिकारी की सर्विसेज के साथ खिलवाड़ करना आखिर क्या आपकी ऐसी मंशा है, इस विधान सभा में क्या 67 लोग कम हैं अपनी चलाने के लिए जिसके लिए आपको सचिव भी XXX[1] स्पीकर साहब भी आपका फेवर करें

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप गलत बोल रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : एक मिनट, एक मिनट...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये XXX का शब्द हटा दीजिए। ये शब्द XXX का चाहिए, डाटा दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्योंकि आप, एक मिनट...(व्यवधान) अभी मैं दस बार कह चुका हूं, अरे, मुझे दो साल की एक्सटेंशन का कोई ऑर्डर तो दिखाइये सर्विसेज का।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दे रहा हूं। ये लीजिए। आपकी बात पूरी हो गई।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं पढ़ लूं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दे रहा हूं, दो मिनट और रूक जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सवाल यह है जब 20 जुलाई को...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जी।

अध्यक्ष महोदय : अब दो मिनट बैठ जाइये शांति से।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अब 20 जुलाई को रिपेट्रिएट हो गये...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब दो मिनट रूकेंगे? अब दो मिनट जरा रूक जाइये। आपने अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में दो-तीन बातें कही। ये नोट है मेरे द्वारा। दिल्ली विधान सभा का जो नियम है उसके अंतर्गत मैंने काम किया है।

मैंने ही खुद लैटर लिखा है कि प्रसन्ना जी का अप्वाइंटमेंट यहां होना चाहिए। वो राज्य सभा में ऐसे-ऐसे काम करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट को बेस बना कर जिसका आपने जिक्र किया, दिल्ली गवर्नमेंट, सर्विसेज डिपार्टमेंट ने ऑल इंडिया रेडियो को भेजा और वहां से इनको यहां भेजा गया। मैं उस लैटर पर जिस लैटर पर इनको यहां भेजा गया है, मैं उस लैटर की अभी चर्चान हीं की कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं बताता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वो लैटर है आपके पास? पहले लैटर की कॉपी है?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : देखिये, दिल्ली गवर्नमेंट...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, दिल्ली गवर्नमेंट...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड, सब बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : और आपकी कोई प्रेपरेशन नहीं है। आप यहां प्रेपेयर होकर आइये...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, फिर आप बात दूसरी कर रहे हैं। विजेन्द्र जी, आप गलत कर रहे हैं ये बात। आप विषय को ट्विस्ट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, दो मिनट रूकिये ना। कपिल जी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिये, एक तो माननीय मंत्री जी हैं आप। आप जब

---

[1] XXX चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गये।

भी बोलने के लिए खड़े हों अपनी चेयर पर जाकर खड़े हों। यह जरूर थोड़ा सा सदन की मर्यादा का ध्यान रखें। बैठ कहीं भी सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बोलने के लिए, देखिये, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं...एक बार ध्यान से सुन लीजिए विजेन्द्र जी, यह लिखना-पढ़ना छोड़ दीजिए थोड़ी देर। फिर आपको दिक्कत आएगी। आपने सर्विसेज डिपार्टमेंट का जिक्र किया। सर्विसेज डिपार्टमेंट का आपने लैटर मांगा, किसने एक्सटेंशन दिया? मैं 31 मई, 2016, जून छोड़ दीजिए, जुलाई छोड़ दीजिए, अगस्त छोड़ दीजिए, 31 मई, 2016 का लैटर दे रहा हूं, सर्विस डिपार्टमेंट का जिसने एक्सटेंशन दिया। लीजिए। आपको शब्द वापस लेने पड़ेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, ये मैं लैटर दे रहा हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं 31 मई का लैटर दे रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पढ़ो आप। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या पढ़ूंगा? उसको आप छोड़ दीजिए। आपने जो बात की थी, मैं उसको दे रहा हूं। एक साल पूरा होने से एक महीने पहले का लैटर दे रहा हूं एक्सटेंशन 2018 तक और सर्विसेज डिपार्टमेंट का।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, पेरेंट डिपार्टमेंट ने इंकार...वो एक्सटेंशन नहीं देगा। आप कहां से दे देंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पेरेंट डिपार्टमेंट उनको रिलीव नहीं करेगा, आप कैसे आगे फाइल चला लेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैं अब उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : यह दिल्ली गवर्नमेंट...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने सर्विसेज डिपार्टमेंट की बात की।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर दिया...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये दो मिनट।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप ऑर्डर पढ़िये।

अध्यक्ष महोदय : मैं पढ़ लूंगा बाद में। मैंने पढ़ा हुआ है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप अगर यहां पर...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप बैठ जाइये दो मिनट। अब माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री सत्येंद्र जैन (ऊर्जा मंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे सभी सदस्यों ने बताया है हैरारकी जो है सबसे ऊपर आती है, जनता उससे नीचे आती है। चुना हुआ सदन और सदन के नीचे आती है सरकार। हमें भी, जब सरकार बनी तो सबसे पहले समझाया गया था कि आप जवाबदेह हैं सदन के प्रति और उसके अलावा उससे ऊपर जनता के प्रति जवाबदेह हैं। अगर कोई सरकार का मुखिया है

तो इसका मतलब सदन के नीचे ही है। वो सदन के ऊपर तो है नहीं। जो भी है सरकार का मुखिया अभी, उसमें वो कोर्ट में केस चल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, जो भी फैसला करेंगे और आज के...जिसको भी हम मान लेते हैं, ठीक है। उसको हम मान लेते हैं तो फर्स्ट सदन से ऊपर बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है, कतई नहीं हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया था हिंदुस्तान के अंदर ये असेम्बली आजादी से बहुत साल पहले स्टार्ट हो गई थी। इस असेम्बली ने काम करना बहुत साल पहले शुरू कर दिया था और अंग्रेजों का जो माइंडसेट था, वही माइंडसेट अंग्रेजों से माफी मांगने वालों का आज भी है। जो उनसे माफी मांगा करते थे। उसी माइंडसेट पर वो काम कर रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा था कि पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव, सरकार हम हैं। हम अपने हिसाब से, जो मर्जी चलाएंगे। हम लाट साहब हैं, हम गोरे लोग हैं। हम इस देश को चलाएंगे और यहां के कुछ लोग चुनकर विधानसभाओं में, लोकसभा में बैठेंगे और वो बैठ के अपनी रिक्वेस्ट हमारे पास भेजते रहेंगे और जो हमारे मन में आएगा, हम मान लेंगे और नहीं मन में आएगा तो नहीं मानेंगे परंतु यह देश 1947 में आजाद हुआ था और उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि 1950 में संविधान भी हमारे देश का अपना संविधान बना हुआ था और संविधान बनने के बाद और आजादी आने के बाद जो परंपराएं, जो कहते हैं कि उनक अंडर काम करते हैं हम। मुझे लगता है कि वो खत्म हो चुकी हैं। हम किसी अंग्रेज के अंडर काम नहीं करते। हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, यह समझना पड़ेगा। कई सौ सालों की गुलामी के बाद हमारी रगों के अंदर, बहुत सारे लोगों की रगों के अंदर गुलामी आज भी दौड़ रही है। उनको गुलाम रहना है। गुलामी के अंदर बात करना! गुलामों की तरह व्यवहार करना! उनको ऐसा लगता है कि

शायद हम कम्फर्टेबल हैं, हम बचे रहेंगे। उस तरह से एक तोते को आप ले लीजियेगा। उसको दो-तीन साल पिंजरे में बंद कर दीजिए, दरवाजा खोल भी देंगे, वह उड़ नहीं सकेगा। उसको लगता है कि इस पिंजरे में बंद कर दीजिए, दरवाजा खोल भी देंगे, वह उड़ नहीं सकेगा। उसका लगता है कि इस पिंजरे के अंदर ही रोटी मिलेगी। इसके अंदर ही हमारे को जो भी खाने को मिलेगा, उसके अंदर ही मिलेगी। इसके अंदर ही हमारे को जो भी खाने को मिलेगा, उसके अन्दर ही मिलेगा। मेरा यह मानना है कि कोई भी सदन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्दर कभी भी किसी भी सरकार के अंडर किसी भी व्यवस्था के अंदर काम नहीं कर सकता। सदन स्वतंत्र होता है और इंडीपेंडेंट होता है, सबसे ऊपर होता है। सरकार का यह मानना है कि यह सदन सर्वोपरि है। सदन की यह जो स्वतंत्रता है, उसके लिए सरकार दृढ़ संकल्प है और हर तरीके से सन की निष्पक्षता और सर्वोच्चता बनी रहनी चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं।

एक-दो चीजें कहना चाहूंगा। विपक्ष के नेता ने जो प्रसन्ना जी को भी अभी धमकी दी, कहा, ''प्रसन्ना जी के साथ मुझे सिम्पेथी है।'' सिम्पेथी नहीं उनको धमकी दे रहे हैं कि यहां पर क्यों बैठे हो? कि उनके साथ सिम्पेथी है, कहते हैं कि आप यहां से जाओ और नहीं तो मैं तुम्हें भी देख लूंगा। इनका जो स्टाइल है बात करने का और मुझे तो कई बार यह लगने लगा है कि जो यह बोलते हैं, अगले दिन वो करके दिखाते हैं। आज सुबह इसी सदन में मुझे धमकी दी कि अपनी जिंदगी की परवाह करो, नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। सुन लीजिये। अब ये प्रसन्ना जी को धमकी दे रहे हैं कि आपसे मुझे सिम्पेथी है। अरे भाई! किस बात की सिम्पेथी वो मांगने आये थे सिम्पेथी? वो आपसे कोई सिम्पेथी मांगने नहीं आए। वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम

कर रहे हैं और आज मुझे पता लगा कि प्रसन्ना जी को पूरे बारह वर्ष देश की लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में काम करते हुए हो गये हैं। इतना एक्सपीरियेंस होने के बाद यह मेरी समझ से बाहर है कि उनसे वो खबरें पढ़वाकर क्या करना चाहते हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि प्रसार भारती डूब रहा है! अरे भाई! तुम तो डूब ही रहे हो, इनको क्यों लेकर डूबना चाहते हो? ये तो नहीं डूबना चाहते। वो तो डूबनी ही डूबनी है। और दूसरी बात अब हमारे आदरणीय महामहिम वो तो एडवरटाईजिंग में भी आने लगे हैं, प्राइवेट कंपनियों के लिये। बी. एस. एन. एल. को डुबाने जा रहे हैं, एम. टी. एन. एल. को डुबोने जा रहे हैं। तो प्रसार भारती को भी वो डूबो ही देंगे, गारंटी है। तो कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्यों डुबोना चाहते हो? अरे! अच्छे भले आदमी हैं, उनको काम करने दो। एक्सपीरियेंस है, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का। उनको काम करने दो। उनको न्यूज रीडर बनाकर क्या करोगे? अरे! बहुत ऊपर पद पर पहुंच चुके हैं। उनको वापस इतने नीचे क्यों ले जाना चाहते हो? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे...वो तो मुझे भी पता है। वही तो मैं कह रहा हूं कि डाईंग कैडर है, मर रहा है। अरे! मर रहा है, मरने दो। इनको क्यों मार रहे हो? ये तो अच्छे भले काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो हम सरकार की तरफ से जो सदस्यों ने कहा है, पूरा समर्थन करते हैं और हम चाहेंगे कि प्रसन्ना जी को इसी विधानसभा में आपके आदेश के अनुसार अगले दो साल तक यहीं पर रख जाए, धन्यवाद।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जो प्रस्ताव इस विषय पर रखा है। उस पर एक बार वोटिंग हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सोमनाथ भारती जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है। मैं इससे पहले इस पर वोटिंग करवाऊं श्री विजेन्द्र गुप्ता जी से व्यक्तिगत तौर पर भी, अध्यक्ष के नाते भी प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रसन्ना जी यहां बहुत ढंग से योगदान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और आप कई बार उनके विषय में गलत बोल जाते हैं, पीछे भी आपने गलत कहा कि ऊपर चढ़कर क्यों आते हैं, मुझे दस चीजें उनसे जाननी होती हैं, दस सदस्य उनको लिखकर देते हैं कि मेरा भी नाम डिस्कशन में आना चाहिए, मेरी आपसे प्रार्थना है और इसको आप थोड़ा सीरियसली ले लें कि सेक्रेटरी के विषय में आप टिप्पणी करना थोड़ा सा बंद करें और साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि आपका इन्फ्ल्यूंस भी है इस सरकार में, केंद्रीय सरकार में।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मेरी सरकार में नहीं है। मैं यहां की बात कर रहा हूं। उस सरकार की बात नहीं कर रहा, वो आप जानें, आपका काम। मैं यहां की बात कर रहा हूं कि इस इन्फ्ल्यूंस में आपका जो इन्फ्ल्यूंस है, हमारे सेक्रेटरी साहब को आप सहयोग करें और वो रिलीव न हों, इसमें मेरा योगदान करें। मेरे अपने और इस सदन की गरिमा को बनाये रखने में प्रसन्ना जी जैसे सेक्रेटरी की आवश्यकता बहुत बड़ी है, ये मेरी व्यक्तिगत आपसे प्रार्थना है और इसी में अब सोमनाथ भारती जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें
जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
संकल्प स्वीकार हुआ।

अब इस विषय में मैं एक-दो लाइनें और थोड़ा सा इस सदन की जानकारी में दे रहा हूं। आप सदस्यों की भावना को समझते हुए मैं इस विषय को, I will take of the matter with Hon'ble Speaker, Lok Sahba and the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha and I will also like to talk with all the respectable Speakers and Chairmans of the country. I am directing the Sectt. to circulate the Resolution to the all concerned and I also appeal to Hon'ble Information & Brodcasting Minister to release Sh. Prasnna Ji for this Delhi Assembly.

सदन का समय आधा घंटे के लिये बढ़ाने की मैं प्रार्थना कर रहा हूं सभी सदस्यों से।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

नियम 55 के अंतर्गत अभी मेरे पास तीन नोटिस हैं, उन तीनों पर मैं बहुत जल्दी चर्चा करवा लूं, सभी राजेन्द्र पाल गौतम जी।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्र पाल गौतम।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बोलने का और सदन के समक्ष रखने का अवसर दिया।

दिल्ली की जनता की आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बहुमत से जिताया और जनता की भावनाओं के अनुसार जो सरकार चुनी गई, उसने जो जनता के साथ वायदे किये थे, उन वायदों पर काम करना सरकार ने ईमानदारी से शुरू किया जो पिछली सरकारों में देखनें में नहीं आता था।

अध्यक्ष जी, अगर हम सच्चे मन से बात करें तो ये पहली सरकार होगी जिन्होंने अपने किये हुए वायदों को जुमला ना मानकर बल्कि कॉन्ट्रैक्चुअल

ओब्लीगेशन के रूप में स्वीकार किया और एक-एक करके ईमानदारी के साथ अपने वायदों को पूरा करना शुरू किया। पांच सौ स्कूल बनाने की बात हमने की थी लेकिन डीडीए के द्वारा हमें जब जगह उपलब्ध नहीं कराई गई तो उसी अनुपात के हिसाब से हमने अपने स्कूलों के अंदर जहां जगह बची थी, वहां आठ हजार कमरों का निर्माण करने का काम शुरू किया। उन माताओं से पूछिये या उन बच्चों के दिल से पूछिये जो बच्चे कमरे के अभाव में बरामदे में या पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं! कितने खुश हो रहे होंगे वो बच्चे जब वो अपने स्कूल के अंदर नये भवन का निर्माण होता हुआ देख रहे थे और तेजी से निर्माण जारी था और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने जनता ने नजदीक मोहल्ला क्लीनिक बनाने का काम शुरू किया। वो इसलिये किया था ताकि कम से कम जो रोजमर्रा होने वाली बीमारियां हैं, उन बीमारियों के लिये लोगों को हॉस्पिटल के अंदर बड़ी बड़ी भारी भीड़ के अंदर जा के लाईनों में न लगना पड़े बल्कि अपने घर के नजदीक मोहल्ला क्लीनिक के अंदर वो इलाज करा सकें लेकिन बड़े दुख की बात है। सरकार की अपेक्षाओं के हिसाब से जिस जिस अधिकारी को चयनित किया गया, जो जो अधिकारी सरकार की अपेक्षाओं के हिसाब से काम कर रहे थे और काम तेज गति से आगे बढ़ रहा था, ये बात माननीय एल. जी. साहब को बर्दाश्त नहीं हुई और एक एक करके चाहे आप वैट कमिश्नर को ले लें, चाहे किसी दूसरे विभाग के सीनियर अधिकारी को ले लें, एक-एक करके जिस जिस अधिकारी ने सरकार की अपेक्षाओं के हिसाब से ईमानदारी से काम किया, उन सबको एल. जी. साहब ने वहां से हटाने का काम किया जो बेहद शर्मनाक है और ये घटना केवल हटाने की नहीं है बल्कि जिस तेज गति से गाड़ी चल रही

थी, जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से उस गाड़ी को पटरे से उतारने का काम किया जो बेहद शर्मनाक था! ऊपर वाला सब देख रहा है। सबके कर्मों का हिसाब किताब एकाउंट में लिखा जा रहा है। एक दिन हिसाब हमें भी देना है ऊपर वाले को और एक दिन हिसाब एल. जी. साहब को भी देना है! उन अधिकारियों के खिलाफ एल. जी. साहब ने क्या किया जनको एंटीकरप्शन ब्रांच के अंदर बिठा दिया और जब से वो बैठे हैं, तब से लगातार रिश्वत का बोलबाला है और उसे रोकने के लिये एंटीकरप्शन ब्रांच कुछ भी नहीं रही है। जो कंपलेंट हमने दी है एंटीकरप्शन ब्रांच को, एंटीकरप्शन ब्रांच ने हमारी कंपलेंट को डंप कर दिया और जिसके खिलाफ हमने ऐलीगेशन्स लगाये हैं, उनको सम्मन तक नहीं किया गया, जो शर्मनाक है! लेकिन अगर कोई झूठी कंपलेंट भी आम आदमी पार्टी के किसी एम. एल. ए. के खिलाफ दे दे, किसी अधिकारी के खिलाफ दे दे, किसी मिनिस्टर के खिलाफ दे दे तो मीणा जी बड़ी तत्परता दिखाते हैं उस पर कार्रवाई करने में। ये अपना स्पष्ट हो जाता है, मानसिकता स्पष्ट झलकती है कि आखिर मंशा क्या है? इस सरकार को कमजोर करने की मंशा है! यह सरकार जो वायदे पूरे करने का काम कर रही है, उसको रोकने की मंशा बेहद शर्मनाक है! ये केवल आम आदमी पार्टी के वादे पूरे करने से रोकने की मंशा है। ये मंशा बेहद शर्मनाक है! ये केवल आम आदमी पार्टी के वादे पूरे करने से रोकने की साजिश नहीं, ये दिल्ली के विकास को, दिल्ली की गति को रोकने की साजिश है, जिसकी निंदा होनी चाहिए। हम भी मानते हैं कि हाई कोर्ट का एक आर्डर आया, हम उस आर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन जनता के मेनडेट की रिस्पेक्ट करना मैं समझता हूं एल. जी. साहब को भी जनता के मेनडेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिये। जनता ने मेनडेट आम आदमी पार्टी को दिया है। जनता से वायदे हमने किये हैं। उन

वायदों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है और हम कृत संकल्प हैं उन वायदों को पूरा करने के लिये। लेकिन दुखद ये हैं! जनता के प्रति एकाउंटेबिलिटी किसकी है? हम अपनी एकांउटेबिलिटी से भाग नहीं सकते और हम उसको पूरी तरीके से निभाने के लिये तैयार खड़े हैं। उस एकांउटेबिलिटी को मुझे लगता है कि उसकी रिस्पेक्ट माननीय उपराज्यपाल महोदय को भी करनी चाहिए। चूंकि जनता से बड़ा कोई नहीं। जनता इस सदन को चुनती है और ये सदन जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से उनकी भावनाओं के अनुकूल काम करता है। जिस तरीके से एल. जी. सहाब लगातार एक-एक करके अधिकारियों को हटा रहे हैं, एक तरफ मोहल्ला क्लीनिक के काम में लग हुए, क्लीनिक बनाने वाले अधिकारी को जिस तरीके से हटाया गया और जो स्कूल के अंदर जो कमरों का निर्माण बड़ी तेज गति से हो रहा था, उन अधिकारी को जिस तरीके से हटाया गया, जब कि हमारे माननीय उपमुख्य मंत्री जी ने उनसे निवेदन किया था कि जनता के हित के लिये काम बड़ा तेज गति से, सही दिशा में चल रहा है प्लीज, इनको मत हटाइयेगा। लेकिन बेहद शर्मनाक और बहुत दु:ख के साथ अफसोस है कि इस तरह का काम करके सरकार को डिस्बैलेंस करने की जो कोशिश माननीय उपराज्यपाल जी कर रहे हैं, इस देश की जनता उसको देख रही है। वो कभी माफ नहीं करेगी और साथ में परवाला भी उसको देख रहा है। आपका भी एकाउंट मेन्टेन हो रहा है। आपको भी ऊपर जाने के बाद जवाब देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिये राजेन्द्र जी, कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : हमारी एकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है लेकिन मुझे लगता है एल. जी. साहब की एकाउंटेबिलिटी केंद्रीय सरकार के प्रति, बी. जे. पी. के प्रति है, उनके दिशा निर्देशों पर काम करते हैं ये शर्मनाक है!

अध्यक्ष महोदय : अब कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : माननीय अध्यक्ष जी, लगातार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो लोग नशा बेचने का काम करते हैं, उनको रोकने के लिए क्या पुलिस को आज तक एल. जी. साहब ने कोई आदेश दिया? हम लगातार डेली न्यूज पेपर पढ़ते हैं; कभी आज तक कोई एक भी आदेश ऐसा एल. जी. साहब का किसी ने पढ़ा हो तो बता दें कि जो दिल्ली के अंदर नशा रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के लिए एल. जी. साहब ने आदेश पारित किया हो। चोरों को पकड़ा जाता है; वो डायमंडस की चोरी करते हैं, ज्वैलरी की चोरी करते हैं, दो करोड़ रूपये की! उसमें पुलिस वाले उस ज्वैलरी को खा जाते हैं और मुजरिमों को छोड़ देते हैं। ये एक घटना नहीं, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जहां पुलिस के पार्ट पर कितना बड़ा पक्षपात होता है; गुंडों को छोड़ने की कार्रवाई की जाती है। नशा बेचने वाले को बढ़ावा दिया जाता है। जहां एल. जी. साहब को अपनी भूमिका निभानी चाहिये जो उनके अपने डायरेक्ट अधिकार क्षेत्र के अंदर पुलिस आती है, स्कूलों के अंदर हॉस्पिटल के लिये स्कूलों के लिये जो जगह देनी चाहिये, जो डायरेक्ट डी. डी. ए. उनके अंडर में आता है, वहां एल. जी. साहब खामोश क्यों है? क्या एल. जी. साहब की जनता के प्रति, दिल्ली की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? बेहद दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दिल्ली की जनता सब देख रही है, आने वाले समय में इनको माफ नहीं करेगी और मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि सभी साथी अपना मनोबल ऊंचा रखे। ये हमारे मनोबल को तोड़ने की साजिश है, इस सरकार के मनोबल को तोड़ने की साजिश है लेकिन हम टूटने वाले नहीं, हम खड़े रहेंगे और अपने वायदों के हिसाब से काम करते रहेंगे। हम बिल्कुल कमजोर पड़ने वाले नहीं हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया, शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी (तिलक नगर), संक्षेप में रखियेगा बहुत जरनैल जी, प्लीज।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) **:** जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले देश की राजधानी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां लोकतंत्र का गला घोंटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का जो भारत का इतिहास है, उसमें सबसे बड़ी जीत लेकर आई ये वो पार्टी है, जिसको सबसे ज्यादा दिल्ली वालों ने प्यार देकर एक मिसाल कायम की पर ये बात इस देश के जो हिटलर हैं, उनको पसंद नहीं आई और उस दिन से लग गए जी कि जिस तरीके से व्यवस्था का गला घोटा जाए। मेरे साथियों ने अलग-अलग किस्म के एग्जाम्पल दिए। अध्यक्ष जी, हम भी रोज देख रहे हैं कि इस पार्टी ने जो काम किया है, वो सारी दुनिया जानती है। आज तक तो भारत की चर्चा होती थी डी. डी. सी. ए. घोटाले के लिए, व्यापम घोटाले के लिए, कोयला घोटाले के लिए, इन घोटालों के लिए चर्चा होती थी और अमेरिका जैसी कंट्री में अगर मोहल्ला सभा क्लिनिक की चर्चा हो रही है तो ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही और कर भी कौन रही है, वो पार्टी जिससे उनको सबसे ज्यादा खतरा है, चर्चा तो उनके मंत्रियों की भी होती थी पर वो येल यूनिवर्सिटी की डिग्रियों की होती थी तो वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। ये पार्टी, ये सरकार जिस पार्टी को सबसे बड़ा मेंडेट मिला है, क्या काम कर रही है; ये बुनियादी जरूरतों के काम कर रही हैं दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली वालों की शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, सीवर के लिए, पानी के लिए। ये इन बुनियादी जरूरतों के काम कर रही है, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अध्यक्ष जी, 1993 में दिल्ली में ए. सी. बी. बनी थी। 2013 तक किसी को मालूम नहीं था कि ए. सी. बी.

होता क्या है? 2013 में जब सरकार बनती है जो करप्शन के खिलाफ एजेंडे को लेकर आई तो फरवरी से लेकर और अगले कुछ महीनों में 35 लोगों को वो अरेस्ट करवाती है। 152 लोगों को सस्पेंड करती है। उनसे क्या दुश्मनी है कि उस ए. सी. बी. जैसी एजेंसी को उठाकर दिल्ली सरकार से ले लिया। इसी तरीके एक-एक करके जो भी अच्छे काम हो रहे हैं, जो भी अच्छे काम सरकार करना चाह रही है, जो अच्छे अधिकारी काम करना चाह रहे हैं, वो सारे पर एक-एक करके कुतरे जा रहे हैं। आपने समय कम दिया अध्यक्ष जी, मसले मेरे साथियों ने बहुत सारे बताए हैं, दो लाईनों के माध्यम से क्योंकि उन हिटलरों के जो गुर्गे इस सदन में बैठे हैं, उनको संदेश देना चाहता हूं। उनको समझ आ जाए कि :

'उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा,

चेहरे पर कीचड़ था और शीशा साफ करता रहा।'

अपने अंदर झांकें, अपने अंदर गल्तियां ढूंढें, सामने कुछ नहीं है। सामने एकदम साफ है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, शॉर्ट रखिएगा, प्लीज।

श्री जगदीप सिंह : थैंक्यू, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

Sir, our country has a beautiful system of democratic government. We do not have a monarchy, we have a beautiful system of democratic government. सर, गवर्नमेंट अगर एक आदमी चला रहा है तो वो मोनार्की कर रहा है और न ये हमारे पूरे कंट्री में कहीं एलाउड किया है, न ये मोनार्की सिस्टम हमारा कान्स्टीट्यूशन किसी स्टेट में एलाउड करता है। हां, आज से 1600

साल पहले चाणक्य के टाइम पर जब एक आंदोलन हुआ था अखंड भारत बनाने का, तब ये जो छोटी-छोटी मोनार्कीज थी, इनको इकट्ठा करके एक अखंड भारत बनाया गया था। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। एक आंदोलन ये हुआ था जहां पर 700 साल मुगलों ने राज किया, उसको हटाया गया, एक आंदोलन हुआ जहां पर अंग्रेजों को हटाया गया और एक आंदोलन आज हो रहा है। एक ये जो मोनार्की पैदा की जा रही है दिल्ली में, इसके खिलाफ भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सर, जो एल. जी. साहब ये कर रहे हैं अपनी, ठीक है, पॉवर अगर कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, उनको सम्मान दिया है कि सर्विजिस को वो कर सकते हैं, बट अगर कोई आदमी अपनी पॉवर मिसयूज करने लग जाता है तो वो ब्राह्मण से रावण भी बन जाता है और कहीं न कहीं ऐसा ही दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के साथ किया जा रहा है। एल. जी. साहब अपने एल. जी. हाउस से बाहर निकलकर देखें कि अस्पतालों में किस तरीके से छोटे-छोटे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। आज अस्पतालों को बड़ा करने की जरूरत है। आज मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत है। बीस साल से ये एक्सपेंशन न हो पाई। हमारी सरकार बड़े दिल से इस पर काम कर रही है और वो उन्हीं अफसरों का तबादला करते जा रहे हैं जिनको हमारी सरकार ने ये बड़ी जिम्मेदारी दी कि आप मोहल्ला क्लिनिक बनाइये, आप अस्पतालों को बड़ा कीजिए, आप स्कूलों में बड़ी-बड़ी क्लासिज के लिए स्कूलों को बड़ा कीजिए, कालेज बनाइये, उन सबका तबादला किया जा रहा है। जहां पर उनको दिख रहा है कि दिल्ली की जनता के लिए बेटर काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, वहां पर एल. जी. साहब अपनी उंगली अड़ा रहे हैं। वहां अपनी उंगली दे रहे हैं और ये उंगली उनकी नहीं है, ये उंगली ऊपर से दी गई है, ये प्रोक्सीमेटली ये उंगली किसी और न पकड़ाई है। ये जो इस

तरीके से दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा रहा है, ये दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा मेंडेट क्रिएट करके दिल्ली में असेम्बली में भेजा है ताकि दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम हो सके। मैं यहां से आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहता हूं बी. जे. पी. वालों को; आप दो लोग बैठे हैं, सुन लें, दिल्ली की जनता है और जनता ये सब जानती है सर, इसका जवाब ऐसा मिलेगा आप लोगों को, ऐसा मिलेगा कि दिल्ली में नहीं पूरे देश में साफ हो जाओगे ये गारंटी है।...

अध्यक्ष महोदय : चलिए जगदीप जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री जगदीप सिंह : इस हाउस से मैं निवेदन करता हूं कि आज एक बड़ा रेजल्यूशन पास करें कि दिल्ली स्टेट में कोई मोनार्की सिस्टम नहीं चलेगा यहां पर गवर्नमेंट चलेगी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्ग : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

अध्यक्ष जी, 10 फरवरी, 2015 को जैसे ही दिल्ली विधान सभा के चुनाव के नतीजे आए और दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटों का ऐतिहासिक बहुमत देकर के आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता सौंपी, तभी से केंद्र के अंदर बैठी मोदी जी की सरकार अवसाद में चली गई, डिप्रेशन में चली गई और उस दिल्ली की जनता से बदले लेने की साजिशें बी. जे. पी. के रणनीतिकार नित नई साजिशें बनाने लगे, नित नई रणनीति बनाने लगे। जनता से येन केन प्रकारेण बदला लेने की रणनीति बनाने लगे। पूरा तंत्र लग गया,

ए. सी. बी., सी. बी. आई., रॉ, इंटलीजेंस, पुलिस सभी को लगा दिया गया, आम आदमी पार्टी की सरकार को सताने के लिए, उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के लिए और विधायकों को तंग करने के लिए। ये करारी हार इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अध्यक्ष जी, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति के जनक माननीय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया जी को जिनकी बदौलत आज दिल्ली की सरकार द्वारा स्कूलों में 8000 नए क्लास रूम बनाए जा रहे हैं। 54 मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं जिनके अंदर विश्वस्तरीय वो सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो अमेरिका और जापान में भी उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों को ट्रैनिंग के लिए विदेश भेजा गया। ऐसा शिक्षा के इतिहास में पहली बार हुआ है। शिक्षा की प्रणाली को और अधिक कारगर बनाने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी दिन-रात अथक प्रयास कर रहे हैं। आज दिल्ली में शिक्षा का स्तर बुलंदियों को छू रहाहै। तो ये केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार को बर्दाशत नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार के पी. डब्ल्यू. डी. के प्रधान सचिव सर्वज्ञ श्रीवास्तव को केंद्र सरकार ने एल. जी. के माधयम से इसलिए हटाया क्योंकि सरकारी स्कूलों में 8000 नये क्लास रूम बनाये जा रहे थे। इन्हीं की देख-रेख में दिल्ली के अंदर 1000 मोहल्ला क्लीनिक बन रहे थे। बस, ये बेहतरीन कार्य इनसे बर्दाशत नहीं हुआ और एल. जी. साहब ने सर्वज्ञ श्रीवास्तव का तबादला कर दिया। दिल्ली की जनता को केंद्र सरकार द्वारा किस बात की सजा दी जा रही है? ये आज मैं अपने भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं। दिल्ली की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज पूरे विश्व में दिल्ली सरकार के काम-काज की तारीफ हो रही है; चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या घर-घर में पानी पहुंचाने की बात हो या बिजली के बिल आधे करने की बात हो। जर्मनी, फ्रांस, रशिया,

अमेरिका आदि सभी जगह दिल्ली सरकार की प्रशंसा हो रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए मैं सलाम करना चाहता हूं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी को जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं। आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक की प्रशंसा वाशिंगटन पोस्ट ने भी की है जो कि दिल्ली वालों के लिए बड़ी गौरव की बात है! इन अच्छे और लोकहित के अभूतपूर्व कार्यों से बी.जे.पी. सरकार बुरी तरह से बौखला गई है। बी.जे.पी., एम.सी.डी. में मोहल्ला क्लीनिकों को तोड़ने की साजिश भी कर रही है जो मोहल्ला क्लीनिकों पर काम कर रहे हमारे स्वास्थ्य सचिव को भी हटवा दिया गया! ये कहां का इंसाफ है?

अध्यक्ष जी, ट्रांसफर-पोस्टिंग तो एक बहाना है, इनका मकसद केजरीवाल सरकार को गिराना है। ये तो केवल एक बहाना है। ये असल में तो केजरीवाल सरकार को गिराना चाहते हैं। जिस प्रकार से बी. जे. पी. की केंद्र की सरकारने रेल का किराया बढ़ाकर आम जनता के जीवन गाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की है, ठीक उसी प्रकार दिल्ली के सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण करके दिल्ली सरकार को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, 400 फाइलें मंगाकर एल. जी. साहब दिल्ली सरकार के अधिकारियों का समय नष्ट कर रहे है। उनको डिमोरलाईज किया जा रहा है। उनको काम करने से रोका जा रहा है। उन पर एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। सरकार के काम में हस्तक्षेप कर हरे हैं, व्यवधान डाल रहे हैं। दिल्ली सचिवालय को भी एल. जी. ससचिवालय बनाना चाहते हैं एल. जी. साहब। दिल्ली के अधिकारों पर राजधानी के अधिकारों पर अतिक्रमण इस देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिये, विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गर्ग : आने वाले समय में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र में बी. जे. पी. का सूपड़ा साफ होगा और अध्यक्ष जी, मैं ये बता देना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। धन्यवाद, जयहिंद–जयभारत।

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल : धन्यवाद अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर यदि घोटालों के नाम पर अगर जाना जाता था तो कांग्रेस सरकार को जाना जाता था और नरसंहार के नाम पे जाना जाता था तो गुजरात सरकार को जाना जाता था और जम्मू कश्मीर के अंदर अव्यवस्था के लिए जाना जाता है तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है और दिल्ली के अंदर ईमानदारी से काम करने के लिए जाना जाता है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को जाना जाता है, अरविंद केजरीवाल की! दिल्ली के कामों के अंदर यदि रोड़ा अटकाने के लिए जाना जाता है। विजेन्द्र गुप्ता जी की तो औकात ही कुछ नहीं है। ये तो इशारा वहां से है।

अध्यक्ष महोदय : हां महेन्द्र जी।...नितिन जी, प्लीज उनको बोलने दो लय टूटती है। उनको बोलने दो।

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी, मैं जो कहना चाहता हूं जिस हिसाब से इस समय में अच्छे काम करने वाले ऑफीसर्स अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, इतना असहाय महसूस कभी किसी ने नहीं किया होगा और जो बुरे अफसर थे, वो भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे क्योंकि दिल्ली के अंदर ये ईमानदार सरकार आ चुकी थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार आ चुकी थी जो भी भ्रष्ट अफसर काम करता था जो अरविंद केजरीवाल

उनको जो रास्ता दिखाता था, आप जानते हैं और इस समय जो ऑफिसर्स अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने की बजाए उनको यहां से हटाया जा रहा है! क्या करना चाह रहे हैं महामहिम साहब? यदि किसी बेटी का रेप होता है तो उसके प्रति उनकी जवाबदेही बनती थी, नहीं है जनाबदेही कहीं पे। यदि आज कहीं पर डेंगू के मरीज हो रहे हैं या चिकनगुनिया के मरीज हो रहे हैं, क्या जवाब देही उनसे लेते हैं? जवाबदेही जनता लेती है तो चुनी हुई सरकार से लेती है। मैं आपके माध्यम से यहां पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष को भी और महामहिम साहब को भी कहना चाहता हूं कि ये अहंकार अच्छा नहीं है। एक फिल्म देखी थी हमने कभी, वक्त फिल्म थी उसके कुछ बोल हैं जो मैं आपके सदन के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष के कानों में डालना चाहता हूं और ये सुनने की हिम्मत रखें उसको! ये लिखना तो बाद में कर लेना गुप्ता जी क्योंकि ये बहुत जरूरी है :

''वक्त से दिन और रात,
वक्त से कल और आज,
वक्त की हर शह गुलाम,
वक्त का हर शह पे राज।''
आदमी को चाहिए वक्त से डरकर रहे,
कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज,
वक्त का बदले मिजाज।''

कम से कम इतना जरूर जान लो कि ये वक्त सभी के पास आता है और 2019 के अंदर वो वक्त दिखाएं कि दुनिया नाम लेने के लिए भी तरस जाएगी ऐसा काम करके दिखा देंगे। अरे! जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उनको

काम करने दें आप। और मैं अध्यक्ष साहब पूरे के पूरे सदन की तरफ से आपको सैल्यूट करता हूं कि जिस कदर आपने आज हमारे सचिव श्री प्रसन्ना सूर्यकुमार को यहां पर आपने यहीं पर इसी सीट पर रखने के लिए आपने हिम्मत दिखाई तो इसके लिए मैं पूरे सदन की तरफ से आपको सैल्यूट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद महेन्द्र जी। अब कन्कलूड करिए प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयल : कन्कलूड तो मैंने कहा 2019 के अंदर पूरा का पूरा कन्कलूड ही कर देंगे और पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी आ जाएगी। क्योंकि हम तो आम आदमी हैं और आम आदमी की बात करते हैं और आम आदमी के हक के लिए लड़ते हैं और उसके लिए लड़ते ही रहें, इनकी तरह आराम नहीं करेंगे और फालतू के कामों के अंदर टांग अड़ाएंगे नहीं।

अध्यक्ष महोदय : बैठिये-बैठिये, प्लीज। हो गया आपका, बहुत सुंदर।

श्री महेन्द्र गोयल : आपको सम्मान करता हूं, जय हिंद।

अध्यक्ष महोदय : भावना गौड़ जी। संक्षेप में रखियेगा प्लीज।

अध्यक्ष महोदय : भावना गौड़ जी। संक्षेप में रखिएगा प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ : शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। जगदीप जी के साथ झगड़ना पड़ेगा। लिस्ट में आखिरी नम्बर पर नाम डालते हैं और क्योंकि मुझे लगता है कि यह विषय अपने आप में बहुत गंभीर है, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सरकार अगर उसके चुने हुए प्रतिनिधि, उसके अधिकारी मिलकर सामंजस्य से काम न करें, तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार का चलना अपने में बहुत मुश्किल होता है।

अध्यक्ष महोदय, इतिहास का हिस्सा तो हम नहीं रहे लेकिन इतिहास के विद्यार्थी जरूर रहे हैं। जब हमारा देश गुलाम था, उस समय लंदन में बैठकर के एक सरकार चला करती थी और यहां भारतवर्ष के अंदर लाट साहब बनाए जाते थे...

अध्यक्ष महोदय : भावना जी एक सैकेंड। सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जा रहा है। आप सब की सहमति चाहिए।

(सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाने पर सदन द्वारा सहमति प्रकट की गई।)

सुश्री भावना गौड : शुक्रिया, शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। यानि मुझे जगदीप जी से झगड़ना नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, लंदन में बैठकर के एक सरकार चलाई जाती थी और भारतवर्ष के अंदर लाट साहब बनाए जाते थे, वाइसराय बनाए जाते थे। कोई भी कानून लंदन से पास होता था और उसको पूरे भारतवर्ष के अंदर इम्पलीमेंट किया जाता था। यानि कानून बन रहा है लंदन से और इम्पलीमेंट होगा भारतवर्ष में! आदेश पास होगा लंदन से, भारतवर्ष में रहने वाले वाइसराय उसको पास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने आप में लंदन की सरकार हो गए और यहां बेठे हुए हमारे एल. जी. साहब अपने वायसराय हो गए लाट साहब हो गए और सेम वैसा ही हो रहा है। आज जो परिस्थिति हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर इतने बड़े जनमत को लेकर के आम आदमी पार्टी 67 लोग हम जीत करके के आए पूर्ण बहुमत से लेकिन दिल्ली में सरकार कौन चला रहा है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। केंद्र सरकार के माध्यम से इस सदन में बैठे हुए तीन एम. एल. ए. और वो तीन एम. एल. ए. एल. जी. साहब को माध्यम बना करके केंद्र सरकार

का आशीर्वाद लेकर के बैक डोर से सरकार चला रहे हैं। बैक डोर से ये तीनों विधायक!

अध्यक्ष महोदय, वैसे लोकतंत्र का जो ढांचा है, उसका ऊपरी आवरण तो डेफिनेटली ब्रिटिश संसदीय पद्धति के अनुसार है लेकिन हमें बात केवल ढांचे की नहीं करनी, हमें बात करनी है आत्मा को लेकर के। यूरोप में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। सोवियत साम्राज्य जो था वो बिखर गया इन सब चीजों को लेकर के लेकिन इतिहास में एक व्यक्ति हुआ उसका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। उस व्यक्ति ने बहुत स्पष्ट कहा और मुझे लगता है कि शायद उनको पूर्वाभास भी होगा कि 'स्वाधीनता और अनर्थ' इन चीजों की परिभाषाएं की हैं उन्होंने। उन्हें लगता था कि एक तरफ तो संविधान है और संविधान के द्वारा निर्मित उनके कानून, उनके कायदे और दूसरी तरफ लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनमत से चुनकर के आई हुआ कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी। लेकिन इन दोनों के अंदर सामंजस्य नहीं होगा और अगर विरोधाभास होगा तो किसी भी राज्य के अंदर कोई भी सरकार न तो ठीक तरह से पनप सकती है और न ही वो ठीक तरह से काम कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय, राजगोपालाचार्य जीने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का शासन जहां एल. जी. साहब का सामंजस्य सरकार के साथ में नहीं होगा, जहां केंद्र सरकार का सामंजस्य अपनी राज्यों की सरकारों के साथ में नहीं होगा, वहां केवल तीन चीजें पनपेंगी और वो तीनों चीजें होंगी; एक अव्यवस्था फैलेगी अपने आप में और अव्यवस्था के अंदर तीन चीजें शामिल होंगी, हिंसा, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार। ये तीन चीजों को अपने आप स्थान मिलेगा ऐसी सरकार में। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सरकार कोई भी अपने आप में स्थिर नहीं रहती। सरकारें बदलती रहती हैं। नियमों के

अनुसार, निर्देशों के अनुसार, परंपरा के अनुसार, मर्यादा में रहकर के, अपनी सीमाओं के अंदर रह करके जो व्यक्ति और सरकारें काम करती हैं, स्वाभाविक तौर पर वो प्रशंसा की पात्र होती हैं और हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार इसके लिए अपने आप में वचनबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय, इतिहास में पहली बार कोई ईमानदार सरकार चुनकर के आई है। हम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्य मंत्री का पीए कौन होगा, उनके ओ. एस. डी. कौन होंगे, कौन चपड़ासी काम करेगा, इन सब चीजों को अगर केंद्र सरकार देखेगी या एल. जी. देखेगा तो मुझे लगता है इस तरह से सरकारें नहीं, परिवार भी नहीं चला करते। अध्यक्ष महोदय, सरकार चलाने की जिम्मेवारी विधान सभा की होती है। विधान सभा में बैठे हुए प्रतिनिधियों की होती है। अब देखिए, आदेश करेंगे एल. जी. साहब, कानून बनाएगी विधान सभा, कानून के अंदर संशोधन करने का काम कौन करेगा, वो भी एल. जी. साहब करेंगे तो इस तरह की सरकारें मुझे तो समझ में नहीं आता। हम अपने आप को सौभाग्यशाली कहें या दुर्भाग्यशाली कहें, पूर्ण बहुमत से आई हुई एक सरकार को आज एल. जी. के निर्देशों पर काम करना पड़ रहा है और मुझे देखिए अध्यक्ष महोदय, टीवी के माध्यम से हम देखते हैं, मीडिया बार-बार दिखाता है, केजरीवाल जी की 'नजीब जंग से जंग।' अब देखिए मीडिया के बंधुओं को बता दूं कि कोई व्यक्तिगत तौर पर जंग हमारी नजीब साहब के साथ में नहीं है। हमारी जंग तो केवल भ्रष्टाचार को लेकर के है और आम आदमी पार्टी की सरकार आई और आप सबने एक विज्ञापन देखा होगा 'जंग विरोधी सीमेंट', तो मुझे तो लगता है कि हमें जनता ने फौलाद का बनाकर के भेजा है, हमें सीमेंट की तरह से बना करके भेजा है। इस लिए प्रत्येक वो व्यक्ति जो ईमानदारी से काम नहीं करेगा, जो अपनी

जिम्मेवारी को, जिम्मेवारी समझ करके काम नहीं करेगा, उसके सामने तो कम से कम हम फौलाद और सीमेंट का काम करेंगे और वैसे भी किसी व्यक्ति ने कहा है :

'जब जनता की रहमतो का सहारा मिल गया हमें,

तो हमने समुद्र में भी रस्ता बना लिया।'

अध्यक्ष महोदय, सीधा-सीधा खिलवाड़ है एल. जी. साहब की तरफ से! केंद्र में बैठी हुई बी. जे. पी. की सरकार की तरफ से! अब देखिए, एक ईमानदार आफिसर की नियुक्ति की जाती है पीडब्ल्यूडी के अंदर। बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके विकास कार्यों को हम देख रहे हैं। उनके विकास कार्यों को जनता सराह रही है। लेकिन ऐसे आफिसर को निकाल करके दिल्ली सरकार से बाहर कर दिया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मैडिकल बैक ग्राउड का है, उसको हैल्थ का सैक्रेट्री नियुक्त किया जाता है, दिल्ली सरकार की तरफ से लेकिन उसका बहुत जल्दी ट्रासंफर कर दिया जाता है और आदरणीय मनीष जी की प्रेस कांफ्रेंस में मैंने सुना था वो स्वयं भी एल. जी. साहब के पास गए थे और उन्होंने बताया था कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये अपने आप में दो ऐसे अंग हैं, जिसके बिना सरकार विकास नहीं कर सकती। अफसरों को इसी स्थान पर रहने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

सुश्री भावना गौड : जी, अध्यक्ष महोदय। लेकिन मनीष जी की बात को एल. जी. साहब ने नहीं माना। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। जैसा कि मेरे साथी ने बताया

8000 हजार क्लास रूम्स नए बनाए जा रहे हैं। सौ स्कूलों की जमीन को भी छांट लिया गया है और हैल्थ सिस्टम को लेकर के एक ग्रास रूट के ऊपर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हजार मोहल्ला क्लीनिक बनाएंगे। लेकिन विकास कार्यो की झड़ी लगाने वाले ऑफिसर अगर हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो किस तरीके से सरकार की रीढ़ की हड्डी टूटेगी, इस बात का ख्याल करना चाहिए, इस बात का चिंतन करना चाहिए और जबकि देखिए अध्यक्ष महोदय ये सभी ऑफिसर एक्स कैडर पोस्ट के हैं और सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर 80 आईएएस ऑफिसर हैं और लगभग सीटें 150 के करीब हैं लेकिन अभी 80 काम कर रहे हैं। और इसमें से केवल हमारी सरकार ने केवल दो ही लोगों की मांग की। पी. डब्ल्यू. डी. के ऑफिसर और हैल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर। एजूकेशन में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैल्थ में काम कर रहे हैं और दुनिया भर के विकास कार्य हो रहे हैं तो इस सिस्टम को तबाह किया जाए ऑफिसर्स को हटा कर के, ये न तो हमें समझ में आता है, न हमारी जनता को समझ में आता है। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने एक...

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, अब कन्क्लूड करें प्लीज। लम्बा हो रहा है।

सुश्री भावना गौड : जी सर, मैं बस खत्म कर रही हूं अपनी बात को। हाई कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर दिया था। लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के अंदर दिल्ली के विकास के कामों को रोका जाए, ऐसा आदेश नहीं दिया था लेकिन एल. जी. महोदय केवल इसी बात का पालन कर रहे हैं।

तो मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, सीधा-सीधा दुश्मनी निकालने का काम किया जा रहा है दिल्ली सरकार के साथ में और दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई जनता के साथ में। दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है और यहां केंद्र में बैठी हुई हुई बी. जे. पी. की सरकार और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो संवैधानिक तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ में जीत करके आई है, ऐसी सरकार को चला रहे हैं केंद्र में बैठे हुए लोग और वो भी असंवैधानिक तरीके से!

अध्यक्ष महोदय, लगातार न्यूज पेपर में एल. जी. साहब के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी एक टीम का गठन किया लेकिन वो टीम जिस तरह के परिणाम सामने ला रही है, उससे लगता है कि वो टीम पूरी तरह से नेगेटिव सोच लेकर के बैठी है और उसका काम दिल्ली को विकास कार्य देना नहीं है, केवल और केवल पालीटिकल एजेंडे को लेकर के एल. जी. साहब और उनकी टीम काम कर रही है।...

अध्यक्ष महोदय, बस, दो मिनट मैं और लूंगी सदन के। देखिये, प्रश्न अपने आप में यह है कि क्या संविधान विफल हो गया है? देखिये, जापान अपने आप में एक छोटा सा देश है और उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का अकाल है लेकिन एक अद्भत सामंजस्य है वहां पर और वहां पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने देश से प्यार करता है अपने राज्य के विकास कार्यों से प्यार करता है। वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य देखना चाहता और वहीं दूसरी ओर भारतवर्ष! अद्भुत खजाना है यहां पर। हर तरीके से हम संपन्न हैं लेकिन एक जहां पर थोड़ी सी कमी है यहां के लोग, यहां के पदाधिकारी, यहां चुनाव जीत कर के आने वाले व्यक्ति उन सबके अंदर लोक कर्तव्य का अभाव है। उनके अंदर अनुशासन का अभाव है। उनके अंदर इस तरह की लगन नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और किस जिम्मेदारी को लेकर

के लोगों ने मुझे चुना है। अध्यक्ष महोदय, एक मुझे बात करते-करते किसी कवि की पंक्ति याद आ रही है कि 'हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती।' देखिये, प्रधानमंत्री जब आये, प्रधानमंत्री साहब ने एक जितेंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति थे।

अध्यक्ष महोदय : भावना जी अब कन्क्लूड करिये प्लीज।

सुश्री भावना गौड : सर, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात सन को बता रही हूं। प्रधानमंत्री जी जब चुनकर के आये तो उनके बहुत अच्छे खास साथी थे जिनका नाम दीपेंद्र मिश्रा है और उनको प्रिंसिपल सेक्रेट्री बनाने के लिए वो अलग से अध्यादेश लेकर के आये और उन्हें अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। इसकी जानकारी सदन को नहीं होगी, इसलिए मैं इस चीज की जानकारी इस सदन को दे रही हूं। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के अंदर बी. जे. पी. की सरकार है और वहां एक अमन नाम के व्यक्ति हैं और जबकि वो व्यक्ति आई. ए. एस. अधिकारी हैं और बिना नियम और बिना कानून कायों के वो आज भी लगातार उसी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि संविधान अपने आप में खरा नहीं है लेकिन अगर कुछ खरा नहीं है तो क्योंकि यहां पर रहने वाले मनुष्यों की सोच, वो अपने आप में खरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठे हुए हमारे सभी विधायक, अगर मैं इनको सबकी बहुत एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर ही हूं शायद हमारे विपक्ष के लोगों को अच्छा न लगे लेकिन हमारी सरकार में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर हम उनको संत की संज्ञा दें तो अपने आप में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम सभी लोग ईमानदारी से काम करने वाले अपनी सरकार में बैठके आत्म-निरीक्षण का काम कर रहे हैं लेकिन वहीं हमारे विरोधी और अगर मैं कहूं तो खट्टे-खट्टे पापी

ये लोग केवल, आम आदमी पार्टी की सरकार को कैसे गिराया जाए, केवल उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं अंत में, एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगी कि अब समय आ गया है कि राज्यों को अपने मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने चाहिए और इस परिवर्तन की शुरूआत अगर हम दिल्ली से करें तो बहुत बेहतर होगा। हम सबके लिए आदर्श बनेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। विजेन्द्र जी। कभी-कभी जगदीश जी को मौका दे दिया करो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जी, बिल्कुल कि आज इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव उन्होंने किया। अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे कार्यालय को ये आदेश दिल्ली सरकार का प्राप्त हुआ और दिल्ली सरकार ने खुद चार हिस्सों में ट्रांसफर पोस्टिंग के काम को बांट दिया यानि उस पर लिखा केटैगेरी ऑफ एमप्लाईज और उसके आगे लिखा अप्रूविंग अथॉरिटी, तीसरा हिस्सा सेक्रेटरी सर्विसेज यानि की सेक्रेटरी सर्विसेज के स्तर पर ही आगे कहीं फाईल नहीं जाएगी। आखिरी हिस्सा है एचओडी। एचओडी के लेवल पर यानि एचओडी ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी करना है, वो ही करेंगे और आगे कहीं फाईल नहीं जाएगी और इसके अनुसार लगभग एक लाख इमप्लाईज अगर हैं दिल्ली सरकार में, तो 99,900 अधिकारी, कर्मचारियों की अप्रूविंग अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी तक पूरी हो जाती है 99,900 की। मात्र लगभग 100 या जितने भी उसमें और दस, बीस, पचास, कम या ज्यादा कर लीजिये, उनको अप्रूव करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है और मैं नहीं समझता कि आपका कोई भी ऐसा प्रस्ताव, जिस पर आपको अप्रूवल चाहिए अगर आप एक इंजीनियर-इन-चीफ को जो कि एक टेक्नीकल व्यक्ति

है, उसको आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी. डब्ल्यू. डी. यानि कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर, जहां पर सिर्फ एक आई. ए. एस. आफिसर ही बैठ सकता है, वहां बैठा कर और फिर ये कहें, देखिये अधिकारी तो आते जाते रहेंगे। अधिकारियों से सरकार नहीं है, सरकार है आपसे। आप सत्ता में हैं। आप बहुमत में हैं लेकिन अधिकारियों की कमी पकड़कर आप लगातार जिस तरह लटक रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपका जो अपना अस्तित्व है, वो कहीं कोई स्थान नहीं रखता। आप एक आई. आर. एस., डाक्टर को आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ प्लस डीजी हेल्थ, डायरेक्टर जनरल, दो दो पोस्ट दे रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कभी झूठ ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। झूठ के पैर नहीं होते और वो इसलिए बार-बार पिटता है और वो पिट रहा है। आप लॉग टर्म में सोचिये। आपकी सरकार की साख धीरे-धीरे जा रही है और वो इसलिए जा रही है कि आप नियम और कानून को धत्ता बताकर और उसको आप...अभी कहा जा रहा है और फाइलें मंगाई जा रही हैं। वगैरह-वगैरह। 4 अगस्त, 2016 का जो हाईकोर्ट का आर्डर है, उसको पढ़िये आप। अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो नेट पर वो है। उसकी कापी निकालिये। उसका जो न्क्लूजन है, वो पढ़िये। थोड़ा होमवर्क किया करिये और जो कन्क्लूजन्स हैं, उसमें सारी स्थिति स्पष्ट की गई है। अब जो 400 फाइलों की बात आप कर रहे हैं, वो फाइलें आप तो खुद ही भेज रहे हैं। आप मुझे एक आदेश ऐसा दिखा दीजिये जिसमें कहीं ये कहा गया हो कि ये फलानी-फलानी फाइल ये उपराज्यपाल को भेजनी ही भेजनी है। ये मुझे आदेश दे दीजिये आप या ये हमने मंगाई है। उपराज्यपाल भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है अगर आप व्यवस्था को तोड़कर कुछ बात कहेंगे तो आप कह सकते हैं, आपका अधिकार है। लोकतंत्र में कुछ भी बोलिये। फिर इस देश में तो क्या-क्या बोला जाता है,

क्या-क्या होता है, वो हम सब जानते हैं लेकिन बोलने से सरकारें नहीं चलती। आपका दायित्व है सरकार चलाने का। जिम्मेदारी है आपकी सरकार चलाने की और अगर आप मुंह ऊपर करके थूकोगे तो थूक आपके मुंह पर ही गिरने वाला है। ये आप समझ लीजिये क्योंकि आप सरकार हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बैठिये-बैठिये, उपसभापति जी बैठिये।

अध्यक्ष महोदय : राखी जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुझे ये दुस्साहस करना पड़ रहा है कि उपसभापति को मुझे कहना पड़ रहा है, आप बैठिये।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, मैं बैठा रहा हूं न। विजेन्द्र जी, आप डायरेक्शन मत दीजिये। विजेन्द्र जी, मैं रोक रहा हूं न उनको। आप डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तो प्रश्न ये है कि एक आदेश, हां 4 अगस्त के हाईकोर्ट के अनुसार अगर अधिकारियों को लगता है कि रूल्स का कहीं न कहीं वॉयलेशन हो रहा है और उसकी अप्रूवल की जरूरत है तो अधिकारी फाईल भेज रहे हैं। आप रोक दीजिये अधिकारियों को। मत भेजें फाईल। मुख्यमंत्री जी, उपमुख्यमंत्री जी यहां बैठें, चिट्ठी लिखकर कहें कि आप मत भेजें। फाईल नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप देश की कानून व्यवस्था को ही धत्ता बताकर पूरी व्यवस्था को धत्ता बताकर, संविधान का धत्ता बताकर, कानून को धत्ता बताकर हर चीज मे अविश्वास प्रकट करते रहेंगे तो आप सोचिये

आप जा किस रास्ते पर रहे हैं और आप पहुचेंगे कहां? आज भी मौका है हमारे पास, हम चीजों को ठीक करने के लिए सही रास चुनें। कब तक आप 67 की जीत के घमंड में चूर होकर इस प्रकार का अनर्गल प्रचार करते रहेंगे, कब तक?

मुझे यह लगता है कि मैं इस पर बहुत लंबी बात कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन 99,900 कर्मचारियों और अधिकारियों को नियुक्त करने का और पोस्ट करने का अधिकार आपके पास है। 100 पर आपको अप्रूवल लेनी है। वो भी आप आपसी सामंजस्य से, नियम और कानून से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी दिल्ली शहर में ऐसा हुआ हो, इस सरकार में भी साल में कि उसमें कोई एक आधा दो परसेंट कहीं पर कोई विषय रहा होगा, वो उसके अलावा कभी रहा हो तो इसको इस तरह से हव्वा बनाकर जनता को क्या पेश कर रहे हैं? क्या आप इनकम्पिटेंट हैं या आप फेल सरकार हैं? आप काम नहीं करना जानते। आपकी अनुभवहीनता सामने आ रही है। इन सबको समेटिए, ठीक करिये और ऐसे सदन विशेष...मुझे आज, आज साढ़े सात तक आप बिठा रहे हो। सबको सुबह 9-10 बजे से लोग चले हुए हैं, विशेष सत्र, विशेष सत्र...मुझे तो अब तक कोई विशेषता इसमें नजर नहीं आई! जन हित में आपने कोई डिस्कशन...एक डिस्कशन 55 में आपने जन हित का नहीं लिया। हमें नोटिस तक नहीं दिया कि 55 में आप अपना कोई भेजिए। सुबह तक ये मालूम था कि आज का लिस्ट ऑफ बिजनेस क्या है! तो ये सारे सिस्टम को आप इस तरह से लाईटली मत प्ले करिए।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को आपके माधयम से कि ये लाईटली प्ले करने का विषय नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी...देश की राजधानी में आपकी सरकार है लेकिन आप हर बात को मजाक बनाना, हर

बात को गलत तरीके से बोलना अपशब्द बोलना, असंसदीय बोलना किसी के बारे में भी कुछ कहना आपके लिए एक मौका है...

अध्यक्ष महोदय : चलिए विजेन्द्र जी, कन्क्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपके पास एक मौका है अच्छा काम करने का, जो आपको करना चाहिए था लेकिन मुझे लग रहा है कि समय बीत रहा है और विशेष सैशन जनहित के मामलों में अगर बुलाये जाएं, उन पर चर्चा हो, लोगों को उसका फायदा हो। आज तक इस विधान सभा में एक भी सत्र में, एक भी विषय ऐसा नहीं लिया जिसमें पानी...अभी पीछे वाटर लॉगिंग हुई थी। दिल्ली पूरी डूब गई। लोग परेशान हो गए। क्या आपने यहां पर 55 में उस पर चर्चा करना चाहा? नहीं चाहा। तो इसलिए जन हित के मामलों पर ध्यान दें तो अच्छा हो।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी सत्येंद्र जैन जी।

श्री सत्येंद्र जैन (स्वास्थ्य मंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जो विजेन्द्र गुप्ता जी ने चार आदेश की बात की हैं, ये आदेश दिल्ली सरकार ने नहीं, एल. जी. साहब ने दिये हैं। मैं क्लेरिफाई कर देता हूं और सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा। बहुत सारे सदस्य मेरे पास काम लेकर आते हैं आजकल। उनको समझाने में बड़ी दिक्कत होती है और बड़ा दुख भी होगा जब आपको सारी सच्चाई का पता लगेगा। ये आदेश है 29 अगस्त, 2016 का, जिसमें एल. जी. साहब ने कहा है कि सभी क्लास वन आफिसर्स; इन्क्लूडिंग आईएएस, दानिक्स और जितने भी क्लास वन आफिसर्स हैं, उन सब का ट्रांसफर आनरेबल एल. जी. साहब करेंगे और उन्होंने फाईल के ऊपर लिखा है... सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, सर। उन्होंने फाईल के ऊपर लिखकर

दिया है कि फाईलें मंत्री को नहीं दिखाई जाएगी। ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई भी फाईल मंत्री को नहीं दिखाई जाएगी, चीफ मिनिस्टर को भी नहीं दिखाई जाएगी। उसी आदेश के नीचे लिखा हुआ है; अगर एल. जी. साहब चाहेंगे तो मुख्य मंत्री से सलाह ले सकते हैं जहां उनका मर्जी होगी। वरना मुख्य मंत्री अपनी ओर से सलाह देने की चेष्टा न करें। दूसरी कैटेगरी; सैक्रेटरीज जो मंत्रियों के साथ सैक्रेटरी लगे होते हैं, पीए जो हमारे पर्सनल एसिस्टेंट होते हैं, उन सबके ट्रासंफर पोस्टिंग चीफ सैक्रेटरी करेंगे। मुझे नहीं पता कि कल मेरा सैक्रेटरी कौन होगा! मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा पीए वहीं होगा या नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी... सर सुन तो लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप भली-भांति समझ रहे हैं इस आर्डर को। आप इस आर्डर की भाषा भली भांति समझ रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री : सर आप सुन लीजिए। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाईल मंत्री के सामने नहीं रखी जाएगी। मंत्री से पूछ कर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की जाएगी और ये आदेश एल. जी. साहब ने खुद अपने हाथ से लिखकर टाईप भी नहीं कराए। सुन लीजिए। नहीं, वो आपको कॉपी दे दी जाएगी। दास केडर क्लास-2 और क्लास-3 की सर्विसेज, जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, वो करेगा सर्विसेज डिपार्टमेंट और बाकी जितने भी आफिसर्स, चपड़ासी से लेकर जो भी आफिसर्स बचते हैं, उन सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग एचओडी करेंगे या रेस्पेक्टिव सैक्रेटरीज करेंगे। किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर किसी भी मंत्री, मुख्य मंत्री की कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल... थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। अभी मैं किसी हॉस्पिटल में चलता हूं। जैसे होता है न रात को चले जाते हैं, कहीं भी, अस्पताल में चले जाते है, देखने के लिए। अगर वहां पर मुझ से कोई शिकायत करे, अगर मैं वहां

पर किसी डाक्टर को कहता हूं इसका ट्रांसफर किया जाए, एल. जी. साहब करेंगे न? उसका ट्रांसफर किया जाए तो सैक्रेटरी साहब करेंगे। चपड़ासी का ट्रांसफर किया जाए तो वहां के एमएस साहब करेंगे। अगर उसको मैंने सस्पेंड करने की बात की तो उन्होंने कहा कि सस्पैंड करना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अलग से आर्डर दिये गए हैं। ये चाहते हैं कि सारे सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। उनको सर्विसेज दी है हाई कोर्ट ने। उनको सारा काम नहीं दिया। इंटरप्रेटेशन किस तरह से कर रहे हैं ये लोग; हाई कोर्ट ने कहा है कि सर्विसेज एल. जी. के हाथ में। सर्विसेज में क्या होता है; आपका प्रमोशन करना है, आपकी सेलेरी बढ़ानी है, वो सर्विसेज का पार्ट है पर अलोकेशन आफ वर्क, काम का बंटवारा कि किस को काम क्या दिया जाएगा, वो उसी आदमी के पास होता है जो उसका कंट्रोलिंग आफिसर होता है। ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल-42 इनके पास भी भी रखा होगा, पढ़ लें। उसके अंदर लिखा है कि Minister in chrage is primarily reponsible for all departments. उसके अपने डिपार्टमेंट में कुछ भी होता है तो वहीं जिम्मेदार समझा जाएगा। अगर दिल्ली में वाटर लॉगिंग होती है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली का पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री मैं हूं, अगर मेरी जिम्मेदारी है रात को दो बजे, रात के चार बजे अगर उसके अफसर वहां पर नहीं आएंगे तो उनको सजा देने का। उनको कहने का ये अधिकार भी मेरे पास होना चाहिए। ये नहीं हो सकता वो कहेंगे... मैंने कुछ अधिकारियों से बात की। अब तो डेढ़ साल हो गया है, खुलकर बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है आप लोग क्यों नहीं... कहते हैं कि सर ऐसा है कि आप हमारा क्या कर लेंगे? डांट लेंगे, ठीक है, डांट खा लेंगे। कहते अगर उन्होंने कुछ किया तो हमें तो बर्बाद कर देंगे। अगर मेरी सीआर आउटस्डेडिंग की जगह

उन्होंने वैरीगुड कर दी तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा और हम मिनिस्टरी में कुछ लिख दिया तो सर्विसेज ही बर्बाद हो जाएगी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इनका कहना है कि फाइलें जो भेज रहे हैं, अपनी मर्जी से फाईल भेज रहे हैं। एल. जी. साहब के आदेश पर दिल्ली के चीफ सैक्रेट्री ने सभी एचओडी, सभी सैक्रेट्रीज की मीटिंग ली और डिटेल में समझाया कि आपने कौन-कौन से फाईलें भेजनी हैं। और 29 अगस्त के आदेश के बाद एल. जी. साहब तीन आदेश और दे चुके हैं कि कौन-कौन से फाईलें भेजनी है आपने और स्पेसिफिक फोन करके मंगा रहे हैं फाइलें। आप कहते हो फाईल नहीं मंगाई। एक आफिसर को, अब तो आफिसर का नाम भी नहीं ले सकते। उसको अगले दिन टर्मिनेट कर देंगे, बुलाया गया कि आधे घंटे के अंदर सारी फाईलें लेकर मेरे आफिस में आ जाओ। आधे घंटे के अंदर फाईलें मंगाई गई। हमने कहा कि अगर फाईलें मंगाते हैं, ठीक। मंगा लीजिए पर मंत्री के थ्रू आनी चाहिए। ये क्या तरीका होता है! ट्रांजेक्शन आफ बिजनेस रूल में लिखा हुआ है कि एल. जी. साहब को अधिकार है, कोई भी फाईल वो मंगा सकते हैं देखने के लिए। परंतु अगर कोई भी डिपार्टमेंट फाईल भेजेगा तो वो मंत्री को सूचित करेगा कि मैं यह फाईल वहां पर भेज रहा हूं। अब उन्होंने क्या बना लिया है कि सब को डराना धमकाना और सारे सिस्टम को बंद करना। हम यह कहते हैं, ''ठीक है, आपको लाटसाहब की उपाधि मिल गई है, पूरे अधिकार भी लाटसाहब वाले मिल गए हैं परंतु लाटसाहब वाला दिल भी तो रख लो। अरे! जिनको कहा गया, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको काम तो करने दो।'' मैं कहता हूं कि काम करने के तीन तरीके हैं। एल. जी. साहब कर लें या हमें करने दें या मिलकर कर लें। कहते हैं ''न करूंगा न करने दूंगा।'' अरे किसी भी तरीके से नहीं करने देंगे। जिम्मदारी किस की है? बाहर देखिए, मीडिया वाले खड़े हों, डेंगू,

फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है जी। दिल्ली हार्ट कोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते रिपोर्ट सब्मिट करनी थी, रिपोर्ट सब्मिट नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? कहते रहे मंत्री जी। मंत्री के कहने से क्या होता है? पहले अगर मैं किसी को कहता था काम करने के लिए और वो काम उसी दिन पूरा न हो, ऐसा हो नहीं सकता था। आज 8 अगस्त से लेकर आज 9 सितंबर है, पूरा एक महीने एक दिन हो गया। दिल्ली सरकार के किसी भी आफिस के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ एक ही काम चल रहा है कि फाईलें ढूंढ-ढूंढकर ले आ रहे हैं। कहते हैं सर, आपका तो क्या होगा? कहते हमें टर्मिनेट कर देंगे। ये कमेटी बिठाई है। कहते हैं ये कमेटी आपका तो क्या बिगाड़ेगी, आप तो तैयार हैं। आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप तो पहले भी जेल हो आए थे। फिर दोबारा जेल हो आएंगे, आपका क्या जा रहा है? हम अगर जेल गए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। एक महीना हो गया। मैंने लिखित में आर्डर दिये हैं सभी अधिकारियों को कि एक महीना बहुत होता है फाईलें इकट्ठी करने के लिए। अब ये ड्रामा बंद कर दो कि ज्यादा से ज्यादा 14 तारीख तक जितनी फाइलें हैं, ले आना। उसके बाद अगर फाईल आती है तो फिर मैं भी देखूंगा आपको। इन लोगों ने जो मजाक बना दिया है गर्वेनेंस का। जिम्मेदारी सरकार की! अधिकार, ये किसलिए? अगर एल. जी. साहब कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, करके दिखाये ना। पुलिस 100 परसेंट उनके अंडर है। दिल्ली के अंदर रोज बलात्कार होते हैं, दिल्ली के अंदर रोज चोरियां होती हैं। अरे! दिल्ली के अंदर क्या काम नहीं होता! दिल्ली के अंदर पुलिस को ठीक करके दिखाये ना। कम से कम ऐसी जगह तो बनायें, लोग जाकर शिकायत तो कर लें पुलिस की।

पुलिस की कोई शिकायत भी नहीं कर सकता कहीं जाकर। अगर एल. जी. साहब को काम करना है तो डी.डी.ए. का काम करके दिखायें ना। उसके चेयरमैन भी वही हैं। डी. डी. ए. डायरेक्टली उनके अंडर आता है। कहते हैं नहीं जी, काम करने के लिए थोड़ा है, काम अटकाने के लिए। वो ऐसे बुरे आदमी नहीं हैं, मिला हूं मैं उनसे कई बार। ये लोग हंस रहे हैं, इन्होंने बुरा बना रखा है। उनको हंस-हंस कर कहते हैं; ये काम भी नहीं होने देना है, ये काम भी नहीं होने देना है, ये काम भी नहीं होने देना है और जो हंसी आ रही है, सुनियेगा, 29 अगस्त के इसी ऑर्डर का दूसरा पेज पढ़ लेना। उसमें कई सेक्रेट्रीज के ट्रांसफर किए गए हैं! आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि सिस्टम कैसे चलता है। कोई भी सेक्रेटरी ज्वाइन करता है, सबसे पहले मंत्री से मिलने आता है। एक भी सेक्रेट्री मुझसे मिलने नहीं आया। तीन सेक्रेट्री मेरे पास नियुक्त किए हैं...(व्यवधान) अखबार में आपने लिखवा दिया होगा। मैं अखबारों के चक्कर नहीं काटता, आप काटते हैं।...(व्यवधान) चलो दिखा देना।...(व्यवधान) एक ता मैं कहूंगा कि आप टेबल पर खड़े होकर बोलिये। 11-12 दिन हो गए, तीन सेक्रेट्री मेरे यहां नियुक्त किए गए हैं...कोई भी अधिकारी अगर नियुक्त होता है सेक्रेट्री लेवल पर तो सबसे पहले मंत्री से मिलने आता है। एक भी अधिकारी ने जहमत नहीं उठाई अभी तक मिलने की। उन तीन में से एक को मैंने बुलाया तो वो आए। यह तो बड़ी अच्छी बात हुई, मुझे लगा कि कम से कम मीटिंग में तो आये। उप मुख्यमंत्री के साथ तो ऐसा हुआ कि वो तीन-तीन मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़ी। मीटिंग में भी नहीं आये। कहते हैं कि हम फाइलें भेज रहे हैं। सर, गवर्नेंस को इन्होंने मजाक बना दिया है! मजाक क्या बना दिया है कि सारी पॉवर हमारे हाथ में है...(व्यवधान) सर, आपको कह रहे हैं। हां जी, हाई कोर्ट ने सिर्फ आदेश

दिये हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि वो अभी डिबेटेबल है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने सिर्फ यह कहा है कि वो अभी डिबेटेबल है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वो अभी डिबेटेबल है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने सिर्फ यह कहा है कि सर्विसेज जो है, वो एल. जी. के अंडर आती है, जो कि संविधान के अंदर नहीं लिखा। हम उसको कहते हैं, मानते नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सर्विसेज का मतलब यह नहीं होता कि जो भी लोग, अगर मेरा ड्राईवर है, चलो आपकी मर्जी से नियुक्त कर दिया। मैंने मान लिया कि कोई भी ड्राईवर आ जाये ठीक है, एनी वन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता परंतु अगर वो गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चलाते टाइम उसे मेरा आदेश, तो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरा आदेश, मानने से मना कर दे कि मेरी मर्जी, तो अपनी मर्जी से चलूंगा। यह पॉसिबल नहीं है और मैं उनको दिल्ली के अंदर हम काम करके दिखायेंगे, इन्हीं लोगों से काम करके दिखायेंगे। दिल्ली के अंदर 105 मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब तो बढ़ गये।

स्वास्थ्य मंत्री : अभी 105 चल रहे हैं। बढ़ने का तो अभी आशा है. ..ये पता नहीं बढ़ने देंगे। ये आशा...पता नहीं क्या करेंगे? हमने इंडिपेंडेंट एजेंसी से रिपोर्ट बनवाई है कि उसका सैटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट-डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर कि क्या है लोगों का। आज दिल्ली के अंदर लगभग 156 हजार लोग हर रोज मोहल्ला क्लीनिक में आ रहे हैं और 11 लाख लोगों को हम देख चुके हैं मोहल्ला क्लीनिक में, 11 लाख लोगों को! और ये मोहल्ला क्लीनिक्स ...मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि सब लोगों के सामने कि जिस तरीके

से पूरे एक महीने काम नहीं हुआ, आज मैंने ऑफिसर्स को बुलाया है, सब को मैंने कहा है कि कुछ भी हो जाये, काम तो करना पड़ेगा या तो लिखित में एल. जी. साहब आदेश दें कि यह काम बंद करना हैं। मैंने आदेश लिखकर दिए हैं, मैं बर्वली काम नहीं करता, सभी अधिकारियों को लिखकर आदेश दिए हैं मैंने कल कि जो भी पर्टिक्युलर एल. जी. साहब लखकर दें आपको कि यह काम नहीं करना है, वो काम बंद होगा। बाकी कोई काम बंद नहीं होगा। अगर आपने काम बंद किया तो आप सब को हम देख लेंगे। अभी क्या हो रहा है कि सब को ऐसा डरा दिया गया है कि अगर आपने कोई भी काम किया तो आपको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। एक महीना हो गया, मोहल्ला क्लीनिक्स के अंदर हम टैस्ट कराते हैं, उसका टैंडर खत्म होने वाला है, कैबिनेट नोट नहीं लगा रहे, अरे, कमाल हो गया! अगर ये 22 तारीख तक नहीं हुआ तो मोहल्ला क्लीनिक्स सारे के सारे बंद हो जायेंगे। यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहते हैं! अगर दिल्ली की जनता...इस तरह के काम हुए, नये मोहल्ला क्लीनिक्स बन रहे हैं, एम. सी. डी. वाले धमकी दे रहे हैं कि सब को तोड़ देंगे। अरे, तोड़ लो, आप में दम है, यही कर लो जाकर। हमें कोई लेना-देना नहीं है, जनता देखेगी। जनता और आप, आपस में बीच में निपट लेना। क्या होने वाला है? जितनी भी विधान सभा है, तीन विधान सभा आपकी भी हैं परंतु आपके काउंसलर्स बहुत सारे हैं, उनके भी काम आयेंगे। ये जनता के हित का काम है, मेरे हित का काम नहीं है, सब के हित का काम है। अगर जनता के हित के कामों के अंदर भी इतना अड़ंगा अड़ायेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि ये लोग राजनेता कहलाने लायक हैं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं और मैं कह दूं कि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, अभी जो चिल्लाएंगे तो वही कर रहे होंगे। अभी एकाउंटबिलिटी की

बात हो रही थी। सर, जो जिसका माई-बाप होता है, उसके लिए काम करता है, जिसका जो माई-बाप होगा उसके लिए काम करेगा। हमारा माई-बाप जिसने हमें वोट दी, जनता है। हम तो जनता के लिए काम करेंगे, दिन-रात काम करेंगे। उस जनता के लिए काम करेंगे, जिसने वोट दिया था। सर, जिनका माई-बाप केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार के लिए करेगा। यह सब कुछ पता है। अब यह युद्ध तो इस बात का है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एल. जी. के माई-बाप...

स्वास्थ्य मंत्री : चलो, मैं बोल देता हूं एल. जी. साहब का माई-बाप केंद्र सरकार हैं। सर, ये छेड़ते रहते हैं, फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जायेगा और ये सहन नहीं कर पायेंगे। एल. जी. साहब का माई-बाप मोदी है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। वो एल. जी. के माई-बाप हैं वो उनकी सेवा करेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे और देश के प्रधानमंत्री के माई-बाप वो अडानी और अम्बानी हैं और जो जिसका माई-बाप है, वो उसकी सेवा करेगा। अच्छा है, बीच-बीच में न छेड़ें।

अध्यक्ष महोदय, इस देश के लोग जो राजनीति में आते हैं, कोई सेवा करने नहीं आते, जो कहते हैं ना हम तो एक रूपये में काम करने को तैयार हैं, तनख्वाह एक रूपया होनी चाहिए, नीलामी लगा लो 10-10 लाख रूपये महीना देने वाले मिलेंगे एम. एल. ए. बनने को। इस देश के अंदर ज्यादातर राजनीति में आते हैं कमाई करने के लिए। धंधा है, उनका धंधा! आप क्यों बोल रहे हो? आपका नहीं है। अगर बोल रहे हो तो आपका भी है। वो धंधा करने आते हैं। बिजनेस में चले नहीं तो यह बिजनेस करने आते हैं। इस बिजनेस को, धंधे को खत्म करने आये हैं। इस देश के अंदर पहली बार 'स्वराज'

लेने के लिए आये हैं, दिल्ली के अंदर मोहल्ला सभाएं बनाने जा रहे हैं। जो मोहल्ला सभा बना रहे हैं, इन नेताओं को कभी समझ में आने वाली नहीं है। ये लोग सारी पॉवर्स को अपनी मुट्ठी में बांध कर बैठे हैं, उसको खत्म करने के लिए आये हैं। सारी की सारी पावर्स जनता को वापस करने आये हैं। इनको डर लग रहा है कि अगर जनता की ताकत जनता के हाथ में चली गई तो नेताओं को नमस्ते करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो अपने साथ चार-चार बॉडी गार्ड लेकर घूमे हैं ना, जनता को धमकाते फिरते हैं नमस्ते करो, नमस्ते करो, मंत्री जी आ गये और ये एम. एल. ए. साहब आ गये, काउंसलर साहब आ गए, इनको कोई नमस्ते करने वाला नहीं मिलेगा। ये चाहते ही नहीं जनता के पास पावर जायें और हम तो आपको करके दिखायेंगे। इस सदन के सामने मैं कहता हूं, ''दिल्ली में भी करेंगे, गोवा में भी करेंगे, पंजाब में भी करेंगे और गुजरात में भी करके दिखायेंगे आपको।''

अध्यक्ष महोदय, एक बात फिर से रिपीट करना चाहूंगा दिल्ली इलैक्शन की। हम इस लायक नहीं थे कि दिल्ली इलैक्शन के अंदर हम 67 सीटें ला सकें। हमेशा हमारी मीटिंगें हुआ करती थीं कि किस तरह से 40 सीटें आ जायें, किस तरह से 42 सीटें आ जाये। इससे ज्यादा कभी नहीं सोचा। हम तो धन्यवाद करते हैं ऐसी पार्टी जिसका पोलिटिकल सेंस, पोलिटिकल समझ इतनी ज्यादा है कि उन्होंने हमें इतना तंग किया, इतना तंग किया कि 67 आई और वही काम अब करने जा रहे हैं, वो हमें इतना तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि हम पंजाब के अंदर भी और गोवा के अंदर भी इनको दिखाएंगे। जनता इसका जवाब देगी। इनको बताएगी कि जो दिल्ली में हुआ था, वही हाल इनका गोवा में होगा और वही हाल इनका पंजाब में होगा और गुजरात में भी होगा। गुजरात के अंदर तो कल ही हो

गया है, सेम्पल कल ही मिल गया इनको। हमारी सरकार के लिए चार मुद्दे सबसे बड़े हैं और जो कोई भी नेता नहीं चाहता... सिद्धू आप ही का है, हमारा नहीं है।

उप मुख्यमंत्री : आपके यहां से ही गया है।

स्वास्थ्य मंत्री : आप ही का था वो हमारा बच्चा है आप ही का बच्चा है। सर, पहली चीज स्वराज, जनता की ताकत जनता के पास। दूसरा मुद्दा है शिक्षा, इस देश के नेता जान बूझकर चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहें, गंवार रहें ताकि इन नेताओं से क्वेशचन न पूछ सकें कोई और इनको चलते हुए सलाम ठोकें। किस बात का सलाम ठोगें? अरे, तुमने सफेद कुर्ता पहनकर सलाम ठोक दिया। अरे, तुम्हारे कर्म कैसे हैं पहले ये बताओ? दिल्ली के लिये तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ काम कर करके दिखाओ, तब तुम्हें सलाम करेंगे न। काम करो नहीं, जो करते हैं, उनको करने नहीं दो और सलाम ठोको। ये इसलिए चाहते हैं कि कोई पढ़े नहीं, दिल्ली की शिक्षा को बदलकर दिखाएंगे और बदल रहे हैं। सबसे बड़ा काम है और इस देश के सारे राजनेता नहीं चाहते हैं कि शिक्षा ठीक हो।

तीसरा काम स्वास्थ्य। इन नेताओं ने जानबूझकर अपने अस्पताल खोल रखे हैं। जगह-जगह अस्पताल, सारी स्वास्थ्य सेवाओं पर कब्जा करके बैठे हुए नेता लोग। ये धोती-कुर्ता वाले बना बना कर पैंट पहन कर बैठ गये हैं। सारे स्कूलों पर कब्जा करके बैठ गये हैं, सारे स्कूलों के मालिक ये नेता लोग हैं। सारे अस्पतालों के मालिक ये बनते जा रहे हैं और सारे स्वास्थ्य सिस्टम को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक हमने खोले हैं। मुझसे मिलने आते हैं लोग। इस देश के ज्यादातर राज्यों के लोग, सरकारें खुद देखने आ रही हैं मोहल्ला क्लिनिक कैसे चलते हैं। इनकी सरकारों से भी आ रहे

हैं। जो इनकी बी. जे. पी. की सरकारें हैं, उनके भी, कोई नेता नहीं आते, सेक्रेटरीज को भेज रहे हैं। विदेशों से आ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि आप सब कुछ मुफ्त में कैसे कर रहे हो। क्योंकि बेईमानी नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे हैं और चौथा जो सबसे जरूरी है वो है करप्शन। इस देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हर जगह करप्शन है और कुछ नहीं है और करप्शन के ऊपर ही ये नेतागिरी पलती है। ये कुकरमुत्तों की तरह से इधर उधर से उगते रहते हैं न, जो कुकरमुत्ते उगते हैं, वो गंदगी पर उगते हैं वो कभी सफाई पर नहीं उगते। अगर ये करप्शन खत्म हो गया तो कुकरमुत्ते उगने ही बंद हो जाएंगे और इसको हम खत्म करके दिखाएंगे, जयहिंद, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सदन के समक्ष रिकार्ड में ये कहना चाहता हूं कि ये जो चर्चा है इसका संदर्भ माननीय उच्च न्यायालय का फैसला नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई है और अब वो मामला विचाराधीन है, सबज्यूडिस्ड है तो इसलिए और यह अकसर बहुत बार हुआ है, कोई पहली बार नहीं। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं... बहुत बार किसी भी देश के उच्च न्यायालय के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जाकर बदले हैं और ऐसी अपेक्षा लेकर हम भी गये हैं और हमें पूरी तरह उम्मीद है कि वहां से वो फैसला आयेगा। उस फैसले के आलोक में एल. जी. साहब ने जो आदेश दिया है, वो भी ठीक है, उन्होंने दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ पावर्स उनको दी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला बदलेगा तो वो भी बदल जाएगा। वो महत्वपूर्ण नहीं

है। मैं इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि चर्चा का मूल बिंदु वो है भी, नहीं क्योंकि विजेन्द्र जी उसमें सब्सटेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि सब्सटेंस क्या है। मैं बताता हूं कि सब्सटेंस क्या है, ये विधानसभा लोकतंत्र के तहत बनी हुई विधानसभा है और इस वक्त दिल्ली में बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ा हमला जो हो रहा है, केंद्र में बैठी हुई सरकार, केंद्र की सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, वो लोकतंत्र के ऊपर हो रहा है उसका सब्सटेंस ये है, इसकी उपयोगिता ये है। इन लोगों ने...अभी सत्येंद्र भाई बोल रहे थे गवर्नेस का मजाक बना दिया, गवर्नेन्स तो छोटी चीज है। इन्होंने लोकतंत्र की भावना का मजाक बना रखा है। इन्होंने देश का मजाक बना रखा है इन्होंने देश को मिली हुई आजादी का मजाक बना रखा है! अभी भावना जी बोल रही थी गुलामी की मानसिकता, ये गुलामी की मानसिकता एक्चुअली थोड़ा सा एक्सक्यूज है। भावना की हकीकत तो ये है कि ये दलाली की मानसिकता है। अभी विजेद्र जी कह रहे थे कि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ की कुर्सी जल्दी उखड़ जाती है। कल हमने भी देखी उखड़ी हुई, पूरे देश ने देखी झूठ की कुर्सी जल्दी उखड़ जाती है। कल हमने भी देखी उखड़ी हुई, पूरे देश ने देखी झूठी की कुर्सी कितनी जल्दी उखड़ती है। गुजरात नहीं, पूरे देश ने देखी है। पूरे देश ने देखा है कल और पिछले हफ्ते से पूरा देश देख रहा है झूठ की खाट भी उखड़ जाती है, झूठ की कुर्सी भी उखड़ जाती है। किसी की खटिया खड़ी हो रही है, किसी की कुर्सी उखड़ गई। ये कह रहे थे कि झूठ पिटता बड़ी जल्दी है कल हमने पिटता हुआ भी देखा झूठ। झूठ को पिंजरे में रहने का शौक पैदा हो गया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पिंजरा भी बनवाएंगे चिंता मत करो, तुम्हारे लिए...अभी हमारे महेंद्र भाई चले गये, कहां गये? उन्होंने कहा कि कन्क्लूड कर देंगे। कन्क्लूजन यही है कि यह झूठ पिंजरे

में ही बंद होगा जाकर। आज नहीं, तो कल होगा जरूर। लोगों के अच्छे दिन...आज वो बड़े मशहूर कपिल भाई, कपिल शर्मा जी हम लोग उनका... कपिल मिश्रा नहीं, कपिल शर्मा। हम सब लोग उनके बहुत मुरीद हैं। उन्होंने सवाल किया कि अच्छे दिन इसीलिए आए? अच्छे दिन तो आएं नहीं आए, पर इस झूठ के बुरे दिन जरूर आ गये। इसको पिंजरे में छिपकर बात करनी पड़ रही है और अब पिंजरे में भी छिपकर बात करता है तो पिटता बहुत है, कुर्सी उखड़ गई, खटिया उखड़ गई तो झूठ के तो पाये उखड़ गये। अध्यक्ष महोदय, पर मैं ये बात कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ।

श्री जगदीश प्रधान : जो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जी।

श्री मनीष सिसोदिया : देखो, दिल से तो आदमी ये भी अच्छे हैं। सब इनको पता है।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी हां भर रहे हैं, ठीक है।

उप मुख्यमंत्री : अब क्या करें मजबूरी में उधर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस चीज के लिए इस सदन में चर्चा का मकसद है, मैं उस पर आना चाहता हूं लेकिन उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा और इन लोगों ने बड़ी मेहनत से पिछले आजादी के बाद से, जिस आजादी का ये लोग मजाक उड़ा रहे हें, बड़ी मेहनत से इन्होंने एक सोने की लंका खड़ी करी, देश की राजनीति की सोने की लंका, बड़े आराम से रह रहे थे कि उसमें जिसको चाहे लूट लें फिर अपनी लंका में लगा दिया सोने की लंका खड़ी करी, देश की राजनीति की सोने की लंका, बड़े आराम से रह रहे थे कि उसमें जिसको चाहे लूट लें फिर अपनी लंका में लगा दिया सोने की... वो दुबई से लेकर और पता

नहीं देश में कहां-कहां इन्होंने लंका घर बना रखे थे। इस देश की राजनीति की सोने की लंका इन्होंने खड़ी कर रखी थी जिसको चाहे उठा लाये, जिसको चाहे लूट लाये जिससे चाहे सर्टिफिकेट बनवा लिया। सर्टिफिकेट बनवाने का पैसा ले लिया। एक आदमी को दफ्तर के बाहर पूरे दिन खड़ा रखेंगे। शाम को बोलेंगे कि इतने पैसे देगा तो तेरा काम हो जाएगा। सोने की काम में जाकर मढ़ दिया वो राजनीति की सोने की लंका! उस राजनीति की सोने की लंका में अचानक हलचल मच गई क्योंकि हमारी वानर सेना उसमें पहुंच गई, सब घबरा गये हैं। सबको पता है कि झूठ के दम पर खड़ी हुई सोने की राजनीतिक लंका में अगर कब और वो लंकिनी को भी पता था और आज इनकी लंकिनियों को भी पता है कि झूठ के दम पर खड़ी की गई सोने की राजनीति की लंका में अगर कोई आग लगा सकता है तो वानर सेना आकर लगाएगी और ये वानर सेना ही है सर! मैं बहुत बार इनको देखता हूं पहली बार टिकट लेने के लिए बात हुई थी। बुरा मत मानना, गुमनाम से चैनल में एक पत्रकार थी, नितिन अपना छोटा सा कहीं बिनजेस करते थे, एक छोटी सी कंपनी में सेल्समैन था मोटरसाईकिल पर घूमता था उसके पर्चे ले लेकर के। ये सब कोई...इनमें से अधिकतर लोग वो हैं अध्यक्ष महोदय, सारे जितने बैठे हैं छोटी सी, वकालत करने की मेहनत कर रहे थे वकालत में मेहनत करने की कोशिश कर रहे थे सब, ये आर्किटेक्ट थे, ये भी अपना मायने सब के सब ऐसे हैं कोई राजनीति की लंका का कोई सिपाही नहीं थी, कोई राजनीतिक पुरोहित नहीं था। जैसे उस वक्त था कहीं आदिवासी, कहीं हनुमान जी, कहीं कुछ सब लोग अपना बैठे थे। एक आदमी आया, उसने इकट्ठा किया कि चलो भई राजनीति की सोने की लंका में आग लगानी है, लग गई

आग। जल गई। इनकी जो राजनीति...इन्होंने बड़ी मेहनत कर करके, लूट खसोट के खड़ी की थी और इनको लगता था कि ये साम्राज्य तो हमारा है। ये तो हमारा अभेद्य दुर्ग है। इसमें अब वानर सेना घुस गई है! ये सारी की सारी हलचल इसलिए हो रही है। ये सारी की सारी छटपटाहट इसलिए हो रही है। इनको पता है कि अब तो लंका जलने वाली है। इनको पता है अध्यक्ष महोदय। बड़ी मेहनत करी थी इनहोंने बाढ़ राहत के पैसे चुरा चुराके। बड़ी मेहनत करी थी इन्होंने सड़क और पुल में कमीशन खा खाकर। बड़ी मेहनत करी थी इन्होंने स्कूलों की बिल्डिंग से लेकर स्कूलों में मास्टरों की नौकरियों में भी कमीशन खा खाकर। शहीदों के कफन खा गये, पैंशन खा गये। अस्पतालों की दवाइयों का पैसा खा गये। लाईसेंस बनवाने में कमीशन लेते थे। सब जगह लूट! सी. डब्ल्यू. जी. का घोटाला कर लिया, खेल में घोटाला कर लिया, रेल में घोटाला कर लिया, तेल में घोटाला कर लिया। व्यापम का घोटाला, कोयले को घोटाला, शौचालय तक का घोटाला कर लिया...(व्यवधान) नहीं, नहीं, इसीलिये मैंने इसको लंबा बोला है फर्जी मैं चाहूंगा कि ये सदन के रिकार्ड में रहे कि मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ इस देश में इन लोगों की राजनीति को सोने की राजनीति की लंका बोल रहा हूं और क्यों रहा हूं उसके मैंने अभी उदाहरण दिये हैं। ये स्नूप गेट करवा देते हैं, एनकाउंटर करवा देते हैं किसी का। एकदम लंका वाला शासन है और इनको लगता था कि कोई इनको हिला नहीं सकता। अचानक कुछ लड़के कही से उठे, जंतर-मंतर पर जाकर बैठे। इन्होंने कहा कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो तो चुनाव लड़ कर दिखाओ, चुनाव लड़ा। यहां भी आकर बैठ गये। अब इनको लगा कि अब तो लंका जली। अब तो लंका में धुआं उठा तो अध्यक्ष महोदय, ये सारी की सारी कवायद इन लोगों की लंका को बचाने की है। अब ये कर क्या रहे हैं उस लंका को बचाने के

लिये? जिस जनता ने इनकी लंका में आग लगाने वाली वानर सेना को इस विधानसभा तक भेजा है, उस जनता को परेशान कर रहे हैं। इसलिये ये सदन बुलाया गया है। उस जनता को दुखी कर रहे हैं ये लोग। बहुत मेहनत से सत्येंद्र भाई ने मिल के, इंजीनियर्स ने मिल के 105 मोहल्ला क्लीनिक बनवाये। अब तक आठ लाख लोगों का प्रोफेशनल एम. बी. बी. एस. डॉक्टर्स के द्वारा मुफ्त में इलाज हो चुका है। मुफ्त में टैस्ट हो चुके हैं उनके। ये चाह रहे हैं कि उनको सबको बंद कर दिया जाये। ये तुड़वाने की साजिश रची जा रही है। उन मौहल्ला क्लीनिक्स को। इसलिए ये सदन बुलाना जरूरी था। ये सदन इसलिए बुलाना जरूरी था क्योंकि जगदीश जी की विधानसभा में, कपिल की विधानसभा में, चौधरी साहब बैठे हैं उनकी विधानसभा में और कई जगह डेढ़-डेढ़ सौ, दो-दो सौ बच्चे पढ़ाने को मजबूर हैं एक एक क्लास में आठ हजार कमरे बनवा रहे हैं। फुल स्विंग में काम चल रहा है। ये सब उन कमरों को तुड़वाने की साजिश कर रहे हैं आज। तोड़ने की साजिश करी जा रही है। क्यों? क्योंकि फाईलें मंगा ली गई हैं, अफसरों को धमका-धमका कर फाइलें मंगा ली गई हैं। खबरदार! किसी अफसर ने अगर कोई भी एक्शन लेने की फाइल नहीं भेजी...और उन फाइलों पर जांच बिठा दी गई है। मेरे से पूछे बिना कमरे कैसे बनवाने का आदेश हो गया? मेरे से पूछे बिना मौहल्ला क्लीनिक कैसे शुरू हो गई? बयालीस सौ कमरे नये बनवाने जा रहे हें। बयालीस सौ कमरे बनवाने का प्रस्ताव मेरे से बिना पूछे तुमने सोच कैसे लिया! किसने सोच लिया, उसके खिलाफ क्या क्रिमिनल एक्शन लिया जायेगा, इसकी जांच बिठाई गई है। इन कमरों को तुड़वाने की साजिश हो रही है, मौहल्ला क्लीनिक्स को तुड़वाने की साजिश हो रही है और जिन अफसरों ने ये मौहल्ला क्लीनिक और कमरे बनवाये हैं, उनको जेल में भेजने की साजिश हो रही है। अध्यक्ष महोदय,

उनको अपराधी हकी तरह से कटघरे में खड़े करने की साजिश हो रही है इसलिए ये विधानसभा का सेशन बुलाना जरूरी था। अध्यक्ष महोदय, बहुत कम चल रहा था। दिल्ली में तेजी से काम चल रहा था। 25 तारीख तक ...फिर 30 तारीख तक...नयी नयी तारीखें दे दी जाती हैं। खबारदार! अगर किसी काम पर और काम किया। सबसे पहले फाइलें भेजो पुरानी! तीन साल की, डेढ़ साल की। मौहल्ला क्लीनिक बाद में बनते रहेंगे, स्कूल बाद में...सारा काम ठप्प पड़ा है अध्यक्ष महोदय। अधिकारियों को रोज बुला बुला कर हड़काया जाता है और तो और, मैं इस सदन में रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही थी तो एल. जी. आफिस से अधिकारियों को फोन करके धमकाया गया कि खबरदार! अगर किसी अफसर ने पैटिशन पर साईन किये तो...किसी अफसर की हिम्मत नहीं हुई। उनको धमकी दी गई, ''नौकरी खा जायेंगे तुम्हारी अगर सरकार में पैटीशन पर साईन किये तो।'' मंत्री होने के नाते मैंने साईन किये हैं उस पर और आज ये चले गये कोर्ट में बोले मंत्री की पैटीशन तो मंत्री थोड़ी साईन करते हैं। मंत्री की पैटीशन कैसे साईन होगी? कोर्ट ने कहा, ''नथिंग डूईंग।'' साईन होगी। जस्टिस है अध्यक्ष महोदय! इनको ये उम्मीद थी कि इनको पैटीशन नहीं फाईल करने देंगे सुप्रीम कोर्ट में। इनको उम्मीद थी कि किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी। बहुत बुरी तरह से डराकर रखा हुआ है हरेक अफसर को जो...ये भी मैं रिकार्ड में कहना चाहता हूं कि ये रिकार्ड में दर्ज रहे कि जो भी आफिसर इस सरकार के साथ मिल के थोड़ा सा काम करता है, दो दिन काम करते हुए दिख जाता है, मंत्री के साथ घूमते हुए दिख जाता है, तीसरे दिन उसको एल. जी. हाउस बुला के कहा जाता है कि तुम्हारे सामने दो ही मॉडल हैं या तो राजेंद्र कुमार मॉडल है या चेतन सांघी मॉडल है या तो तुमको बर्बाद कर देंगे सी.

बी. आई. छोड़ के तुम्हारे पीछे, नहीं तो तुम्हारे और उनका झगड़ा करा के तुम्हें सेंटर में पोस्टिंग करवा देंगे। बोला कौन सा चाहिये? इनके साथ काम मत करो। ये स्थिति पैदा कर दी गई है! ऐसा नहीं है कि अफसर काम नहीं करना चाहते, जो अफसर काम करना चाहता है उसको पूछते हैं, ''बहुत पंख लग गये हैं। तुमको राजेंद्र कुमार बनना है या चेतन सांधी बनना है। ये चल रहा है अध्यक्ष महोदय

अध्यक्ष महोदय, मैं क्योंकि ये सब चीजें सदन के रिकार्ड में रखना चाहता हूं, हमने स्कूल्स में...और मैंने कई बार सदन को जानकारी भी दी है इस बात की कि स्कूल्स में प्रिंसीपल्स के सिर पर सारा काम छोड़ा हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिवली। हमने कहा ये प्रिंसीपल पढ़ायें बिचारे या बिल्डिंग की साफ सफाई देखें! यहां तो बिल्डिग भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, दो-दो कमरे की बिल्डिंग तो हैं नहीं, पचास-पचास सौ सौ कमरों की बिल्डिंगस हैं। उनमें गंदगी रहती है तो फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। हमने एक पॉलिसी बनाई है; एस्टेट मैनेजर की पॉलिसी। एस्टेट मैनेजर उनमें नियुक्त किये गये। लगभग लगभग सारे स्कूल्स में एस्टेट मैनेजर बढ़िया काम कर रहे हैं। आज उसी के दमपर हम कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल पिछले वर्षो के मुकाबले में बहुत सुंदर रहने लगे हैं, साफ सुथरे रहने लगे हैं। ये साजिश रची जा रही है कि उन एस्टेट मैनेजर्स को नौकरी से हटा दिया जाये, निकाल के भगा दिया जाये, फाईल तलब की गई है। जानबूझकर के ढूंढ-ढूंढ के फाईल निकलवाई गई हैं, ''एस्टेट मैनेजर की फाईल निकलवाओ।'' ये सारे मुद्दों पर फाईलें मंगवाई गई है एल. जी. आफिस में। एल. जी. आफिस क्या साजिश रच रहा है, देश में क्या साजिश रच रहा है, क्या दुश्मनी निभा रहा है एल. जी. आफिस मोदी जी के कहने पर दिल्ली की जनता से? मोदी जी ने कह

दिया, ''दिल्ली की जनता ने हमको सिर्फ तीन सीटें दी थीं ना, इसको बर्बाद कर दो दिल्ली की जनता को। इसकी दिल्ली की जनता का कोई काम मत होने दो।''

अध्यक्ष महोदय, स्कूल में मैंने एक इंस्पेक्शन की टीम बनाई, सरकारी स्कूलों में। वहां पर मैंने एक ऑफिसर को लगाया, यंग दानिक्स आफिसर को लगाया, एक महीने पहले। मेंने वो टीम बनाई थी मेरे से बिना पूछे हुए उसका ट्रांसफर कर दिया। वहां से ऐजुकेशन डिपार्टमेंट से बाहर शिफ्ट कर दिया। उसको किसी दूसरी जगह भेज दिया। प्राइवेट स्कूल्स...देश के इतिहास में...सारे देश में चर्चा है, कल गोवा में थे। गोवा में भी इस बात की चर्चा थी और करीब डेढ़ सौ अलग-अलग पूरे देश भर के स्कूल्स आये हुए थे डेढ़ सौ दो-सौ विद्यालय के लोग आये हुए थे। वहां पर एक कांफ्रेंस थी, ऐजुकेशन की। वहां पर सारे लोग कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूल्स पर पहली बार नकेल कसी गई है। प्राइवेट स्कूलों को पहली बार बढ़ी हुई फीस...ना सिर्फ जिन्होंने नहीं बढ़ाई थी, उन्होंने बढ़ाने से रोक दिया और जिन्होंने बढ़ाई...जिन्होंने ले ली थी उनसे वापिस दिलवाई गई है। देश के इतिहास में प्राइवेट स्कूल जब से बनने शुरू हुए, चलने शुरू हुए, पहली बार हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ऐजुकेशन डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक एक हो के काम हो रहा था वहां पर सारे कानूनों को समझने वाला एक ऐजुकेशन में लॉ आफिसर बिठा रखा था हमने। इन्हें लगा कि अगर इस लॉ आफिसर को उठा कर एल. जी. आफिस बिठा दिया। अरे! प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट स्कूल के एक्ट को समझने वाले ऐजूकेशन एक्ट को समझने वाले आफिसर की जरूरत ऐजूकेशन डिपार्टमेंट में ज्यादा है या एल. जी. आफिस में ज्यादा है! एल. जी. आफिस में अबप्राइवेट स्कूलों की दलाली का काम शुरू होगा, वहां पर बिठा कर उसको मदद देंगे वो लोग। क्या इंटरेस्ट है एल.

जी. आफिस का प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम को तोड़ना चाहते हैं वो लोग। पूरी की पूरी लॉबी लग गई है। दिल्ली के लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों से बदला लेना चाहते हैं। और वो एल. जी. के माध्यम से सारे ऐसे फैसले ले रहे हैं; गवर्नमेंट स्कूलों की टीम का इस्पेंक्शन करने वाला अफसर हटा दिया, प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल करने वाले अफसर को, जो लीगल कानूनी पकड़ रखता था, उसको हटा दिया। आठ हजार कमरे बनाने वाले अफसर को हटा दिया। मौहल्ला क्लीनिक बनाने वाले अफसर को हटा दिया। वहां से प्वाईट आफ सेल डिवाईस लगते, वहां पर सारी की सारी राशन चोरी रूक जाती। उस अफसर को हटा दिया वहां से। वैट कमिश्नर...पिछले साल वैट में रेडस बंद कराई। बड़े-बड़े डिसीजन लिये। वैट कमिशनर को छुट्टी पर जाना था, मैंने कहा, ''नहीं, अभी छुट्टी पर मत जाओ।'' ऑनेस्ट आफिसर है। उसने कहा, ''हां ठीक है, नहीं जा रहे, आप कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं।'' एल. जी. साहब ने उसको भी बुला के बोला कि तुमको छुट्टी पर जाना है, ''जाओ।'' छुट्टी पर भेज दिया। अब वैट कौन ले के आयेगा? मैं रिकार्ड में कहना चाहता हूं कि इस महीने दिल्ली में वैट नैगेटिव में चल रहा है। क्यों? क्योंकि एल. जी. साहब सरकार को अपने हिसाब से चला रहे हैं। एल. जी. साहब अपने हिसाब से अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। किसी को भी, जो भी आफिसर काम करते हुए दिखता हे, उसको हटा देते हैं। उसको शिफ्ट कर देते हें वहां से मोदी जी के कहने पर। एकदम प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे मॉनीटर हो रही है एक-एक चीज। वहां से सीधे-सीधे मॉनीटर हो रही है और जो भी अफसर काम करते हुए दिखता है, वैट क्लैक्शन हो रहा है, उसको भी रोक दो, सारी चीजों में जानबूझ के टांग अड़ाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, जिससे काम लेना है, हम चुन हुई सरकार हैं, हमें लोगों से काम लेना है। किसकी क्या योग्यता है...मैं ये नहीं कह रहा है कि सारे अफसर बेईमान हैं, पर किस अफसर की क्या योग्यता है, उसके अंदर क्या खास बातें हैं, किस डिपार्टमेंट में काम लेने के लिए किस तरह का ऑफिसर चाहिए, ये तय करने का अधिकार काम लेने वाले को होना चाहिए। लो हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, आप उससे बात तो करो। मना करने पर मानो तो सही। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, बात बदल जाएगी लेकिन जिक्र तक नहीं कर रहे हैं और ढूंढ-ढूंढ कर उन अफसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं जो लोग काम कर रहे थे। हमने अपने अनुभव के आधार पर डेढ़ साल में ऐसे-ऐसे अफसरों को लगा रखा था जो यंग भी थे, डॉयनेमिक भी थे, एकदम सरकारी ठाट-बाट में रहने की जगह पर एकदम चमचागिरी करने वालों को लगा दिया है। कई ऐसे अफसरों को लगा दिया है जिनकी एकमात्र योग्यता ये है कि उन्हें सरकार में सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी काम रोकने का काम किया है, कभी कोई जिंदगी में काम किया नहीं है। ऐसे अफसर हैं। ऐसे अफसरों को बिठा दिया गया है और उसका नुकसान आज दिल्ली की जनता को हो रहा है। आप खुद भुगतभोगी हैं। ये विधान सभा इन-टोटेलिटी एंड यूनिटी भुगतभोगी हैं इस बात की। विधान सभा की सारी गरिमाओं को ताक पर रखकर, लोकतंत्र की सारी गरिमाओं को ताक पर रखकर बोले तुम्हारा सचिव भी नहीं रहेगा, विधान सभा का सचिव भी नहीं रहेगा। अरे! लोकतंत्र में हो, मतलब... हमने ये तो सुने थे चुनाव से पहले नारे कि जो फलाना बोलेगा, उसको पाकिस्तान भिजवा देंगे। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, सको पाकिस्तान भिजवा देंगे। जो ऐसा नहीं करेगा, उसको पाकिस्तान भिजवा देंगे। पर जिस विधान सभा में हमको वोट नहीं मिलेगी, उसी को हम पाकिस्तान

बना देंगे, उसमें हम पाकिस्तान के हिसाब से काम करने लगेंगे। ये तो पहली बार देख रहे हैं। तालिबानी शासन है क्या? ऐसे ही हटा दोगे किसी को कहीं से! विधान सभा की अपनी गरिमा है। विधान सभा के अंदर किए गए किसी एक्ट पर, विधान सभा के अंदर लिए गए निर्णयों पर तो कानून कोर्ट में भी नहीं होता, वहां भी सीमाएं हैं, कोर्ट की भी सीमाएं हैं। विधान सभा के डिसीजन्स पर तो इंटरप्रेट, इंटरफेयर करने की, उसकी भी अपनी... कोर्ट सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग, सबसे बड़ी इंटरप्रेटिंग बॉडी जो संविधान ने बनाई है, उसको भी कहा गया है कि तुम्हारी सीमाएं हैं। जब तुम विधान सभा के मामलों में हस्तक्षेप करोगे तो, कितना कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो।

अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजों के जरिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जानबूझकर दिल्ली में सारे काम ठप्प करने की साजिश रची जा रही है और मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में यकीन करो नहीं तो जैसे खाट खड़ी हुई थी और कैसे कल कुर्सियां गई थी और जैसे सच को, आपने कहा ना अभी कि 'झूठ के पैर नहीं होते, वो पिटता है एक दिन।' झूठ हमने कल पिटता हुआ देख लिया। आगे बहुत ही बुरी तरह से पिटने वाला है। झूठ याद रखना, झूठ बहुत बुरी तरह से पिटने वाला है। लोकतंत्र से मत खेलो। इस देश में खून पसीना बहाकर कर, कुर्बानी दे देकर लोकतंत्र लेकर आए हैं। इस लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई हैं, इस लोकतंत्र को बर्बाद मत करो। आप जैसे लोगों की वजह से लोकतंत्र इवोल्व होने की जगह कई बार कमजोर पड़ गया है। ऐसे ऐसे लोग जब-जब सत्ता में आते हैं, लोकतंत्र कमजोर पड़ता चला जाता है। अभी आप कह रहे थे; मौका है, बता दीजिए अपने आंकाओं को, मौका है लोकतंत्र से खेलना बंद कर दें। नहीं तो सोने की लंका में ऐसी आग लगेगी कि सांस लेने के लिए नहीं छोड़ेगी जनता। सोने की लंका

में ऐसी आग लगाएगी कि ये वानर सेना कि सांस लेने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे ये सारे लोकतंत्र दुश्मन। सोने की लंका को तो जलकर खाक होना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस सोने की लंका, इस राजनीति की... जो इन्होंने बड़ी मेहनत कर करके खड़ी करी थी सोने की लंका, इसमें ये वानर सेना घुस चुकी है और हमारा कमिटमेंट है या तो जलकर खाक हो जाएंगे या इस सोने की लंका को जलाकर खाक कर देंगे और कह दीजिए अपने आंकाओं से जाकर, डरने वाले नहीं है। 67 के 67 को जेल भेज दोगे, खत्म करवा दोगे तब भी इन्हें...रक्त बीज हैं, एक मरेगा तो 67 पैदा हो होंगे आज मैं चेतावनी दे रहा हूं आपको। ये मत सोचना कि इस देश की जनता बेवकूफ है। देश की जनता ने बहुत सोच-समझकर तीन दिया हैं और तीन लायक नहीं छोड़ेंगे और सबको मार दो, सबको फांसी चढ़ा दो, सबको कत्ल करवा दो। सबको कत्ल करवा दो लेकिन एक बात बताता हूं रक्तबीज हैं रक्तबीज, एक कतरा खून का गिरेगा तो हजार पैदा होंगे। बर्बाद करके रख देंगे तुम्हारे सोने की लंका में रहने वालों को, बर्बाद करके रख देंगे तुम्हारी सोने की लंका को, आग लगा देंगे...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जनता ने चुनकर भेजा हैं हमें...

उप मुख्यमंत्री : तीन भेजा है...(व्यवधान)

(सदन में सामूहिक नारेबाजी)

उप मुख्यमंत्री : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, बैठिए, बैठिए।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आन रिकार्ड कि संदीप कुमार के बारे में भी बात होगी और उससे जुड़े हुए और मसलों पर भी बात होगी। अगर हिम्मत है तो उठकर मत जाना वापस, सुनकर जाना पूरी बात...

अध्यक्ष महोदय : मैं दे रहा हूं समय...

उप मुख्यमंत्री : अगर सीने में कलेजा है तो उठकर भागना मत चोरों की तरह! गद्दारों की तरह! सुनकर जाना पूरी बात। कपिल मिश्रा जवाब देंगे तुम्हारी बात का।...हिम्मत है तो उठना मत यहां से आज विधान सभा में से, विधान सभा सत्र में से!

अध्यक्ष महोदय : सदन का समय,...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, त्यागी जी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा बाकी है दो मिनट बैठे प्लीज, बैठिए। दो विषय जरा बाकी हैं अभी जो बहुत गंभीर. ..महेंद्र जी प्लीज, प्लीज बैठिए अब प्लीज, मेरी रिकवेस्ट है, बैठिए। सदन का समय एक घंटा बढ़ाने की मैं आज्ञा चाहता हूं सब सदस्यों से।

(सदन से सामूहिक सहमति मिलने पर सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।)

मुझे नियम 54 के अंतर्गत दो नोटिस प्राप्त हुए हैं एक विजेन्द्र गुप्ता जी का जिसका मैंने पहले जिक्र किया और एक अमानतुल्लाह जी का भी प्राप्त हुआ था। ये दोनों मैं स्वीकार कर रहा हूं और इस पर विजेन्द्र गुप्ता जी को बोलने की इजाजत देने से पहले एक प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने जो लिखकर

दिया है उसमें, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, आप नेता के विषय में इसमें. ..दो मिनट रूक जाइए, मैंने एक्सेपट किया है। मैं चर्चा करवा रहा हूं और जिसकी आप बात कर रहे हैं...नहीं, इफ एंड बट लगेगा। आप जो मर्जी आए लिखकर दे दें। जो आपने लिखा है वो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, बाहरी व्यक्ति हैं। मैं उन पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दे रहा हूं...आप बोलिए संदीप कुमार के विषय में, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आपका नोटिस, ...एक सैकेंड रूक जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए मैं एक बात कह रहा हूं सभी सदस्य शांत रहे प्लीज और शांतिपूर्वक सदन की चर्चा को चलने दें। मैं संदीप कुमार पर सीमित रखने के लिए...आप जो मर्जी आए बोलें। संदीप कुमार की चर्चा को मैं एलाउ करता हूं। करिए शुरू विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की बात हो रही है यहां और लोकतंत्र का गला घोटा जाता है। विपक्ष का माईक बंदकर के उप मुख्यमंत्री जी चिल्ला-चिल्ला कर माईक चलाकर बोलते हैं। अपनी भाषा को, अपनी बॉडी लग्वेज को संयम में रखिए आप। इस बात को आप ध्यान रखा करिए और केंद्र में भी जो सरकार है, वो चुनकर आई है। पूर्ण बहुमत की सरकार है। गलतफहमी में मत रहिए आप।...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप चर्चा...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आपकी चर्चा का उन्होंने उत्तर दे दिया। वो विषय समाप्त हो गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सुबह से चर्चा चल रही है लेकिन पता नहीं क्या?

अध्यक्ष महोदय : हवा तो 8 महीने पहले आपकी थी। आप हवा की बात कर रहे हैं!

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सत्तारूढ़ दल को इस चर्चा पर रेसट्रिक्शन और सेंसर लगाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, आप चर्चा करिए।...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : चर्चा को निर्भीकता से करने में परहेज करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं। अगर बाहर के व्यक्तियों पर आप चर्चा करेंगे, कल को ये सदन भी चर्चा करेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बाहर और अंदर की बात ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हां, करिए आप चर्चा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मामला गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप ही बार-बार ऑब्जेक्शन लगाते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इतने रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका ही आब्जेक्शन लगता है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुझे नहीं समझ में आया, क्या डर है, क्यों बचा रहे हैं ऐसे लोगों को?

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई अरूण जेटली का नाम लेता है तो आप सबसे पहले खड़े होते हैं। आज तय कर लीजिए अगर आपको चर्चा करनी है तो तय कर लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 31 अगस्त, 2016 तेरह नं. सीट। 26 अगस्त, 2016 इस सीट पर बैठे थे महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री। स्पीकर साहब ने, जब मैंने पत्र लिखा उसके पीछे एक दर्द था और सदन के प्रारंभ होने के तीन दिन पहले लिखा लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब ये कार्य सूची सामने आई तो संदीप कुमार इसमें ये नदारद थे, मेरे पास दो कार्य-सूची हैं आज की। एक कार्य-सूची ये है और एक कार्यसूची ये है। एक कार्य-सूची वो है जिसमें से संदीप कुमार नदारद है। 67 सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने एक ने भी ना नियम-280 में ना नियम 55 की चर्चा में इसका कोई रेजल्यूशन दिया। जब विपक्ष ने ये बात सदन में उठाई तो बाद में संदीप कुमार को इस चर्चा में जोड़ा गया। वो भी पौने आठ बजे, चर्चा पहले दौर में प्रारंभ होनी चाहिए थी, आपने पांच बजे बदला।

अध्यक्ष महोदय : देखिए विजेन्द्र जी, मैं आपको फिर रोक रहा हूं बीच में।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मत रोकिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल रोक रहा हूं, और मैं रोकूंगा। आप सच को सुनिए। आपका नियम-54 के अंदर नोटिस, नहीं-नहीं बिल्कुल नहीं, आप अध्यक्ष के नियमों पर...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जिसने आत्महत्या की...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कल कर्नल देवेंद्र सहरावत के बारे में नहीं सुनना चाहते। आप संदीप कुमार के बारे में नहीं सुनना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब मना किया है आपको?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप आशुतोष के बारे में नहीं सुनना चाहते। आप क्या सुनना चाहते है?

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अपने मुंह मियां मिट्ठू बनो, अपनी वाह-वाही खुद करो, वास्तविकता ये है। अध्यक्ष जी, एक मंत्री...अगर कहूं तो लगभग सवा साल में तीसरा मंत्री जिसको कैबिनेट से आपने, यानी की कुल 7 की कैबिनेट है, तीन मंत्री आपने बदले, एक तो अभी भी खाली है, 67 नंबर पे उनको, आपने 13 से उठाकर के 67 नंबर पर बिठाया मंत्री जी को। क्यों बिठाया है? क्योंकि 15 दिन तक उनकी सीडी सरकार के पास आ गई थी, उसको छुपाया। एक सीडी अभी मेरे कमरे में भी इंतजार कर रही है। पत्रकारों को मैंने बुलाया हुआ है उस सीडी को सुनवाने के लिए। 15 दिन सीडी को दबाया गया, सीडी को प्राइवेट, जानबूझकर और देखिए, सिर्फ दबाया ही नहीं है, 31 अगस्त को जब वो मीडिया में बात आती है, तो एक तारीख को ऐसी सीडी चलाने वालों को, आम आदमी पार्टी एक ब्लॉग के माध्यम से जस्टीफाई करती है। अध्यक्ष जी, आप कहते हैं कि संदीप की चर्चा करो, ऐसे कुकर्मो को बढ़ावा देने वालों की बात करने वालों की चर्चा ना करो। मैं इसकी किसी व्यक्ति का ब्लॉग नहीं मान रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी की सोच है। ये देश के सामने

आनी चाहिए। दिल्ली की जनता के सामने आने चाहिए। इसके अंदर जो लिखा गया है; संदीप कुमार की वकालत की है आम आदमी पार्टी ने। संदीप कुमार की वकालत की है और उन्होंने सिर्फ संदीप कुमार की वकालत नहीं की, उन्होंने सदन में बैठे हुए सारे विधायकों को कहा है कि आप ये सब काम करो। अब "Public Figure Probably can not openly drink, smoke and flirt with the opposiete sex but he or she is entitled to his or her private space or he or she should not be chased there so whatever Sandeep Kumar had done in private without inviting any complaints from his partner, should it create ripples in media and politics जब हमारे सारे विधायकों को पब्लिक फीगर कह रहे हैं...आप ये सब काम करो प्राईवेटली तो संदीप कुमार का प्रैक्टीकल सामने आया और आम आदमी पार्टी की सोच सामने आई। इसके आगे देखिए जिसमें लिखा गया Virginity is not a virtue anymore, Virginity यानि की विवाह से पूर्व एक व्यक्ति जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बंधन है, जो सीमाएं हैं उसका ध्यान करें, Virginity for younger generation these a hint of being left behind in the social race जो वर्जिनिटी का पालन करेगा वो सोशल रेस में पीछे रह जाएगा and such a person is not a subject of envy अध्यक्ष जी, he or she is neither hot nor cool ये यंगर जनरेशन को कहा गया है कि अगर आप वर्जिनिती का पालन करेंगे तो सोशल रेस में आप पीछे रह जाएंगे और ये माना जाएगा कि आप अनवांटेड हैं, अनडिजायर्ड हैं, आप अगर युवतियों के बारे में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हो और उनको डिस्क्रेज और डिग्रेड कर रहे हैं कि अगर आप वर्जिनिटी का पालन करेंगे तो आपका मतलब ये है कि आप अनवांटेड हैं। आपको कोई लाइक नहीं कर रहा है, आप अनडिजायर्ड है आपको कोई

पसंद नहीं कर रहा है, आप अनडिजायर्ड है आपको कोई पसंद नहीं कर रहा। ये भाषा और वो भी संदीप कुमार जो सीट नंबर 13 पर बैठते थे। उनको केंद्र मानकर इस आम आदमी पार्टी के इस आर्टिकल में ये बातें कही गई। अब आगे देश के महान पुरूषों के बारे में लिखते हैं History is also a vitness to the fact that top leaders of the Congress in 1910 were worried about Gandhiji's relationship with Sarla Chaudhary who was distantly related to Ravinderr Nath Tagore मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं दो-तीन लाइनें पढ़ देता हूं...Gandhiji in his later days slept naked with his two nieces to experiment with celebacy वाह! यानि की संदीप कुमार और गांधी जी दोनों में समानता है। दोनों में समानता है। Pandit Nehru has told him like Ashutosh told to Sandip kumar वैसे ही पंडित नेहरू ने गांधी जी को Pandit Nehru had told him not to do so as the country would rise against him but Gandhiji did not budge. पर गांधी जी माने नहीं, यानि कि इन्होंने गांधी जी को और संदीप कुमार को इतना मिला दिया कि हमारे मुंह में गांधी जी की जगह संदीप कुमार, संदीप कुमार की जगह गांधी जी आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कि आप पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने और मुख्यमंत्री जी...विशेष तौर पर छोटी-छोटी बात पर सुबह से ट्वीट करना प्रारंभ करते हैं, उन्होंने इस विषय पर अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की कि जो पार्टी की लाइन है, क्या आपने इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या आपने ये कहा कि इसको साइट से हटाइये, विदड्रा करिये, हम इससे सहमत नहीं हैं। क्या उसके लिए कोई पनिशमैंट तय किया? क्या कोई कार्रवाई हुई? आप क्या संदेश देना चाहते हैं अध्यक्ष जी, मैं आपके माधयम से सरकार से और सरकार में बैठे हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूं? क्या सोसाइटी को

संदेश देना चाहते हैं? क्या यही झलक पंजाब में नजर आ रही है, जो बार-बार शिकायतें आ रही हैं? क्या यही झलक सोनी मिश्रा के मामले में नजर आई जिसने सुसाईड कर लिया क्योंकि आपके आम आदमी पार्टी के नेता जेल में है और उसने कहा कि मुझे सैक्सुअली एब्यूज करने की...ये बार-बार प्रताड़ित किया गया, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूं। कोई एक मामला नही है, यहां अनेकों मामले हैं! क्या ये सैक्स स्कैंडल पार्टी है? क्या अभी तक...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अरे आप बैठिये ना, आप बैठिये, आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री शरद चौहान : ...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, ये क्या भाषा बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलूंगा आगे से।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिये-बैठिये प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : धमकी दे रहे हैं आप! गुंडागर्दी हो रही है यहां पे! जिस तरह की...फाड़ देगा तू, अभी मैं पुलिस में कम्पलेंट करूंगा और तुम्हें पकड़वाऊंगा। आप मुझे सदन के अंदर गाली दे रहे हो। सदन के अंदर इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। काट दे, आजा। गुंडे बैठा रखे हैं यहां पर आपने। गुंडे बैठा रखे हैं आपने। आ जा इधर...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : गुंडागर्दी हो रही है यहां पर। इनको निकालिये अध्यक्ष जी बाहर।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं, हम इनकी भाषा पर...क्यों यहां गुंडागर्दी हो रही है? यहां पर साफ धमकी दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बिल्कुल भाग नहीं लेंगे हम चर्चा में यहां पर। कमाल कर रहे हैं आप! इतनी बद्तमीजी यहां पर सुबह से शाम तक गाली-गलौच, गुंडागर्दी इसके अलावा यहां कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं बैठेंगे यहां।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां चाह रहा हूं...एक सैकेंड जगदीश जी, नहीं। एक सैकेंड मेरी बात सुन लीजिए। विजेन्द्र जी।

...(व्यवधान)

(विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप मुख्यमंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री : इनकी हिम्मत नहीं है यहां पर इस डिबेट में टिक पायें! यहां इनकी हिम्मत नहीं है। भाग गये! मैं पहले कह रहा था बी. जे. पी. के लोग भाग जाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है जो ये सच में शामिल हो सकें, सच में बहस कर सकें! हिम्मत नहीं है, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। मैं इस सदन में आज दो बार चेतावनी दे चुका था कि अगर हिम्मत है तो इस बैठक में भाग लेकर दिखाना वरना मूंछ कटा कर फेंक देना!

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)   170 - 181   9 सितम्बर, 2016

श्री कपिल मिश्रा (पर्यटन एवं मंत्री) : XXXXXXX

---

xxxxxxx (नियम – 283 के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 12.02.2026 के अनुपालन में माननीय मंत्री श्री कपिल मिश्रा के वकतव्य सहित विधानसभा की कार्यवाही का अंश पृष्ठ संख्या 170-181 को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया।)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमानतुल्लाह जी।

श्री अमानतुल्लाह खान : बहुत-बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, बात करने का मौका देने के लिए। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं जैसा कि आपको मालूम है। कल 2.30 बजे वक्फ बोर्ड के ऑफिस में, जो दरियागंज में है, वहां पर ए. सी. बी. ने छापा मारा। मैंने जब उनसे पूछा... मैं वहां था नहीं तो मुझे बताया गया, मैं वहां जब गया, तो मैंने उनसे पूछा कि भई आप लोगों ने क्या छापा मारा है; क्यों छापा मारा है; और आप क्यों आये हो? तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम हुआ है कि कर्मचारियों की जो आपने नियुक्ति की है, उसमें भारी गड़बड़ी हुई है तो मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बोडी है, जो पार्लियामेंट के जरिये पास किए गए वक्फ एक्ट, 1995, दिल्ली वक्फ रूलस, 1997 के तहत् काम करता है। इसमें जो कर्मचारियों का सैक्शन है, वो 64 हैं और जब मैंने वक्फ बोर्ड संभाला था, उस वक्त में वहां पर 42 लोग काम करते थे, जिसमें से पियून, ड्राईवर सिर्फ उसमें 22 लोग ऐसे थे जो कलम चलाना जानते थे। दिल्ली में तकरीबन 2000 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, 2300 किरायेदार हैं। 350 से ज्यादा अलग-अलग अदालतों में केस चल रहे हैं। 2300 किरायेदार में से, वक्फ बोर्ड के जो पुराने रिकाड्र्स हैं, उसमें 450 से 500 किरायेदारों को टच करते थे। वक्फ बोर्ड के पास जो गवर्नमेंट से ग्रांट आती थी, कुछ एड के जरिये और सिर्फ 7 लाख रूपया महीना किराया आता था। वहां पर आठ साल से बेवाओं की पेंशन बंद कर दी गई, पैसा न होने की वजह से। चार-चार, पांच-पांच महीने इमामों की तनख्वाह नहीं दी जाती थी, कोई और स्टाफ की तनख्वाह नहीं दी जाती थी, पैसा न होने की वजह से, पैसा नहीं था तो ये कमी थी। जब मैं आया, नया रूल आया, नया एक्ट आया 2013 उसमें कहा गया कि जो पुरानी किरायेदारी है,

उसको नये सिरे से करो, नये एक्ट के हिसाब से करो। उसमें मैंने वहां देखा कि सारा रिकार्ड विदाउट कम्प्यूटर है, कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, हमें यह नहीं मालूम है कि हमारी जमीन है तो है कहां और कितनी है? जब मैं आया वहां पर तो आने के बाद महसूस किया कि वहां पर स्टॉफ की कमी है और जो सैंक्शन हमें मिला हुआ है, उसको पूरा किया जाये, तो मैंने कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर 22 लोगों को भर्ती किया और वो भी अखबार में एड करके। जो नेशनल अखबार है, मेरे पास जो 9 अखबारों की कटिंग है, इन अखबारों में मैंने एड देकर के जो इंटरव्यूज की डेट दी गई, उस इंटरव्यू में बुलाया गया और इंटरव्यू की डेट जो है 24.04.2016 को हमने अखबारों में एड दिया। राष्ट्रीय सहारा है, इन्क्लाब है, इन सारे अखबारों में हमने एड दिया और एक 13.05.2016 से 01.06.2016 तक इंटरव्यू हुए। उसमें मैंने एक रिक्रूटमेंट कमेटी बनाई। उसमें एक मैम्बर थे, सी. ई. ओ. थे और एक सी. एल. ओ. जो चीफ लीगल ऑफिसर थे, वो सब थे, वो सब थे, जो एक कानून है, ये जो था सारा कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर था। पॉवर है ऑटोनोमस बॉडी है, जरूरत के हिसाब से आप 89 डेज पर, आप इंटरव्यू करके रख सकते हो लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने जो पूरे जाबते थे उन जाबतों को पूरा करने के बाद, मैंने वहां पर रखे। आज भर्ती करने के बाद ये हाल है, जहां 7 लाख रूपया महीने की आमदनी थी, आज वहां एक करोड़ के आस-पास महीने की आमदनी है। जहां बेवाओं की पेंशन बंद थी, वहां पर 2000 से ज्यादा बेवाओं की पेंशन 30 लाख रूपये महीना, जहां 500 रूपया दिया जाता था आठ साल पहले, उसको बढ़ाकर के हमने 1500 रूपये किया और आज हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं 100 बच्चों को । 100 बच्चों को स्कॉरशिप दे रहे हैं तकरीबन 50 लाख रूपया हम स्कॉलरशिप में देने जा रहे हैं। इमामों

की तनख्वाह पहली तारीख को हम लोग रिलीज कर देते हैं। बेवाओं की पेंशन एकाउंट के जरिये 1500 रूपये जितनी दिल्ली सरकार देती है पहली तारीख को...इस बार हमने पेंशन जो है एकाउंट में दे दी। जो स्टाफ है उसको तनख्वाह महीने की आखिरी तारीख को हम दे देते हैं। हमारे पास कोई ड्यूज नहीं है। हम अब 15 अक्टूबर को दो स्कूल कायम करने जा रहे हैं। हम लोग इस साल में पांच स्कूल बनाने जा रहे हैं, जो डी. पी. एस. के लेवल के स्कूल होंगे। पांच हम खोलने जा रहे हैं। दो 15 अक्टूबर को इन्शा अल्लाह हम खोल देंगे। वजह क्या है कि ये, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि ए. सी. बी. ने वक्फ बोर्ड पर छापा मारा। पिछली मर्तबा जो विधान सभा सत्र हुआ था, उसमें हमने कहा कि 1100 बीघा प्रॉपर्टी पर डी. डी. ए. ने कब्जा किया हुआ है और वो प्रॉपर्टी 1100 बीघा तकरीबन 27 हजार करोड़ की बनती है जो मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी है। 27 हजार करोड़ की, हमारा एक मॉल है मेरिएट मॉल जो साकेत के अंदर है हमें पता लगा कि यह कब्रिस्तान की जमीन पर बना दिया गया। मेरिएट होटल फाइव स्टार होटल, साकेत मॉल है जो खिड़की गांव की जमीन पर बना दिया गया, वहां पर मालूम हुआ कि 2 दुकानें वहां पर जो है, इनकी भी हैं, गांधी जी की। राहुल गांधी की दो दुकानें वहां हैं। वहां अगले दिन हमारे पास ए. सी. बी. का नोटिस आ गया। परसों स्कूल, यूनिवर्सिटी की जमीनों की जब हमने तलाश करनी शुरू की तो हमें पता लगा कि हमारी 62 बीघा जमीन है, उसकी आज कीमत 286 करोड़ रुपये बनती है जो सिर्फ 15 हजार रूपये में मतीन अहमद ने शीला दीक्षित से मिलकर के उस जमीन को वहां पर लीज पर दे दिया। 1995 एक्ट के हिसाब से तीन साल से ज्यादा किसी

को आप लीज नहीं दे सकते। इन लोगों ने इनडेफिनेट टाइम के लिए यानी कि हमेशा के लिए 286 करोड़ की जमीन सिर्फ 15 हजार रूपये में लीज पर दे दिया। मैंने एक चिट्ठी ए. सी. बी. को लिखी। ये चिट्ठी मैंने एल. जी. साहब को लिखी, मैंने प्रैस कांफ्रेंस की, अगले दिन मेरे आफिस में ए. सी. बी. ने छापा मार दिया। मैंने उनसे कहा कि मैंने जो आपकी चिट्ठी लिखी थी, क्या वो फाइल आप लेने आये हो? उन्होंने कहा, नहीं साहब, आपने जो कर्मचारी रखे हैं, उस नियुक्ति में आपने गड़बड़ की है, यह हमें कंप्लेंट मिली। हम उस कंप्लेंट पर आपके पास आये हैं। आप हमें वो दस्तावेज दो, हमें फाइलें दो, सारी चीजें दो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मेरी छानबीन कर रहे हो, आप जांच कर रहे हो कि अगर एक रूपये को बेईमाना आप मेरा साबित कर दो, मुझे आकर बता देना, मैं वक्फ बोर्ड भी छोड़ दूंगा, विधायिका भी छोड़ दूंगा और दिल्ली छोड़ कर भी चला जाऊंगा। मैंने उनसे यह कहा कि जो फाइलें मैंने आपको दी हैं, जो मैंने हारून युसूफ के बारे में आपको कंप्लेंट लिखी है, हारून युसूफ वहां पर चेयरमैन थे। जब वो चेयरमैन पद से चले गये तो वो मंत्री बने। उस वक्त में उन्होंने 9 साल तक वक्फ बोर्ड का एक ड्राइवर इस्तेमाल किया। वक्फ बोर्ड ने 15 लाख रूपया उसकी तनख्वाह दी। उनके बारे में मैंने कहा कि इस आदमी ने वक्फ बोर्ड का पैसा इस्तेमाल किया, इस आदमी ने वक्फ बोर्ड का ड्राईवर इस्तेमाल किया, वक्फ बोर्ड ने आठ साल तक इस आदमी की तनख्वाह दी। इसने अपनी पॉवर का गलत इस्तेमाल किया। इसकी छानबीन करके, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाये। मैंने ये दोनों फाइल ए. सी. बी. को दी, एल. जी. साहब को मैंने खत लिखा। कपिल भाई जल बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन्होंने 500 करोड़ के घोटाले

की फाइल, एक चिट्‌ठी ए. सी. बी. को दी, क्या हुआ कि इनके पास भी. ..ए. सी. बी. ने शीला दीक्षित से नहीं पूछा, कांग्रेस के किसी आदमी से नहीं पूछा, जिन लोगों ने गड़बडी की, उनसे नहीं पूछा, बुलाया किसको? कपिल मिश्रा जी को। ऐसे ही यहां हुआ। मैंने मतीन अहमद के खिलाफ, मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ, मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ, मैंने कांग्रेस के खिलाफ, किसने मॉल बनवाया, किसने होटल बनवाया, किसने जमीनें बेचीं, किसने यह घोटाला किया, उसकी छानबीन नहीं की। छानबीन किसकी कर रहे हैं जो ईमानदारी से काम कर रहा है। अब से पहले जब मैं वक्फ बोर्ड में गया था तो वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट माना जाता था। मुझे पांच महीने हुए हैं, एक भी अखबार ने पांच महीने के अंदर यह नहीं लिखा कि वक्फ बोर्ड में किसी किस्म की कोई गड़बड़ी हो रही है। हर दिन वक्फ बोर्ड की खबर किसी न किसी बड़े अखबार में आती है और अच्छाई की खबर आती है कि आज वहां काम हो रहा है। अगर कोई कंप्लेंट लेकर हमारे पास आता है तो विदिन ए मिनट, विदिन एक घंटा, एक घंटे के अंदर हम उसकी कंप्लेंट को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन यहां अजीब सा इत्तेफाक है कि एल. जी. साहब आज दिल्ली को चला रहे हैं। एल. जी. साहब आज ए. सी. बी. को चला रहे हैं तो एल. जी. साहब के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शीला दीक्षित को नोटिस करके बुला लें। एल. जी. सहाब के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है, मतीन अहमद को बुला लें। एल. जी. सहाब की औकात नहीं है कि वो इनको बुलायें। अगर वाकई वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहते हैं, वाकई वो ए. सी. बी. को अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं तो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस की हुकुमत थी, 15 साल तक कांग्रेस ने हुकूम की, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उनके टाइम में फाइव स्टॉर होटल बना

कब्रिस्तान में, उनके टाइम में मॉल ना, उनके टाइम में यह पंजाब छोड़ के 286 करोड़ की प्रोपर्टी जो है, यह घपला किया गया, हमारा एक अधिकारी भी उसमें शामिल था, जो वहां पर सी. ई. ओ. था, उस वक्त में, वो भी शामिल था। उसने अपने ससुर को 1100 गज जमीन वहीं पर पंजाब छोड़ के सिर्फ 25 पैसे स्क्वेयर यार्ड के हिसाब से दी गई। आज उसकी कीमत 46 हजार स्क्वेयर यार्ड है। 25 पैसे के हिसाब से दी गई! अगर वहां पर उसका जेन्युइन किराया लगाया जाता तो एक्ट है, 7 करोड़ 15 लाख रूपये किराया बनता था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 15 लाख रूपये में 63 बीघा जमीन दे दी, जसकी कीमत 286 करोड़ है। तो हम यह जानना चाहते हैं एल. जी. साहब से कि अगर आप वाकई मुसलमान हो तो आपके अंदर मुसलमानों का दर्द होना चाहिए। मुसलमानों के कब्रिस्तान बिक गये, मुसलमानों के कब्रिस्तान पर मॉल बन गये, मुसलमानों के कब्रिस्तान पर मार्किट बन गई, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपकी औकात है तो आप मतीन अहमद को बुलाकर देखो, आप शीला दीक्षित को बुलाकर देखो, आप हारून युसूफ को बुलाकर देखो। ये नहीं बुलायेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं बुलायेंगे कि अगर कांग्रेस घपला करती है तो बी. जे. पी. उसको सपोर्ट करती है। देखिये, कांग्रेस वालों के भ्रष्टाचार की हमने बात की। बी. जे. पी. की ए. सी. बी. है, ए. सी. बी. बचा रही है उनको। इन दोनों की मिलीभगत है, इन दोनों का तालमेल है। जब कांग्रेस हुकुमत में होती है तो बी. जे. पी. इनको बचाती है और जब बी. जे. पी. हुकुमत में होकर गबन करती है तो कांग्रेस इनको बचाती है। ये दोनों एक-दूसरे से मिले हुए हैं। आप देखिये, हमारे पर मुस्तकिल मुझ पर लगाम लगाया हुआ है। मैं जब से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना, पांच महीने हुए, मुझे जेल में भेज दिया इन्होंने। कभी कोई कंप्लेंट कर देते हैं, मुझे मुस्तकिल धमका रहे हैं नजीब जंग साहब

के भाई सफर जंग वक्फ बोर्ड ऑफिस में आये, सी. ई. ओ. से बदतमीजी की, हमारे स्टाफ से बदतमीजी की। हमसे कहा कि मैं एल. जी. को यहीं बुला लूंगा। ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमें दहशत में लाना चाह रहे हैं। ये माहौल क्रिएट कर हरे हैं, हमें डरा रहे हें, धमका रहे हें, हमें दहशत में लाना चाह रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और हमने साबित करके दिखाया। जिस वक्फ बोर्ड की इनकम 7 लाख रूपये थी, 5 महीने में उसको एक करोड़ से ज्यादा करके दिखाया और ऐसा भी करेंगे कि 10 करोड़ तक इसको लेकर आयेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : बस आखिरी, सोमनाथ जी। आप किस विषय पर बोलेंगे?

श्री सोमनाथ भारती : कॉमन।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब कॉमन नहीं। कॉमन विषय खत्म हो गया।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत दर से रोक रखा है।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, अमानतुल्लाह जी के विषय पर कुछ बोलना है, तो बोल लीजिए।

श्री सोमनाथ भारती : दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन ने बहुत कुछ वो होते हुए जो देखा जो कि मुझे लगता है इतिहास में कभी हुआ नहीं। आज जिस तरह से मनीष जी ने अपनी पीड़ा जाहिर की, जिस तरह से जैन साहब ने अपनी पीड़ा जाहिर की, ये सब ऐतिहासिक है। इन कारणों

से विजेन्द्र गुप्ता जी से रूका नहीं गया, जो अभी बात अमानत भाई ने की कि 7 लाख रूपये से एक करोड़ कैसे हो गया और किस तरह के वेस्टेड इंट्रेस्ट के लोग हम सब को तंग करने में लगे हुए हैं, जो कपिल भाई बात की, मुझे लगता है कि आज के बाद हम सब साथियों पर बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं। ये कोई आसान नहीं कर रहे हैं हम। हम यहां पर अपने लिए मौत का बुलावा बुला रहे हैं एक तरह से। जिस तरह से हमने अपनी बातें रखी हैं, जिस तरहज से हमने वो सारी संभावनाएं, वो सारी मुसीबतें जो सरकार झेल रही हैं, जो अधिकारी झेल रहे हैं, किस तरह से डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को रोकने की, बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है आपको रूल 254 के तहत मानीय एल. जी. महोदय को सदन की गरिमा की जो मंशा है, हम सब ने जो आज जाहिर किया है, इसको वहां भेजना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मानीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि इस सरकार को काम नहीं करने की जो इन्होंने ठानी है, मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सदन आपके माध्यम से एल. जी. महोदय तक यह बात पहुंचा दें कि सदन शांत नहीं बैठेगा। सदन में आये लोग, ये वो लोग हैं, जो कि आंदोलन से निकाल कर आये हैं तो ये सोच कर आये हैं, कुछ भी हो जाये, जान चली जाये, आज माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जान भी चली जाये या तो हम जल जायेंगे या जला देंगे। एक ही होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं 254 एक रूल है उसके तहत आप एल. जी. महोदय को सदन की मंशा बता सकते हैं। आप कृपा करके आज जो कुछ भी सदन में घटा है, इस सब को माननीय एल. जी. महोदय को जरूर जाकर बताये, यह मेरी प्रार्थना है आपसे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। आदरणीय उस मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया जी, कुछ कहना है।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे कुछ सूचना मिली है कि आज इस सदन में नेता प्रतिपक्ष ने एक बार, इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि इस सदन को मैं भंग करा दूंगा, वो दो बार दिन में इस तरह की भी बात कर चुके हैं। एक बार सत्येंद्र जैन को और एक बार और किसी उस पर कहा था उन्होंने। धमकी दी थी, इनको धमकी दी थी कि आपको मतलब सेक्रेट्री साहब को धमकी दी एक तरह से कि आप बस एक तरह अपनी खैर मनाओ! इनको दी कि अपनी जिंदगी की सुरक्षा करो, आप तो अपनी जिंदगी की चिंता करो और उसके बाद हैरानी की बात यह है कि जब उन्हीं के उठाये मुद्दे पर बातचीत शुरू हुई तो भाग गये। मैं पहले से कह रहा था कि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप खड़े रह पाओ, आपके पैरों की जमीन खिसका देंगे आज हम! खिसक गई और निकल गये। लेकिन बाहर जाकर जो मुझे सूचना मिली है, कितनी सही है कितनी गलत है, मुझे नहीं पता। बाहर जाकर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है 100 नंबर पर कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, हमारे साथी शरद चौहान द्वारा। मुझे लगता है कि अगर यह बात सही है तो यह गंभीर मामला है क्योंकि विधान सभा के अंदर हुए किसी भी एक्शन पर जांच करने का, कार्रवाई करने का सबसे पहला अधिकार, उस शिकायत को सुनने का अधिकार माननीय अध्यक्ष की कुर्सी का है और इस सदन का है। मैं अभी थोड़ी देर पहले यह बात कह रहा था कि इस सदन के अंदर हुई किसी भी कार्यवाही पर सबसे ज्यादा पॉवरफुल संस्थाओं में से एक अदालत को भी बहुत लिमिटेड अधिकार हैं इसके अंदर इंटरवीन करने के। पर अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष बाहर जाकर, हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं अभी शरद जी के बारे में भी नहीं कह रहा है कि उन्होंने क्या कहा, मैं कोई किसी पक्ष की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर उनकी कोई शिकायत

है तो उन्हें आपके संज्ञान में लाना चाहिए, इस सदन के संज्ञान में लाना चाहिए। सदन तय करेगा कि अगर किसी के ऊपर आरोप है तो उसके आरोप की जांच कैसे होगी, कौन सी कमेटी को जायेगी। सदन के समक्ष आना चाहिए, आपकी चेयर के समक्ष आना चाहिए, किसी कमेटी के समक्ष जाना चाहिए। अगर वो 100 नंबर पर गया है तो सीधे-सीधे इस सदन की अवमानना का मामला बनना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इस सदन में और जब मैं यह रख रहा हूं तो इस प्रस्ताव में उन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए कि वो सरकार में बैठे हुए मंत्री को धमकी देते हैं कि आप अपनी जिंदगी की फिक्र करो, वो सचिव को कहते हैकि आप अपनी नौकरी को खैर मनाओ, वो इस सदन को धमकी देते हैं कि इसको तो हम भंग करा देंगे और फिर सदन की अवमाना करते हुये पुलिस में जाकर शिकायत करते हैं कि सदन के अंदर उनकी धमकी दी गई है जान से मारने की। अगर उनको किसी सदस्य ने वाकई जान से मारने की धमकी दी है तो हिम्मत है तो फिर से आयें सदन के सामने। अध्यक्ष महोदय, यह अवमानना का मामला है, मैं चाहूंगा कि इसको सदन की अवमानना समझा जाये और उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाये, इस मामले में।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी जो माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है, जिक्र किया है मुझे भी इसकी जानकारी मिली है कि विधानसभा के गेट पर पुलिस आई है और इस विषय पर मेरा यह कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर हो सकता है अगर कोई कम्प्लेंट करते विजेन्द्र जी। विधानसभा के अंदर की गई कार्यवाही, विधानसभा के अंदर किसी भी सदस्य द्वारा कुछ भी बोले गये शब्द किसी सदस्य के विपरीत उस पर वो अपना लिखित में दे सकते थे, उसकी जांच होती लेकिन किसी भी पुलिस को किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं है कि विधानसभा के अंदर जो भी टिप्पणियां हुई, उन पर कार्रवाई करें। मैं पुलिस को I want police not to take any action against any member in connection with whatever happened in the House. तो इस विषय पर यहां जो भी कार्यवाही हुई है और विजेन्द्र गुप्ता ने उसकी कोई रिपोर्ट बाहर की है जाकर, वो भी सदन की अवमानना है। इसके लिए केवल सदन कार्रवाई करने का संवैधानिक अधिकार रखता है और माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, मैं इस पर संज्ञान लेते हुए इस सारे विषय को सदन की कमेटी को सौंप रहा हूं।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करूं, स्वस्थ संसदीय परंपराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, सभी मंत्रीगण, नेता विपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा विधानसभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और उनके समस्त अधिकारियों और दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सीआरपीएफ बटालियन-55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलेक्ट्रिकल और होर्टीकल्चर डिवजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। विधानसभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों।

(राष्ट्रगान)

अध्यक्ष महोदय : अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई।)